चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | 27 मई–02 जून 2013 | मूल्य 5 रुपये

इंसाफ़ के साथ यह नाइंसाफ़ी क्यों ?

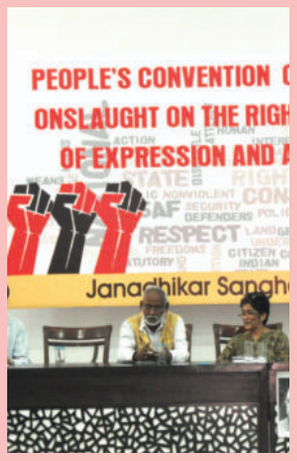

पेज : 3

प्रधानमंत्री की लाचारी से देश शर्मसार

पेज : 4

कब जागरूक होगा हमारा समाज?

पेज : 7

साईं की महिमा

पेज : 12

भारत का दूषित प्रजातंत्र

राजनीतिक दलों का वर्चस्व इतना मज़बूत है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से पार्टी तंत्र में तब्दील हो चुकी है. हालत यह है कि चुनाव अब महज़ खानापूर्ति बनकर रह गए हैं. हर राजनीतिक दल अपनी मूल विचारधारा को त्याग कर येन केन प्रकारेण सत्ता पर क़ाबिज़ होना चाहता है. दरअसल, भारत का प्रजातंत्र दूषित हो चुका है और यही प्रजातंत्र के लिए ख़तरे की घंटी है. क्या है सच्चाई, पेश है विश्लेषण पर आधारित एक रिपोर्ट?

मनीष कुमार

अन्ना हजारे आजकल जनतंत्र यात्रा पर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं. वह देश में घूम-घूमकर राजनीतिक दलों को भ्रष्ट, धूर्त और धोखेबाज़ बता रहे हैं. हैरानी इस बात की है कि किसी भी राजनीतिक दल की अन्ना का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है. दरअसल, भारत का प्रजातंत्र दूषित हो चुका है और चूंकि प्रजातंत्र को ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी राजनीतिक दलों की होती है, ऐसे में अगर राजनीतिक दल जनता से विमुख हो जाए, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपेक्षा हो, भ्रष्ट, बेईमान व गुंडे-बाहुबलियों का सम्मान होने लगे, राजनीतिक दल व नेता विचारधाराविहीन हो जाए और पार्टी किसी विचारधारा और लोगों के समूह की न रहकर किसी परिवार की संपत्ति बन जाए, तो ऐसे दलों के हाथ में प्रजातंत्र की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपना, प्रजातंत्र को ख़त्म करने के बराबर है.

सच तो यह है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों को उन सारी वीभत्स बीमारियों ने ग्रसित कर रखा है, जो प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं. यही भारत के प्रजातंत्र के लिए ख़तरे की घंटी है.

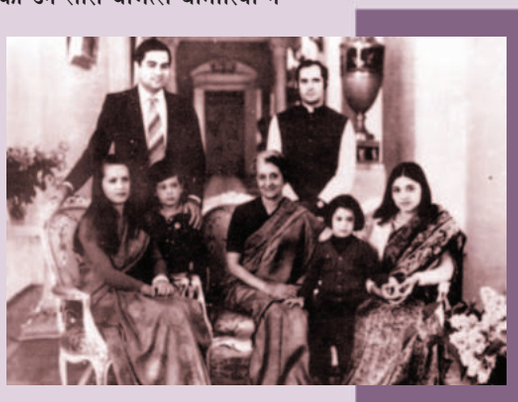

प्रजातंत्र कहां है?

ऐसी व्यवस्था, जिसमें सरकार जनता की हो, जनता द्वारा चलाई जाती हो और जनता के लिए चलाई जाती हो, उसे प्रजातंत्र कहते हैं. वैसे तो प्रजातंत्र के और भी कई मापदंड हैं, लेकिन जब देश का संविधान बन रहा था, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रजातंत्र की उस व्याख्या को माना था. सरकार के इसी स्वरूप को असली आज़ादी माना गया था. प्रजातंत्र के इस स्वरूप के साथ कोई भी समझौता, देश की आज़ादी के साथ समझौता करने के समान है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान में देश का प्रजातंत्र इस मापदंड पर खरा उतरता है या क्या प्रजातंत्र के इस स्वरूप के साथ समझौता हुआ है?

पिछले 67 सालों में भारत के प्रजातंत्र का न केवल पतन हुआ है, बल्कि इस पर ग्रहण भी लग गया है. दरअसल, सरकार के एजेंडे से अब प्रजा ही ग़ायब हो गई है. भारत का प्रजातंत्र अब पार्टीतंत्र में बदल चुका है. देश की सरकारें पार्टी की हैं, पार्टी के द्वारा हैं और पार्टी के लिए हैं. संसद में अब जनमत को तरजीह नहीं दी जाती है. दरअसल, लोगों से जुड़ी समस्याओं पर जब संसद में बातचीत होती है, तब सीटें ख़ाली होती हैं. संसद में कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किस मुद्दे पर बातचीत नहीं होनी है, कौन सांसद क्या बोलेगा और किस मुद्दे को कौन उठाएगा, यह पार्टी तय करती है. और जब कभी वोटिंग होती है, तो सांसदों को अपने मन से वोटिंग करने की भी आज़ादी नहीं है. पार्टी के मुताबिक़, अगर वे वोट न करें, तो सांसद की सदस्यता चली जाती है. कहने का मतलब यह है कि चुने जाने के बाद सांसद और विधायक लोगों के प्रतिनिधि होने की बजाय पार्टी के बंधुआ मज़दूर बन जाते हैं. वे संसद और विधानसभाओं में पार्टी के प्रतिनिधि बन जाते हैं. क्या यही लोकतंत्र का स्वरूप है? क्या लोग अपने प्रतिनिधि को केवल इसलिए चुनते हैं कि वह संसद और विधानसभाओं में उनकी बात न रखकर पार्टी के एजेंट बन जाए?

आंतरिक प्रजातंत्र

न तो यह सही मायने में प्रजातंत्र है और न ही देश के राजनीतिक दलों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास है. प्रजातंत्र सिर्फ़ संस्थागत व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह तो एक मूल्य है, एक पद्धति है, एक जीवनशैली है. जो भी व्यक्ति या संगठन प्रजातांत्रिक मूल्यों से संचालित नहीं होता, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह इन मूल्यों पर विश्वास नहीं करता. देश के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. यह चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, लेकिन असल में, चुनाव आयोग के पास इन पार्टियों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार ही नहीं है. देश के राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आधार पर न तो संगठित हैं और न ही किसी राजनीतिक दल में फ्री ऐंड फेयर सांगठनिक चुनाव होते हैं. पार्टी के अंदर फ़ैसला बहुमत के आधार पर नहीं होता. और अगर इन पार्टियों के अंदर चुनाव होते भी हैं, तो वे दिखावे के होते हैं. हर पार्टी में फ़ैसला लेने वाले वे लोग हैं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है. राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हैसियत बंधुआ मज़दूर की तरह हो गई है. वह पार्टी के लिए काम तो करता है, लेकिन पार्टी के फ़ैसलों में उसकी कोई हिस्सेदारी ही नहीं होती है. आश्चर्य की बात तो यह है कि ज़मीन से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है और वैसे लोग, जिनके पास पैसा और बाहुबल होता है, उन्हें पार्टी में सम्मान दिया जाता है. आज राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है. और दरअसल, इसी वजह से वे लोगों की नज़रों से गिर चुके हैं.

हर राजनीतिक दल परिवारवाद की दलदल में फंसा नज़र आता है और इसीलिए देश की ज़्यादातर पार्टियों का संचालन व नियंत्रण किसी न किसी परिवार के क़ब्ज़े में है. अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मंत्री का बेटा मंत्री, यानी सारी मलाई चंद परिवारों और उनके रिश्तेदारों में ही बट कर रह जाती है. टिकट भी दरअसल, उन्हें ही मिलता है, जो किसी न किसी राजनेता के रिश्तेदार या परिवार से जुड़े होते हैं.

वैचारिक पतन

राजनीतिक पार्टियों का वैचारिक पतन भी अब चरम पर है. कांग्रेस पार्टी ने गांधी और नेहरू के विचारों और समाजवाद का परित्याग कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी अब स्वदेशी, 370 का नाम तक नहीं लेती. वामपंथी पार्टियां अपनी विचारधारा के मूल तत्वों को अब सपना समझने लगी हैं. समाजवादी पार्टियों के एजेंडे से समाजवाद ग़ायब हो चुका है. जेपी आंदोलन से उपजे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यूपीए सरकार इस समय बहुत कठिन दौर से गुज़र रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शायद यही सोचा होगा कि अब चुनाव होने में ज़्यादा वक़्त नहीं है और ऐसे समय में किसी और को कैबिनेट सचिव नियुक्त करना सही नहीं होगा.

दिल्ली का बाबू

अजीत सेठ कैबिनेट सचिव बने रहेंगे

पहले ही इस कॉलम में यह संकेत दिया गया था कि कैबिनेट सचिव अजीत सेठ का कार्यकाल एक साल बढ़ाया जा सकता है. अब यह तय हो गया है, क्योंकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह निर्णय लिया है कि अजीत सेठ का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया जाए. यूपीए सरकार इस समय बहुत कठिन दौर से गुज़र रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शायद यही सोचा होगा कि अब चुनाव होने में ज़्यादा वक़्त नहीं है और ऐसे समय में किसी और को कैबिनेट सचिव नियुक्त करना सही नहीं होगा. शायद इसीलिए उन्होंने अजीत सेठ को एक साल और काम करने का मौक़ा देने का फ़ैसला किया. हालांकि अजीत सेठ पहले कैबिनेट सचिव नहीं हैं, जिनका कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी दो और कैबिनेट सचिवों को ऐसा मौक़ा मिल चुका है. इनसे पहले के कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को दो बार ऐसा मौक़ा मिला था, जिसके कारण सुधा पिल्लई और एम रामचंद्रन को निराश होना पड़ा था, क्योंकि चंद्रशेखर के कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने पर इन्हीं दोनों को कैबिनेट सचिव बनने का मौक़ा मिलता. सूत्रों का कहना है कि अजीत सेठ के मामले में ऐसी प्रतिस्पर्द्धा नहीं थी, क्योंकि इसका अनुमान पहले से लगाया जा चुका था कि सेठ को कम से कम एक साल और इस पद पर बने रहने का मौक़ा मिलेगा. ■

बाबू और कोर्ट

न्यायपालिका कड़ा रुख़ अपना रही है. इससे उत्तर प्रदेश के उन बाबुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिन्होंने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की है. अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा अधिकारी डीएस यादव को कोर्ट के आदेश पर पूरा दिन हिरासत में ही रखा गया. इसी तरह राज्य के प्रधान गृहसचिव आरएम श्रीवास्तव को क़रीब तीन घंटों तक कस्टडी में रखा गया और जब उन्होंने माफ़ी मांगी, तभी छोड़ा गया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच ने 36 शीर्ष बाबुओं के ख़िलाफ़ कोर्ट के आदेश को न मानने और इसकी अवहेलना करने के कारण ग़ैरज़मानती वारंट जारी किया है. उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बाबुओं पर एक साथ वारंट जारी हुआ है. जिन बाबुओं पर वारंट जारी हुआ है, उनमें मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार, लखनऊ के डीआईजी नवनीत सिकेरा, पूर्व डीजीपी अतुल कुमार, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव बीएस भुल्लर का नाम शामिल है. इनके अलावा, राज्य लोक सेवा के अधिकारियों का नाम भी इस सूची में शामिल है. इन बाबुओं को अब कोर्ट में पेश होना होगा. देखना यह है कि इन लोगों को कितने समय तक कस्टडी में रहना पड़ता है!■

महाराष्ट्र पुलिस की परेशानी

दिलीप चेरियन

महाराष्ट्र पुलिस और राज्य के नेताओं के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं. राज्य विधानसभा में कुछ विधायकों द्वारा एक पुलिस अधिकारी को पीटने की घटना के बाद वहां की पुलिस और नेताओं के बीच संबंध और ख़राब होते जा रहे हैं. महाराष्ट्र पुलिस ने इस बात की शिकायत की है कि स्थानांतरण और प्रोन्नति के मामले में नेताओं का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण पुलिस को अपना काम सही तरीक़े से करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पूर्व मुख्य सचिव डीएम सुखथंकर और दो पूर्व पुलिस आयुक्तों जुलिओ रीबेरो तथा एस सॉनी के साथ बैठक में राज्य के गृहमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार अब डीजीपी को दी जाए. हालांकि गृहमंत्री को अभी इसके लिए कैबिनेट से बात करनी होगी तथा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वान को भी राज़ी करना होगा. सूत्रों का कहना है कि इसमें अब औपचारिकता ही बच गई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा. हम तो समय का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है.■

dilipcherian@gmail..com

भारत का दूषित प्रजातंत्र

पृष्ठ एक का शेष

नेता भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय भ्रष्टाचार का नया इतिहास लिख रहे हैं. ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाले कांशीराम के नाम पर राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी आज ब्राह्मणों की रैलियां कर रही है. दरअसल, आज भारत की सभी पार्टियां प्रैगमेटिक पार्टियां बन गई हैं. और इसीलिए इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है. जो विचारधारा है, वह सिर्फ़ जनता को धोखा देने के लिए है. जब इनकी सरकार बनती है, तो इनकी नीतियों और फ़ैसलों में विचारधारा की छाया तक नज़र नहीं आती है. राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीति शास्त्र की किताबों में कांग्रेस पार्टी को सेंट्रिस्ट, बीजेपी को राइटिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों को लेफ्टिस्ट पार्टियां और कई राज्यों की पार्टियों को सोशलिस्ट लिखा जाता है. लेकिन हक़ीक़त यह है कि ये पार्टियां कई वर्षों से विचारधाराविहीन हो चुकी हैं. दरअसल, राजनीतिक दलों ने देश का राजनीतिक वातावरण ऐसा बना दिया है, जिसमें उन्हें लगता है कि विचारधारा के आधार पर चुनाव जीते ही नहीं जा सकते. चुनाव जीतने के लिए तिकड़म करना और जातियों का गठजोड़ करना ज़रूरी है. यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए विचारधारा का परित्याग कर दिया है. विचारधाराविहीन राजनीति किसी भी प्रजातंत्र के लिए दीमक का काम करती है. इसमें कोई शक नहीं है कि देश की राजनीतिक पार्टियां दीमक बनकर देश के प्रजातंत्र को खोखला कर रही हैं.

परिवारवाद का ज़हर

दरअसल, राजनीतिक दल स्वयं खोखले होते जा रहे हैं. हर राजनीतिक दल परिवारवाद की दलदल में फंसा नज़र आता है और इसीलिए देश की ज़्यादातर पार्टियों का संचालन व नियंत्रण किसी न किसी परिवार के क़ब्ज़े में है. अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मंत्री का बेटा मंत्री, यानी सारी मलाई चंद परिवारों और उनके रिश्तेदारों में ही बट कर रह जाती है. टिकट भी दरअसल, उन्हें ही मिलता है, जो किसी न किसी राजनेता के रिश्तेदार या परिवार से जुड़े होते हैं. इस दूषित परंपरा को राजनीतिक दल चुनाव जीतने की कुंजी समझते हैं और यही दलील देकर कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखा दिया जाता है. कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक दलों ने अपने क्रिया-कलापों के कारण कार्यकर्ताओं, समर्थकों, वोटरों और जनता को लोकतंत्र से विमुख कर दिया है. यह लोकतंत्र का स्वरूप नहीं, बल्कि लोकतंत्र को दूषित करने वाली राजनीतिक संस्कृति है. ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? क्या राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्ना हजारे ने भ्रष्ट राजनीतिक दलों के भ्रष्ट आचरण पर हमला बोल दिया है. वैसे, आने वाले दिनों में इस बात पर देश की जनता राजनीतिक दलों की विवेचना ज़रूर करेगी.

राजनीतिक दल और संविधान

यहां यह समझना ज़रूरी है कि चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का संवैधानिक अस्तित्व क्या है? राजनीतिक दलों के अलोकतांत्रिक आचरण की जानकारी के बावजूद चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव में अहम भूमिका दे रखी है. सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या चुनाव आयोग जनतंत्र के मौलिक मूल्यों को दरकिनार करके चुनाव करना चाहता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान में राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है. हमारे संविधान में राजनीतिक दल शब्द का कोई प्रयोग तक नहीं है. देश में चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है. संविधान के मुताबिक़, चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी वोटर लिस्ट तैयार कराना और चुनाव कराना है. लेकिन चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को केंद्रीय भूमिका दे दी. इसका परिणाम यह हुआ कि वास्तविक लोकतंत्र भारत में स्थापित नहीं हो सका. न तो जनता की सरकार है और न ही जनता द्वारा इसे चलाया जा रहा है. जनता चुनाव में मतदान करके पांच साल के लिए गुलाम बन गई. इस ग़लती की वजह से ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं पार्टीसभा में तब्दील हो गईं. पार्टी ही घोषणा पत्र जारी करती है. पार्टी ही उम्मीदवार खड़े करती है. पार्टी ही धनबल का इस्तेमाल करती है और शराब व पैसे बंटवाकर वोट लेती है. चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया से जनता ग़ायब है. न कोई जनता का उम्मीदवार है, न जनता की समस्याओं के लिए लड़ने वाला उनका प्रतिनिधि है. यह लोकतंत्र का कैसा स्वरूप है, जहां जनप्रतिनिधि जनता का नहीं, बल्कि पार्टी का एजेंट बन जाता है. राजनीतिक दलों ने एक और काम किया, जिससे जनप्रतिनिधि एजेंट से पार्टियों के गुलाम बन गए. 52वें संविधान संशोधन के ज़रिए, दलबदल विरोधी क़ानून पास कर लोकसभा और विधानसभाओं को और भी पंगु बना दिया गया. इससे राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तानाशाह बन गईं.

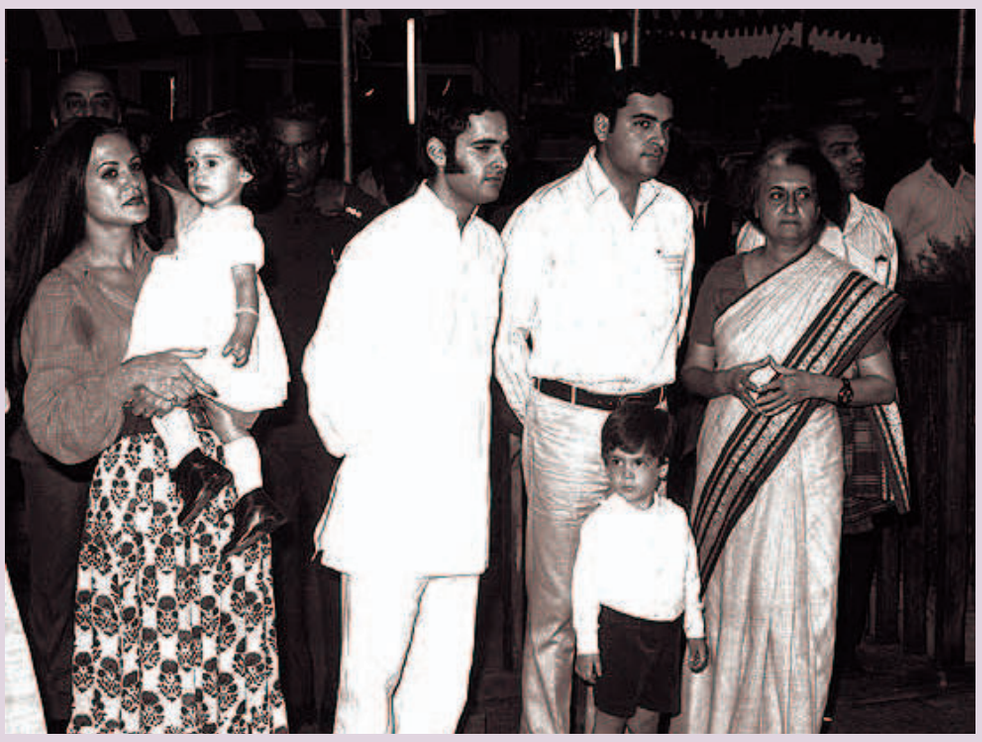

यह आयोग की भूल है या फिर जानबूझ कर किया गया षड्यंत्र, इस पर हमें विचार करना होगा. राजनीतिक दलों की अहम भूमिका की वजह से आज साधारण नागरिक चुनावी प्रक्रिया से दूर चला गया है. हालांकि लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका सिर्फ़ वोट देने तक ही सीमित नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों ने देश में एक ऐसे राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया है, जिसमें आम आदमी चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता. हालत यह है कि राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनाव तक को दूषित कर दिया है. सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आज पहली शर्त यही है कि आप करोड़ों रुपये का जुआ खेलने में सक्षम हैं या नहीं. प्रजातंत्र में चुनाव पर पैसे का महत्व इतना वीभत्स है कि राजनीतिक दल शराब और पैसे देकर चुनाव जीतने को ही सक्षम रणनीति मानते हैं. राजनीतिक दलों का वर्चस्व और राजनीतिक दलों की दूषित मानसिकता की वजह से भारत का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और भ्रष्टाचार का जनक बन चुका है. लोगों की समस्याओं के निदान के लिए सरकार कुछ करेगी, यह उम्मीद भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि सरकार लोगों की हिस्सेदारी से नहीं चल रही है.

इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक दलों ने अपनी तिकड़म से देश के प्रजातंत्र को दूषित कर दिया है. स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महापुरुषों के सपनों का गला घोट दिया गया है. 1947 से पहले देश में जिस तरह शोषण था, वह आज भी है, जनता पर जिस तरह का थोपा हुआ शासन था, वह आज भी है. जिस तरह अंग्रेज भारत की संपदा को लूट रहे थे, उसी तरह आज भी लूटा जा रहा है. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि पहले विदेशी लूट रहे थे और आज राजनीतिक दलों की मदद से देश के ही लोग लूट रहे हैं. दरअसल, आज की सरकार अंग्रेजों की सरकार से ज़्यादा शोषण कर रही है. किसानों की ज़मीन कौड़ियों के भाव छीनी जा रही है, जंगल पर लोगों का हक़ नहीं, नदियों पर जनता का हक़ नहीं, खनिज संपदा की लूट हो रही है और इस लूट का फ़ायदा देशी-विदेशी कंपनियां मिलकर उठा रही हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार इनके लिए बिचौलियों का काम कर रही है. एक के बाद एक शर्मनाक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है. देश में बेरोज़गारी, अशिक्षा, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है. शर्मनाक बात यह है कि इनसे जुड़ी हर योजना भ्रष्टाचार की वजह से फेल हो जाती है और कोई ज़िम्मेदार भी नहीं होता. अजीब बात यह है कि लोककल्याण की योजनाएं सफल नहीं होतीं, बल्कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती हैं. देश का बच्चा-बच्चा यह जानता है कि ये योजनाएं नेताओं, अधिकारियों और पार्टी से जुड़े लोगों के कमाने का ज़रिया बन गई हैं, लेकिन न किसी को सज़ा मिलती है और न ही कोई जवाबदेह होता है. राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के अहम मूल्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही को शून्य कर दिया है. लगता है कि लोकतंत्र की आड़ में देश में पार्टियों की तानाशाही चल रही है. वैसे तो यह काम संसद और विरोधी दलों का है, लेकिन संसद का आलम यह है कि वह सदनों में पारित प्रस्तावों से भी मुकर जाती है. न्यायपालिका का हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोगों की आस्था टिकी हुई है, वरना जिस तरह से देश में न्यायिक व्यवस्था है, उससे तो लोग निराश ही हैं. वह लोकतंत्र बेमानी है, जिस पर जनता का भरोसा नहीं है.

निराश जनता अब आक्रोश में है, इसीलिए सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलनों को जनता का समर्थन मिल रहा है. लोग राजनीतिक दलों के फ़रेब से तंग आ चुके हैं. अन्ना हजारे गांधी और जयप्रकाश नारायण की तरह दलगत राजनीति पर प्रहार कर रहे हैं. यह अपेक्षा करना भी बेमानी है कि राजनीतिक दल सुधरेंगे और देश में सच्चे लोकतंत्र को क़ायम करेंगे. इसलिए देश में सच्चा लोकतंत्र लाने के लिए अब लोगों को ही आगे आना होगा. राजनीतिक दलों की तिकड़मबाज़ी का विरोध करना होगा. अब वक़्त आ गया है कि सच्चे लोकतंत्र और संविधान को लागू करने के लिए देश की जनता को आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना होगा. देश के युवाओं और चरित्रवान लोगों को राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में लेना होगा, वरना आने वाले दिनों में पूरा देश चंद परिवारों के अधीन चला जाएगा.■

manish@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

एसपी सिंह परिहार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय गए

1986 बैच के आईएएस अधिकारी एसपी सिंह परिहार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह रजनी रंजन रश्मी की जगह लेंगे.

राधा कृष्ण माथुर रक्षा मंत्रालय गए

रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव के रूप में काम कर रहे 1977 बैच के आईएएस अधिकारी राधा कृष्ण माथुर को रक्षा मंत्रालय में सचिव बनाया गया है. वह शशिकांत शर्मा की जगह लेंगे.

राजीव राय पीईएसबी गए

1998 बैच के सीएसएस कैडर के अधिकारी राजीव राय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह पीएस बेहुरिया की जगह लेंगे.

राजीव चावला संयुक्त सचिव बने

1987 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव चावला को उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

सत्यब्रत साहु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गए

1991 बैच के आईएएस अधिकारी सत्यब्रत साहु को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह टीएम विजय भास्कर की जगह लेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 12
दिल्ली, 27 मई–02 जून 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
	6452888
	011–23418962
विज्ञापन व प्रसार	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

क़ानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफ़े के बाद कपिल सिब्बल को क़ानून मंत्रालय का प्रभार मिलता है.

जनांदोलनों को कुचलना चाहती है सरकार

इंसाफ़ के साथ यह नाइंसाफ़ी क्यों?

जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा, सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत जनसंगठनों की मदद करने वाले इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ़) का बैंक खाता पिछले महीने 30 अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सील कर दिया. इसके अलावा, एफसीआरए को भी 180 दिनों के लिए रद्द करने का जनविरोधी फ़ैसला लिया गया है. केंद्र सरकार की दलील है कि विदेशों से मिलने वाली अनुदान राशि का उपयोग जनता के हितों के ख़िलाफ़ किया जाता है. ये शब्द कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के हैं, जिसे सरकार ख़ुद बोल रही है. दरअसल, निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल बन चुके राजनेताओं, उद्योगपतियों और नौकरशाहों की तिकड़ी ने शोषित और वंचितों के अधिकारों को बिल्कुल नीलाम कर दिया है. आख़िर क्या है पूरे मामले की सच्चाई, जानने के लिए पढ़िए चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह
arsingh@chauthiduniya.com

लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बरक़रार रखने वाले और वर्षों से इस दिशा में काम कर रहे इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ़) का बैंक अकाउंट पिछले दिनों सरकार ने सील कर दिया. इस संबंध में इंसाफ़ के राष्ट्रीय महासचिव चितरंजन सिंह ने बताया कि नई दिल्ली के कटवरिया सराय स्थित इंसाफ़ कार्यालय को केंद्रीय गृहमंत्रालय के दफ़्तर से एक ख़त मिला. ख़त में सरकार ने कहा है कि इंसाफ़ की गतिविधियां पूर्वाग्रह से ग्रसित और जनता के हितों के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए उसका बैंक खाता तत्काल प्रभाव से फ्रीज किया जाता है.

चितरंजन सिंह के मुताबिक़, भूमंडलीकरण एवं सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ और मानवाधिकार के पक्ष में संघर्ष करने के लिए इंसाफ़ की स्थापना की गई थी. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन ऐक्ट (एफसीआरए) के नियमों में गृह मंत्रालय ने संशोधन कर धरना, जुलूस और प्रदर्शन करने वालों और उनके एफसीआरए रद्द करने की धमकी के विरुद्ध इंसाफ़ ने 5 अगस्त, 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे 16 सितंबर 2011 को ख़ारिज कर दिया गया था. उसके बाद 2 जनवरी, 2012 को इंसाफ़ ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और सरकार से इस संबंध में जवाब भी मांगा. हालांकि सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई जवाब ही दाख़िल नहीं किया है.

इंसाफ़ ने एफसीआरए रद्द किए जाने और बैंक खाता सील किए जाने के ख़िलाफ़ पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसे केंद्र सरकार की साज़िश क़रार दिया, ताकि सरकार देश में जल, जंगल और ज़मीन की लूट मचा रहे कॉरपोरेट घरानों की राह आसान कर सके. इस मौक़े पर प्रो. अचिन विनायक, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी और इंसाफ़ के महासचिव चितरंजन सिंह और अनिल चौधरी समेत कई बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार और रंगकर्मी मौजूद थे. ग़ौरतलब है कि इंसाफ़ देश भर में चल रहे क़रीब 700 ज़मीन से जुड़े आंदोलनों और संघर्षों का एक नेटवर्क है. बाबरी विध्वंस के बाद इंसाफ़ का गठन इसलिए भी किया गया था, ताकि देश में भूमंडलीकरण और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ तथा प्रजातंत्र के पक्ष में जनता को जागरूक किया जा सके.

इस संबंध में इंसाफ़ के महासचिव चितरंजन सिंह ने चौथी दुनिया को बताया कि केंद्र सरकार देश में चल रहे जनांदोलनों से भयभीत है, इसलिए वह जनसंगठनों को कुचलने के लिए नित्य नई साज़िश रच रही है. उनके मुताबिक़, भारत सरकार ने वर्ष 2010 में जो नया एफसीआरए क़ानून बनाया, उसमें नियम-3 सबसे विवादित पक्ष है.

पिछले दिनों 17 मई को नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में जन अधिकार संघर्ष समिति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनसंगठनों की आज़ादी पर राज्य की दमनकारी नीतियों पर एक जनसम्मेलन आयोजित किया. इस सम्मेलन में राकांपा के महासचिव डीपी त्रिपाठी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव देवव्रत विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह, कल्याणी मेनन सेन, वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा, अनिल चौधरी समेत विभिन्न जनसंगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत की.

नए नियम के अनुसार, कोई भी संगठन, जो जनता के हित में बंद, हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको या जेल भरो जैसी कार्रवाइयों को अंजाम देता है, वह एफसीआरए का पात्र नहीं हो सकता. ऐसी किसी भी इकाई को सरकार राजनीति प्रकृति वाला संगठन कहती है, हालांकि यह श्रेणी तय करने का सर्वाधिकार उसने अपने पास सुरक्षित रखा है.

वहीं इस बारे में इंसाफ़ के संस्थापक सदस्य अनिल चौधरी चौथी दुनिया को बताते हैं कि कुडनकुलम से लेकर कश्मीर तक देश भर में चल रहे जल, जंगल, ज़मीन, अस्मिता और अधिकारों के संघर्षों पर इंसाफ़ की अहम भूमिका रही है. ऐसे में केंद्र सरकार ने एफसीआरए रद्द कर यह साबित कर दिया है कि उसकी और कॉरपोरेट घरानों के हितों के ख़िलाफ़ जो काम करेगा, उसका अंजाम यही होगा. वहीं इस मुद्दे पर किसान संघर्ष समिति के नेता डॉ. सुनीलम चौथी दुनिया को बताते हैं कि इंसाफ़ सदैव जनपक्षधर संगठनों के साथ खड़ी रही है. उन्होंने बताया कि मुलताई के किसानों का दर्द हो या फिर अडानी के ख़िलाफ़ जारी संघर्ष, सभी में इंसाफ़ ने पीड़ितों का भरपूर साथ दिया है. सुनीलम के मुताबिक़, अगर बैनर-पोस्टर, पर्चे, किताबें, प्रदर्शन स्थल का ख़र्च उठाना और नागरिक अधिकारों की बात करना गुनाह है, तो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि हमारी सरकार लोकतंत्र को किस अंधेरी सुरंग की ओर ले जा रही है. चौथी दुनिया से बातचीत में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इंसाफ़ के बैंक खाते को सील करने पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लुटेरों की भूमिका में खड़ी नज़र आती है, जो एफडीआई के रास्ते विदेशी धन हासिल कर रही है. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह अपना फ़ैसला वापस नहीं लेती है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. मेधा पाटकर के अनुसार, सरकार ने जनांदोलनों को कुचलने के लिए इंसाफ़ के साथ यह नाइंसाफ़ी की है, जो पूरी तरह संविधान विरोधी है. गृहमंत्रालय ने 30 अपैल को नोटिस भेजकर इंसाफ़ का बैंक खाता सील कर दिया और एफसीआरए को 180 दिनों के लिए रद्द कर दिया.

पिछले दिनों 17 मई को नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में जन अधिकार संघर्ष समिति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनसंगठनों की आज़ादी पर राज्य की दमनकारी नीतियों पर एक जनसम्मेलन आयोजित किया. इस सम्मेलन में राकांपा के महासचिव डीपी त्रिपाठी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव देवव्रत विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह, कल्याणी मेनन सेन, वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा, अनिल चौधरी समेत विभिन्न जनसंगठनों से जुड़े लोगों ने शिरकत की. इंसाफ़ का बैंक खाता सील किए जाने पर राकांपा महासचिव डीपी त्रिपाठी ने अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए सरकार से फ़ौरन इस निर्णय को वापस लेने की मांग की. वहीं देवव्रत विश्वास ने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों के हाथों की कठपुलती बन चुकी है, क्योंकि वे जैसा कहते हैं सरकार वैसा ही करती है. इस जनसम्मेलन में शामिल सभी लोगों ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष करने का संकल्प दोहराया. ■

हच, वोडाफोन और कपिल सिब्बल

क्या यह सिर्फ़ भ्रष्टाचार है?

कपिल सिब्बल चाहते हैं कि वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी को कर माफ़ी दी जाए. यह पैसा इस देश की जनता का है, उसे सरकारी ख़ज़ाने में जाना चाहिए, उसे क्यों वे एक कंपनी द्वारा हड़पने देना चाहते हैं? इसमें उनका क्या हित है?

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

यह सिर्फ़ भ्रष्टाचार नहीं है. यह भ्रष्टाचार से कहीं बड़ी बात है. एक ही दिन में, केंद्र सरकार के दो मंत्री इस्तीफ़ा दे देते हैं. रेल मंत्री पर उसके रिश्तेदार द्वारा रिश्वत लेकर रेलवे के एक अधिकारी को प्रमोशन दिलाने और क़ानून मंत्री पर सीबीआई रिपोर्ट को प्रभावित करने का आरोप है. बावजूद इसके, केंद्र सरकार का एक और मंत्री नए मंत्रालय का प्रभार मिलते ही 24 घंटे के अंदर ऐसा काम करता है, जिसकी उम्मीद लोकतंत्र में नहीं की जाती. मामला कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री कपिल सिब्बल का है. क़ानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफ़े के बाद कपिल सिब्बल को क़ानून मंत्रालय का प्रभार मिलता है. क़ानून मंत्रालय का प्रभार मिलने के 24 घंटे के भीतर ही कपिल सिब्बल एक ऐसा काम करते हैं, जिसे मानने से भारतीय संसद और ख़ुद यूपीए सरकार तक ने मना कर दिया था. दरअसल, क़ानून मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे कपिल सिब्बल पर आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कपिल सिब्बल ने क़ानून मंत्री का कार्यभार संभालते ही वोडा-हचिसन कर मामले में आउट ऑफ कोर्ट (अदालत से बाहर मामले को सुलझाने की कोशिश) समझौता करवाने की कोशिश की. आरोप तो यहां तक लगाया गया कि कपिल सिब्बल और उक्त कंपनी के बीच दो हज़ार करोड़ रुपये का सौदा हुआ है. दरअसल, उक्त कंपनी के ऊपर क़रीब 11 हज़ार करोड़ रुपये का कर बाक़ी है, जिसे उस कंपनी को सरकार के पास जमा कराना है. लेकिन कंपनी यह कर नहीं जमा कराना चाहती है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का दावा है कि उनके पास सिब्बल के ख़िलाफ़ कई सबूत और दस्तावेज़ हैं, जो कपिल सिब्बल के ऊपर सवाल खड़े करते हैं. यह भी आरोप लगा है कि चूंकि सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल उक्त कंपनी के वकील थे, इसलिए भी सिब्बल ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई और इस तरह का काम किया. इस पूरी घटना में पी चिदंबरम और अटर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती पर भी आरोप लगे हैं. आरोपों के मुताबिक़, अश्विनी कुमार के क़ानून मंत्री रहते वाहनवती भी आउट ऑफ कोर्ट समझौते के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जैसे ही क़ानून मंत्रालय का प्रभार कपिल सिब्बल को मिला, उन्होंने अपनी राय बदल दी. उन्होंने सिब्बल से वोडाफोन से समझौते की सिफ़ारिश की और सिब्बल भी मान गए. अब सवाल यह है कि अचानक, रातोंरात यह सब कुछ कैसे बदल गया. ध्यान देने की बात यह है कि इस कर विवाद को लेकर सरकार के साथ वोडाफोन का विवाद काफ़ी पुराना है. सरकार वोडाफोन को इस मामले में माफ़ी देने के पक्ष में नहीं है. वोडाफोन ने हचिसन इंडिया में हॉन्गकॉन्ग की हचिसन वामपोआ की हिस्सेदारी ख़रीदी थी. वोडाफोन इस समझौते के तहत देय कर से मुकर रहा था. मामला अदालत में गया. इस मामले में जनवरी 2012 में उसे सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल हुई. लेकिन सरकार ने कर क़ानून में बदलाव कर दिया. तब वोडाफोन ने समझौते की कोशिश की.

चूंकि, पहले अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी राय दी थी कि इस मामले में समझौता नहीं हो सकता, लेकिन जब कपिल सिब्बल ने क़ानून मंत्री बनते ही फिर से अटॉर्नी जनरल की राय मांगी, तो वे समझौते के लिए सहमत हो गए. सवाल यह है कि जिस मामले में सरकार का रुख़ पहले ही साफ़ हो चुका है कि कर माफ़ी नहीं दी जा सकती, उस मामले में सरकार के ही एक मंत्री का इस तरह का व्यवहार क्या साबित करता है? आख़िर क्यों कपिल सिब्बल चाहते हैं कि वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी को कर माफ़ी दी जाए? इसमें उनका क्या हित है? आख़िर यह पैसा इस देश की जनता का है, उसे सरकारी ख़ज़ाने में जाना चाहिए, उसे क्यों वे एक कंपनी द्वारा हड़पने देना चाहते हैं? जिस देश के करोड़ों ग़रीब लोग अपने हिस्से की कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं, वहां एक कॉरपोरेट हाउस को हज़ारों करोड़ के टैक्स की छूट देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री सिफ़ारिश करता है, तो इसे क्या कहा जाना चाहिए? ■

आख़िर क्यों कपिल सिब्बल चाहते हैं कि वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनी को कर माफ़ी दी जाए? इसमें उनका क्या हित है? आख़िर यह पैसा इस देश की जनता का है, उसे सरकारी ख़ज़ाने में जाना चाहिए, उसे क्यों वे एक कंपनी द्वारा हड़पने देना चाहते हैं?

उत्तराखंड में अन्ना ने कहा

प्रधानमंत्री की लाचारी से देश शर्मसार

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

सजनतंत्र यात्रा के पहले और दूसरे चरण की सफलता के बाद 13 मई से जनतंत्र यात्रा का तीसरा चरण उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू हुआ. प्रदेश में जनतंत्र यात्रा ऋषिकेश से शुरू होकर ब्रम्हखल, श्रीनगर, रुद्र प्रयाग, जोशीमठ, ब्रदीनाथ, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी और रुद्रपुर पहुंची.

प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हज़ारे की अगुआई में चल रही जनतंत्र यात्रा 14 मई को उत्तराखंड के ऋषिकेश से होते हुए बदकोट पहुंची. ऋषिकेश में अन्ना हजारे ने गंगा आरती के बाद अपनी यात्रा शुरू की. यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ अब लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनेताओं ने आज़ादी के बाद जनकल्याणकारी नीतियों को लागू करने की बजाय अपना हितसाध्य किया है. उन्होंने कहा कि राजनेताओं को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है. अन्ना हजारे ने ऋषिकेश की जनता से आह्वान किया कि वे सितंबर माह के प्रथम महीने में दिल्ली ज़रूर आएं और जनसंसद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. आज़ादी के साढ़े छह दशक बीत जाने के बाद भी देश की आम जनता तमाम तरह की परेशानियों से त्रस्त है, लेकिन सियासी पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं है.

इस मौक़े पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने कहा कि यह देश भ्रष्ट राजनेताओं के दुष्चक्र में फंस चुका है. ऐसे में अन्ना हजारे जैसे गांधीवादी समाजसेवी की ओर जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजनीतिक दलों ने न केवल जनता के साथ धोखा किया है, बल्कि उन्होंने संविधान को भी ठेस पहुंचाई है. जनलोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा और वामपंथी पार्टियों ने अंदरूनी एकजुटता दिखाते हुए इस विधेयक को पास नहीं होने दिया. इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि मौजूदा राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन उनका यह तिकड़म अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी से जनता परेशान है और उसे नेताओं से नफ़रत होने लगी है. हालत यह है कि कई क्षेत्रों के सांसद और विधायक आक्रोशित जनता से बचते फिर रहे हैं. उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि जब सांसदों और विधायकों के वेतन वृद्धि का सवाल आता है, तो सभी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, लेकिन बात जब जनता की आती है, तो यही राजनेता चुप्पी साध लेते हैं.

जनतंत्र यात्रा 15 मई को उत्तराखंड के ब्रम्हखल और डूंडी के रास्ते उत्तरकाशी पहुंची. ब्रम्हखल और डूंडी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनकी यह यात्रा व्यवस्था परिवर्तन के लिए हो रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने जितना इस देश को नहीं लूटा, उससे कहीं ज़्यादा हमारे नेताओं ने देश की दुर्गति कर डाली. उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में देश का हर तबक़ा निराश और परेशान है. कहीं किसान आर्थिक परेशानियों की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं, तो कहीं पढ़े-लिखे नौजवान बग़ैर नौकरी के अवसाद में जी रहे हैं. नौकरीपेशा से लेकर हर वर्ग इस व्यवस्था में त्राहि-त्राहि कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में संविधान में कहीं भी पक्ष और पार्टी बनाने की बात दर्ज नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद इस देश में हज़ारों की संख्या में पार्टियां खड़ी हो गईं, लेकिन जनता की समस्याएं ख़त्म नहीं हुईं. अन्ना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह तनिक भी गंभीर नहीं है. यही वजह है कि जनलोकपाल क़ानून पारित करने के वचन से वह पीछे हट गई, क्योंकि सरकार को यह महसूस हो गया कि अगर यह क़ानून पास हो जाता है, तो उसकी गिरफ्त में नेता और अफ़सर ही आएंगे. अन्ना ने हुंकार भरते हुए कहा कि उन्हें देश के नौजवानों से ख़ास उम्मीदें हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी देश पर संकट आया है, तब युवाओं ने ही महत्व-पूर्ण भागीदारी निभाई है.

संतोष भारतीय ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार घोटाले करने में नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रही है. सरकार की कारगुज़ारियों से देश की जनता परेशान है. अन्ना हजारे को नौजवानों के रूप में सिपाहियों की ज़रूरत है, जो कम से कम देश के लिए एक साल का समय दे सकें. उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, यह कोई नहीं जानता. जनता क्या चाहती है, इससे नेताओं को कोई मतलब नहीं है. यही वजह है कि लोग अब सरकार के विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं. उल्लेखनीय है कि अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा 31 मार्च से अमृतसर के जलियांवाला बाग़ से शुरू हुई थी. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होते हुए उनकी यह यात्रा इन दिनों उत्तराखंड में है. जनतंत्र यात्रा 16 मई को उत्तराखंड के चम्बा, नई टिहरी होते हुए श्रीनगर पहुंची.

चंबा और नई टिहरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनकी इस यात्रा का मक़सद देश में भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से लोगों को निजात दिलाना है. मौजूदा केंद्र और राज्य सरकारें जनआकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही हैं, चाहे किसान हो या मज़दूर, नौकरीपेशा हो या गृहणी सभी परेशान हैं. राजनेताओं का मक़सद जनकल्याण करना नहीं, बल्कि किसी तरह सत्ता हासिल करना है. अन्ना ने मनमोहन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लाचारी से देश शर्मसार है. इस मौक़े पर अन्ना ने युवाओं का आह्वान किया कि वे व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में निर्णायक भूमिका अदा करें. उन्होंने लोगों से अपील की कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में वे बड़ी संख्या में दिल्ली आएं, क्योंकि जनविरोधी केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जनसंसद का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं से बड़ी जनसंसद होती है, लेकिन भ्रष्ट राजनेता जनता की ताक़त को भूल चुके हैं. ■

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

न्याय और आर्थिक सहायता के लिए दर-दर भटक रहे शैलेष पासवान को उस समय एक बड़ा सहारा मिला, जब स्थानीय पत्रकार एवं समाजसेवी निखिल आनंद ने उनके कंधे पर हमदर्दी का हाथ रखा और हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया.

उत्तर प्रदेश

न्यायपालिका के कठघरे में नौकरशाही

क्या अब अधिकारी सुधरेंगे?

अदालत के सख्त रुख़ ने उत्तर प्रदेश के उन नौकरशाहों के होश उड़ा दिए हैं, जो अपने कर्तव्यों की न केवल अनदेखी, बल्कि अदालती आदेशों के अनुपालन में भी हीलाहवाली कर रहे थे. सूबे की जनता को अदालत के ताजा तेवरों ने राहत ज़रूर प्रदान की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिकारी वाकई सुधर जाएंगे या उनका पुराना रवैया बरक़रार रहेगा?

अजय कुमार

अदालत के रुख़ से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में हड़कंप मचा हुआ है. न्यायपालिका और उसके आदेशों को हल्के में लेने और बार-बार अवमानना करने वाले अधिकारियों को अदालत ने जब उनकी हैसियत (सजा) बताई, तो उनके पास माफी मांगकर जान बचाने के अलावा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा. प्रदेश की नौकरशाही के रवैये से अदालत की नाराज़गी की गाज इतनी गहरी थी कि सूबे के सबसे बड़े अधिकारी (मुख्य सचिव जावेद उस्मानी) तक नहीं बच पाए. अन्य अधिकारियों में भी अनेक सचिव स्तर के नौकरशाह थे. किसी को अवमानना का नोटिस थमाया गया, तो किसी को अवमानना में हिरासत में ले लिया गया. कई आला अफसरों के ख़िलाफ़ ग़ैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए गए. जिन अधिकारियों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए, उन्हें कस्टडी में अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. अदालत के आदेशों की लगातार अवहेलना करने वाले नौकरशाहों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें यह दिन भी देखना पड़ सकता है. निश्चित ही इसके लिए जितनी ज़िम्मेदार प्रदेश की नौकरशाही है, ठीक उतनी ही गुनहगार सूबे पर क़ाबिज़ रहने वाली सरकारें हैं.

मात्र दस-पंद्रह दिनों में नौकरशाहों के ख़िलाफ़ अदालतों ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए. हमेशा लापरवाह अधिकारियों को डांट-फटकार कर शांत हो जाने वाली अदालतों के सख्त तेवरों ने उन नौकरशाहों के कान भी खड़े कर दिए हैं, जिन पर आज भले ही अदालत की गाज न गिरी हो, लेकिन तलवार उन पर भी लटक रही है. बीते दिनों उच्च न्यायालय के आदेशों को मानने में देरी करने अथवा हीलाहवाली का परिचय देने वाले आला अधिकारियों को जिस तरह उच्च न्यायालय की अलग-अलग पीठों ने दिन भर हिरासत में रखा, वह केवल उन अधिकारियों की ही नहीं, बल्कि सरकार की भी फ़ज़ीहत का मामला नज़र आता है. लखनऊ में उच्च न्यायालय की अलग-अलग पीठों ने प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव स्टांप एवं निबंधन, अपर आयुक्त प्रशासन, फ़ैज़ाबाद के साथ-साथ कई अधिकारियों को हिरासत में लिया, वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय को कोर्ट में हाजिर होकर यह बताने के लिए कहा कि राज्य सरकार की तरफ़ से कोर्ट कार्यवाही में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है. ये दोनों मामले एक दिन ही सामने आए. अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि 8 मई को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अतुल कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन बी एस भुल्लर, डीआईजी रेंज नवनीत सिकेरा, आईजी कारागार एवं जिलाधिकारी लखनऊ अनुराग गुप्ता सहित कई अन्य अधिकारियों के ख़िलाफ़ ग़ैर-जमानती वारंट जारी कर दिए. वारंट जारी करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के विद्वान न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए यहां तक कहा कि अधिकारी अदालत के आदेश समय सीमा में नहीं मानते और जब अवमानना का मामला बनता है, तो वे अदालत में हाजिर नहीं होते हैं.

उच्च न्यायालय ने सख्ती शुरू की, तो यह सिलसिला 9 मई को भी जारी रहा. इस दिन उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा ने समेकित बाल विकास योजना से संबंधित नियमावली अदालत के आदेश के बाद भी निश्चित समय सीमा के भीतर न बन पाने के कारण मुख्य सचिव जावेद उस्मानी के ख़िलाफ़ अवमानना नोटिस जारी कर दिया. इसी दिन उच्च न्यायालय लखनऊ की एक अन्य पीठ ने विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के ख़िलाफ़ ग़ैर- जमानती वारंट जारी कर दिए. प्रमुख सचिवों में रवींद्र सिंह एवं अवनीश कुमार अवस्थी भी शामिल थे. पीठ ने इसके अलावा, निदेशक पंचायतीराज सौरभ बाबू, सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार, यूपी को-ऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक सुभाष चंद्र शर्मा, नॉर्थ मेंटनेंस टेलीफोन के महाप्रबंधक ए के टंडन, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ यू के सिंह एवं बीएसए लखीमपुर को भी अवमानना के मामले में तलब कर लिया. पीठ ने दो टूक कहा कि सरकारी अधिकारी इस बात का बहाना नहीं बना सकते कि वे संबंधित विभाग में थोड़े समय ही तैनात रहे.

बहरहाल, अदालत के सख्त रवैये के बाद सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य में ऐसे अधिकारी आम जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता एवं सक्रियता दिखाएंगे. उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए यह अच्छा संकेत है कि नौकरशाहों की टालमटोल से नाराज़ उच्च न्यायालय ने कई अफसरों को कड़ी फटकार लगा दी. उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत की सख्ती से आम जनता का भी थोड़ा-बहुत भला देखने में आएगा, क्योंकि उसके पास तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वह शिकायत न सुनने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कुछ कर सके. आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपने जनप्रतिनिधियों के पास ही ऐसे सुस्त एवं लापरवाह अधिकारियों के रवैये का रोना रोती है, लेकिन कभी-कभी विधायक, मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी नौकरशाही के अड़ियल रवैये से त्रस्त हो जाते हैं. कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पाया. नौकरशाहों की हठधर्मी से तंग आकर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता कल्याण सिंह ने यहां तक कह दिया था कि नौकरशाही बेलगाम घोड़े की तरह होती है, जिसकी रानों में ताकत होती है, वही इसे काबू में रखने की महारथ हासिल कर सकता है. नौकरशाही को कंट्रोल में रखने में कल्याण सिंह को महारथ हासिल थी. पहली बार जब वह मुख्यमंत्री बने, तो नौकरशाहों को उन्होंने अपने हिसाब से नचाया, लेकिन बाद में उनकी भी पकड़ ढीली होती चली गई. बसपा प्रमुख मायावती भी जब सत्तारूढ़ होती हैं, तो नौकरशाही को अपने हिसाब से चलाती हैं, उनके सामने तो नौकरशाह कांपते हैं. मायावती नौकरशाहों को सार्वजनिक मंचों, बैठकों एवं अन्य सरकारी आयोजनों के समय उनकी नाकामी के लिए डांटती-फटकारती रहती थीं.

खैर, उच्च न्यायालय को जिस तरह अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ रहा है, उससे राज्य के नौकरशाहों के लापरवाही भरे रवैये की पुष्टि होती है. इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि जिन मामलों के चलते उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उसकी खंडपीठ लखनऊ के विद्वान न्यायाधीशों ने अधिकारियों को फटकार लगाई, उनमें से ज़्यादातर न्यायिक विषय ही नहीं थे. ये मामले अदालतों के समक्ष इसलिए पहुंचे थे, क्योंकि अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने की बजाय हीलाहवाली कर रहे थे अथवा इस बात से बेपरवाह थे कि उनके विभागों से संबंधित कुछ मामले अदालतों में विचाराधीन हैं. कुछ मामलों में एकल पीठ के निर्णय के ख़िलाफ़ नौकरशाह बड़ी पीठ के पास जा रहे हैं, जैसा कि प्रमुख सचिव गृह आर एम श्रीवास्तव के साथ हुआ. दोहरी पीठ ने श्रीवास्तव को तकनीकी आधार पर अवमानना के मामले से राहत दे दी. अदालत की सख्ती का रंग नौकरशाहों पर खूब दिख रहा है. यही वजह थी कि सूबे के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी 9 मई को सभी बैठकें रद्द करके इलाहाबाद पहुंच गए और वहां उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

सुशासन पर एसिड के फफोले

चंचल की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं?

पिछले लगभग सात महीने से अपना झुलसा हुआ चेहरा लिए न्याय की आस में पिता के साथ इधर-उधर भटक रही चंचल की ओर सरकार का ध्यान आज तक नहीं गया. हैरानी की बात तो यह है कि एक ग़रीब दिहाड़ी मज़दूर की इस बेटी की मदद के लिए कोई भी सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल आगे नहीं आया. ऐसे में, सवाल यह उठता है कि क्या इसी को सुशासन कहते हैं?

शशि सागर feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2012 का अक्टूबर महीना. नवरात्र चल रहे थे. पूरा सूबा भक्तिमय था, लेकिन सप्तमी की रात 19 वर्षीय चंचल के लिए काली रात बनकर आई. इलाके के चार दबंग युवकों ने उसे सोते समय एसिड से नहला दिया. उस रात को याद करके चंचल आज भी सहम जाती है. वह आपबीती सुनाती है कि एकबारगी तो ऐसा लगा कि मानो किसी ने मुझे आग की भट्ठी में झोंक दिया है. 21 अक्टूबर की उस रात चंचल अपनी 16 वर्षीय बहन सोनम एवं माता-पिता के साथ अगले दिन होने वाले कन्या पूजन और विजयदशमी की तैयारियों पर चर्चा करते-करते कब नींद के आगोश में समां गई, पता ही नहीं चला. तब किसी को सपने में भी भान नहीं था कि आने वाला समय उन सबके लिए एक बड़ी मुसीबत साथ ला रहा है.

दरअसल, उस दिन हुआ यह कि मध्य रात्रि क़रीब 12 बजे इलाके के चार युवक अनिल, राज, घनश्याम एवं बादल दबे पांव छत पर चढ़ आते हैं और अगले ही पल रजाई हटाकर चंचल पर एसिड से भरी बोतल उड़ेल देते हैं. बुरी तरह झुलसी चंचल की चीख-पुकार सुनकर माता-पिता के साथ बहन भी जाग उठती है. पहले तो उन्हें लगता है कि हमलावरों ने चंचल पर गर्म तेल डाल दिया है, लेकिन माजरा समझते उन्हें बिल्कुल देर नहीं लगती. बहन को संभालने के क्रम में सोनम का हाथ भी झुलस जाता है. पिता शैलेष पासवान एवं माता सुनैना देवी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आख़िर अब किया क्या जाए. अगले पल वे आस-पड़ोस में जाकर मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन अफसोस! कोई भी शख्स उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता. ऐसे में, निराश माता-पिता चंचल एवं सोनम को लेकर पीएमसीएच पहुंचते हैं, जहां उनका इलाज शुरू होता है.

बेटी अस्पताल में और पिता प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर, इस उम्मीद में कि मामले की रिपोर्ट दर्ज हो और बेटी के इलाज की समुचित व्यवस्था हो जाए, लेकिन यहां भी ढाक के वही तीन पात वाली कहावत चरितार्थ होती है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि पीड़िता से 164 के बयान आज तक नहीं लिए. हालत यह है कि हमलावरों के घरवाले आज भी शैलेष पासवान को धमकाते हैं कि मुकदमा वापस ले लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा. विडंबना देखिए, एक लड़की का जीवन पलक झपकते ही बर्बाद हो गया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. न तो कोई आर्थिक मदद और न ही हमदर्दी के दो बोल कहने की फुर्सत किसी मंत्री, सांसद या विधायक को मिली. और तो और, राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले को लेकर आश्चर्यजनक बेरुखी का प्रदर्शन किया. घटना के पांच माह बाद आयोग की प्रतिनिधि बीते 10 अप्रैल को चंचल और उसके परिवार से मिलने पहुंचीं, वह भी रस्म अदायगी के लिए और फिर उसके बाद से आज तक उन्होंने चंचल की कोई ख़बर ही नहीं ली कि उसे कोई सहायता मिली या नहीं और अगर इलाज हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है, तो क्यों?

न्याय और आर्थिक सहायता के लिए दर-दर भटक रहे शैलेष पासवान को उस समय एक बड़ा सहारा मिला, जब स्थानीय पत्रकार एवं समाजसेवी निखिल आनंद ने उनके कंधे पर हमदर्दी का हाथ रखा और हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया. निखिल ने फेसबुक पर हेल्प एसिड अटैक विक्टिम नामक एक पेज बनाया और लोगों से मदद की अपील की. इसी पेज के माध्यम से जानकारी पाकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा चंचल के परिवार से मिले. कुशवाहा के प्रयास से निखिल ने रांची के देवकमल अस्पताल में चंचल के इलाज के लिए वहां के निदेशक एवं जाने-माने प्लास्टिक सर्जन डॉ. अनंत सिन्हा से मुलाकात की. चंचल को देखने और जांच के बाद डॉ. सिन्हा ने जून से उसका इलाज करने की बात कही. उन्होंने कहा कि वह अपनी फीस एवं अस्पताल के विभिन्न चार्ज नहीं लेंगे, बावजूद इसके चंचल के इलाज में लगभग 15 लाख रुपये का ख़र्च आ सकता है. डॉ. सिन्हा के अनुसार, चंचल को 11-12 सर्जरी से गुजरना होगा. उपेंद्र कुशवाहा एवं डॉ. सिन्हा ने शैलेष पासवान को आश्वस्त किया है कि पैसों की कमी चंचल के इलाज में आड़े नहीं आएगी.

जब मैंने चंचल से बातचीत की, तो उसकी जीवटता एवं हौसला देखकर आश्चर्यचकित रह गया. वह ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि अपनी पीड़ा, अपना दर्द वह ख़ुद सबको बताए. साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि वह कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी. अपने चेहरे को उसने दुपट्टे से ढंक रखा था. बोलने से होने वाली तकलीफ और जलन से वह रह-रहकर कराह उठती थी. जब मैंने उसका चेहरा देखना चाहा, तो उसने कहा, भैया, नहीं देख पाएंगे आप. मेरे हाथ में उसकी पुरानी तस्वीर थी, लेकिन जब मैंने उसका मौजूदा चेहरा देखा, तो सन्न रह गया. उसकी आंखें गल चुकी हैं और होंठों का पता ही नहीं चलता. सच तो यह है कि जिसने भी उसे पहले कभी देखा होगा, वह उसे अब पहचान ही नहीं पाएगा.

चंचल भरपेट भोजन नहीं कर पाती, नींद भी उसे बहुत कम आती है. चंचल के पिता शैलेष कहते हैं कि शासन-प्रशासन की बात तो दूर, हमारा दर्द जानने के लिए मुखिया-सरपंच तक नहीं आए. मां सुनैना कहती हैं कि अगर समाज चाहे, तो हमारी बेटी के साथ न्याय हो सकता है और वह ठीक हो सकती है. शैलेष बताते हैं कि हमलावरों के ख़िलाफ़ वह पहले भी पुलिस में शिकायत कर चुके थे, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया. अगर लिया गया होता, तो आज चंचल की यह हालत न होती. इलाकाई लोग बताते हैं कि उक्त युवकों का चाल-चलन कभी भी ठीक नहीं रहा और वे दबंग परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. इससे पहले शेरपुर में हुई छेड़छाड़ की एक घटना में भी उनका नाम आ चुका है. पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि राज्य सरकार को चंचल की मदद के लिए आगे आना चाहिए.

ग़ौरतलब है कि चंचल पटना जिले के मनेर प्रखंड के छितनावा गांव की रहने वाली है. उसके इलाज में आने वाले भारी ख़र्च को लेकर सभी परेशान तो हैं, पर उनके हौसले बुलंद हैं. चौथी दुनिया की तरफ़ से हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वे चंचल की मदद के लिए आगे आएं, ताकि उसका इलाज सही ढंग से हो सके.■

दक्षिण अमेरिका में भी नरबलि का लंबा इतिहास रहा है. शासकों की मौत और त्योहारों पर इंका लोग सेवकों की बलि दिया करते थे, ताकि वे मृतक के अगले जीवन में उसका साथ दे सकें.

21वीं सदी में भी अंधविश्वास!

कब जागरूक होगा हमारा समाज?

इक्कीसवीं सदी में आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है कि वह दुनिया के विकसित देशों से मुक़ाबला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो अंधविश्वास में बुरी तरह जकड़े हुए हैं. नरबलि भी इसी अंधविश्वास का प्रतीक है और इससे यह पता चलता है कि आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, क्योंकि कुछ लोग देवी-देवता को ख़ुश करने के लिए किसी मासूम की बलि चढ़ाने में भी नहीं हिचकते हैं, बिना यह सोचे कि उस मासूम के घरवालों पर क्या बीतेगी! ऐसे में सवाल यह उठता है कि आख़िर कब जागरूक होगा हमारा समाज?

फ़िरदौस ख़ान
firdaus.journalist@gmail.com

पिछले दिनों झारखंड के धनबाद में बलि के लिए दो बच्चियों के अपहरण का मामला सामने आया. आरोप है कि आरपीएफ हवलदार मुनीलाल ने बलि के लिए दो सगी बहनों का अपहरण किया. वह बच्चियों के हाथ-पैर बांधकर काली की पूजा कर रहा था. कमरे में तंत्र-मंत्र की ध्वनि गूंज रही थी और बच्चियां ख़ौफ़ से कांप रही थीं. वह बच्चियों की बलि दे पाता, इससे पहले ही बच्चियों को तलाश करते हुए उनके परिवारीजन मौक़े पर पहुंच गए. बलि में नाकाम रहने पर गुस्साए हवलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बच्चियों के दादा राजनाथ यादव और पिता उमेश यादव घायल हो गए, लेकिन परिवारीजनों ने हवलदार को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. हवलदार के घर से 11 नरकंकाल बरामद हुए हैं, जिनमें खोपड़ियों और हाथ की हड्डियों की भरमार थी. बच्चियों का कहना है कि हवलदार ने उनके हाथ-पैर बांधे, उन्हें बिस्कुट खिलाए और फूल माला पहनाई. ग़ौरतलब है कि तक़रीबन 35 साल पहले बिहार के सीवान ज़िले के निवासी मुनीलाल के एक बेटे और एक बेटी की मौत हो गई थी. इससे वह बहुत परेशान रहने लगा था. उसी दौरान एक तांत्रिक से उसकी मुलाक़ात हुई. तांत्रिक ने उसे बताया कि उस पर भूत-प्रेत की छाया है. तांत्रिक के कहने पर उसने तंत्र विद्या सीखने का फ़ैसला किया और कोलकाता चला गया. वहां उसे आरपीएफ में नौकरी मिल गई. मुनीलाल का कहना है कि वह काली का भक्त है और पिछले 30 सालों से काली की पूजा कर रहा है. दो साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई. वह तीन बेटियों और दो बेटों के साथ रहता है. उसके बच्चों का कहना है कि वे बचपन से ही अपने पिता को काली की साधना करते हुए देख रहे हैं.

दरअसल, नरबलि का इतिहास बहुत पुराना है. दुनिया की विभिन्न पौराणिक संस्कृतियों में नरबलि का प्रचलन रहा है, लेकिन वक़्त के साथ यह कुप्रथा ख़त्म होती चली गई. धार्मिक अनुष्ठानों में नरबलि की जगह पशुओं की बलि दी जाने लगी. आज नरबलि एक बड़ा अपराध है, जिसकी चहुंओर निंदा की जाती है, लेकिन दुःख की बात तो यह है कि आज भी नरबलि के मामले सामने आ रहे हैं. आज के आधुनिक युग में जहां इंसान अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग प्राचीन काल की बर्बरता से अभी तक बाहर नहीं

निकल पाए हैं. नरबलि के मामले यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज भी अंधविश्वास में डूबे लोग कितनी बर्बरता से किसी की जान ले लेते हैं. हैरानी की बात तो यह भी है कि जिन लोगों पर जनता की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होती है, वे भी ऐसे अमानवीय कार्य कर बैठते हैं कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है.

इसमें कोई दो राय नहीं कि धनबाद में तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाई गई बच्चियां ख़ुशनसीब थीं, लेकिन कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं, जिनकी बेरहमी से बलि चढ़ा दी जाती है और उनके घरवाले रोते-बिलखते रह जाते हैं. बीती 25 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के निरमंड में चार साल के मासूम की बलि दे दी गई. सुमित नामक यह बच्चा तीन दिनों से ग़ायब था और बाद में उसका शव एक बोरी में मिला. जब बोरी खोली गई, तो बच्चे के माथे पर काला तिलक, मुंह और बाज़ू काले किए हुए थे. ये सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बच्चे की बलि दी गई है. बीते 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के गांव हिनौता में काली मंदिर के पास एक खेत में अज्ञात मासूम बच्चे का कटा हुआ सिर मिला. ग्रामीणों को पास के एक तालाब के किनारे ख़ून के छींटों के निशान और ज़मीन पर बलि के वक़्त लिखे जाने वाले मंत्र दिखे. ग्रामीणों का मानना है कि नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किसी ने मासूम की बलि चढ़ाने के बाद उसका कटा सिर खेत में दबा दिया होगा. इससे पहले बीते 20 मार्च को राजधानी दिल्ली के भलस्वा इलाक़े में एक बच्चे की सिरकटी लाश मिली. पुलिस को शक है कि बच्चे की हत्या बलि के लिए की गई है. पिछले साल 20 फ़रवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के गांव बरपाली के सोमनाथ राठिया के दस साल के बेटे प्रवीण राठिया की सिरकटी लाश पूंजीपथरा के छर्राटांगर के जंगल में मिली. वह 15 दिनों से ग़ायब था. परिवारीजनों ने गांव के ही एक तांत्रिक पर बच्चे की बलि चढ़ाने का आरोप लगाया था, जो जांच में सही निकला. पुलिस ने भी लाश मिलने के दो दिनों बाद बच्चे की बलि देने की पुष्टि कर दी. पूछताछ में तांत्रिक ने नरबलि देने की बात स्वीकार कर ली. उसके घर से एक तलवार, दो त्रिशूल और एक सब्बल बरामद किया गया. तांत्रिक ने बच्चे की बलि देने में इनका इस्तेमाल किया था.

देश का सर्वोच्च न्यायालय नरबलि के मामले में बेहद सख़्त है. अदालत ने उन लोगों के लिए सज़ा-ए-मौत और सख़्त सज़ा के आदेश जारी किए हैं, जो मानव बलि देते हुए पकड़े जाएंगे या फिर इसमें किसी भी प्रकार से लिप्त होंगे. नरबलि के कई मामलों में दोषियों को सख़्त सज़ाएं भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद नरबलि के मामले सामने आ ही जाते हैं. बीते 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के 11 साल के बच्चे प्रवीण राठिया की बलि देने के आरोप में ज़िला अदालत ने दिलीप राठिया नामक व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई. द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ए के साहू ने फ़ैसला सुनाते हुए इसे दुर्लभतम से दुर्लभ मामला माना. दिलीप पर धारा 201 के तहत 7 साल की सज़ा और 15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है, जबकि धारा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाई गई है. मामले के मुताबिक़, दिलीप ने 22 फ़रवरी, 2012 को गांव बड़गांव में प्रवीण का गला काटकर बलि चढ़ा दी थी. फिर उसके सिर को अपने आंगन स्थित पूजा कक्ष में गाड़ दिया था. संदिग्ध गतिविधियों के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के घर से बलि में इस्तेमाल की गई तलवार और त्रिशूल को बरामद किया था. चूंकि हादसे के पखवाड़े बाद बच्चे की खोपड़ी मिली थी, लिहाज़ा बच्चे की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया था. इसी तरह पिछले साल मार्च में झारखंड के कोडरमा ज़िले की एक निचली अदालत ने भी गांव पूरनाडीह के छह साल के बच्चे अमन की बलि के मामले में सभी नौ अभियुक्तों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया. ग़ौरतलब है कि 20 मार्च, 2010 को गांव पूरनाडीह के छह साल के अमन के ग़ायब होने के मामले में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था. बाद में 24 मार्च, 2010 को बच्चे का शव बरामद किया गया. दरअसल, गांव के देवी मंडप में बच्चे की बलि दी गई थी. अभियुक्तों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 20 मार्च को बच्चे की बलि दी थी.

क़ाबिले-ग़ौर है कि प्राचीनकाल में दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में नरबलि का प्रचलन था. लोगों का मानना था कि बलि देने से उनका देवता उनसे ख़ुश होगा और उनकी मनोकामना पूरी होगी. महाभारत में भी नरबलि का ज़िक्र आता है. इसके मुताबिक़, राक्षसी हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के साथ वन में रहती थी. वह काली की भक्त थी और उसे हर रोज़ पूजा के दौरान एक मानव की बलि देनी होती थी. एक दिन हिडिंब मानव बलि के लिए भीम को पकड़ लाया, लेकिन हिडिंबा भीम को देखकर उस पर मोहित हो गई. इसलिए उसने भीम को बचाने की कोशिश की, लेकिन हिडिंब ने भीम को ललकारा और युद्ध में उसकी मौत हो गई. बाद में हिडिंबा ने भीम से गंधर्व विवाह कर लिया. उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया. प्राचीन भारत में भी नरबलि से जुड़े कई क़िस्से हैं. कर्नाटक के कुकनूर क़स्बे में स्थित एक प्राचीन काली मंदिर में नरबलि दी जाती थी.

चीन की लोककथाओं में भी नरबलि की बातें कही गई हैं. एक पौराणिक लोककथा के मुताबिक़, चीन की महान दीवार के नीचे हज़ारों लोगों को ज़िंदा दफ़न कर दिया गया था. चीन में झोउ राजवंशों के दौरान प्राचीन चीनी नदी के देवताओं को नरबलि दी जाती थी. कहा जाता है कि दुष्ट प्रवृत्ति के पुरोहित धन के लालच में नदी के देवताओं को बलि दिया करते थे. क्विन राजवंश ने 384 ईसा पूर्व इस कुप्रभा को ख़त्म कर दिया, लेकिन मिंग राजवंश के सम्राट होंग्वु ने 1395 में इसे फिर से शुरू कर दिया. जब उसके बेटे की मौत हुई, तो उसके साथ उसकी क़रीबी दो महिलाओं को भी राजकुमार के साथ ज़िंदा दफ़न कर दिया गया. 1464 में सम्राट ज़्हेंगटोंग ने मिंग शासकों और राजकुमारों के लिए इसे वर्जित घोषित कर दिया. किंग राजवंश के दौरान 1673 में सम्राट कांगज़ी ने इस पर रोक लगा दी. मिस्र में भी राजा की मौत के बाद उसके सेवकों को शव के साथ ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था. तर्क था कि क़ब्र में राजा को सेवकों की ज़रूरत पड़ेगी. जापान के मानव स्तंभ हीतोबशीरा के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसके निर्माण के वक़्त कुंवारी कन्या को इसके नीचे दफ़न किया गया था, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से इसकी रक्षा की जा सके. नरबलि के मामले में एज़्टेक लोग काफ़ी बदनाम रहे हैं. वे अपने देवता को नरबलि देते थे, ताकि उसे रक्त लगातार मिलता रहे. उनका मानना था कि उनके देवता हर रोज़ सूरज के साथ युद्ध में लीन रहते हैं. यह दुनिया हर 52 साल चक्र में ख़त्म हो सकती है और नरबलि इसे रोक सकती है. इसीलिए 1487 में मैक्सिको टेनोक्टिटलान के महान पिरामिड को पवित्र करने के लिए हज़ारों क़ैदियों की बलि दे दी गई.

रोमन में भी राजा की मौत के साथ उनके सेवकों को शव के साथ ज़िंदा आग के हवाले कर दिया जाता था. यहां 97 ईसा पूर्व में नरबलि की प्रथा ख़त्म कर दी गई. देवताओं को ख़ुश करने के लिए नरबलि की बजाय पशुओं की बलि दी जाने लगी, मगर जर्मनी में नरबलि आम नहीं थी. जब कभी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जान-माल पर बन आती थी, तभी यहां नरबलि दी जाती थी. ग्यारहवीं सदी में यहां कई मंदिरों में नरबलि दी जाती थी.

दक्षिण अमेरिका में भी नरबलि का लंबा इतिहास रहा है. शासकों की मौत और त्योहारों पर इंका लोग सेवकों की बलि दिया करते थे, ताकि वे मृतक के अगले जीवन में उसका साथ दे सकें. पेरू के इंका लोगों ने 1527 में इंका हुयना कापक की मौत होने पर तक़रीबन चार हज़ार अनुचरों, दरबार के अधिकारियों, मनपसंद व्यक्तियों और दासियों की बलि दी थी. इंका क्षेत्रों में बलि चढ़ाए गए बच्चों की बहुत-सी ममियां मिली हैं. दरअसल, यह एक प्राचीन प्रथा थी, जिसे कापाकोचा कहते थे. इसी तरह उत्तरी पेरू के मोक़े लोग भी एक साथ बहुत से किशोरों की बलि देते थे. एक पुरातत्ववेत्ता स्टीव बौरगेट ने 1995 में 42 किशोरवय लड़कों की हड्डियां पाई थीं. ये लोग युद्ध बंदियों का पहले जुलूस निकालते थे, बाद में उनकी बलि देकर उनका रक्त अपने देवताओं को चढ़ाते थे. इसी तरह उत्तरी अमेरिका के पॉनी लोग वार्षिक उषाकाल नक्षत्र प्रथा का अभ्यास करते वक़्त एक युवा कन्या की बलि देते थे. दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी संप्रदाय या माउंड बिल्डर्स द्वारा भी नरबलि दी जाती थी. पश्चिमी अफ्रीका में उन्नीसवीं सदी के आख़िर तक नरबलि दी जाती थी. राजा और रानी की मौत पर नरबलि आम थी. दहोमे में जब किसी शासक की मौत होती थी, तो हज़ारों गुलामों की बलि चढ़ा दी जाती थी. 1727 में तक़रीबन चार हज़ार लोगों की बलि दिए जाने की जानकारी मिलती है. इसके अलावा, एक अन्य सालाना समारोह में पांच सौ गुलामों की बलि दी गई. मगर जैसे-जैसे इस्लाम धर्म फैलता गया, बलि पर भी रोक लगती रही. मुसलमानों के अलावा ब्रिटिश लोगों ने भी नरबलि का विरोध करते हुए इसके ख़ात्मे के लिए आवाज़ उठाई. नरबलि का अंतिम प्रमुख केंद्र आधुनिक नाइजीरिया स्थित बेनिन साम्राज्य था. बेनिन साम्राज्य 1890 में ब्रिटिश शासन के साथ नरबलि पर रोक लगाने के लिए सहमत हुआ. हालांकि इसके बाद भी वहां नरबलि जारी रही. नरबलि को रोकने की कोशिश में जब एक ब्रिटिश निरीक्षक की हत्या कर दी गई, तो ब्रिटिश शासन ने बेनिन पर क़ब्ज़ा करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर

दी. नतीजतन, अपनी रक्षा के लिए बेनिन का शासक ज़्यादा से ज़्यादा नरबलि देकर देवता को ख़ुश करने में जुट गया. मगर जब ब्रिटेन ने जीत हासिल कर ली, तो वहां नरबलि कम हो गई. तिब्बत के कुछ इलाक़ों में भी नरबलि का ज़िक्र किया जाता है.

यह हैरानी की ही बात है कि इक्कीसवीं सदी में आज जब भारत विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है कि वह दुनिया के विकसित देशों से मुक़ाबला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो अंधविश्वास में बुरी तरह जकड़े हुए हैं. दरअसल, जब तक समाज में रूढ़िवादिता रहेगी, तब तक अंधविश्वास रहेगा. और जब तक अंधविश्वास क़ायम है, तब तक नरबलि जैसी अमानवीय प्रथा का पूरी तरह ख़ात्मा नहीं किया जा सकता. इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए और लोगों को यह समझाया जाए कि कोई भी देवी या देवता किसी की बलि लेकर ख़ुश नहीं होता, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है. ■

कुमार ने सर्वोच्च अदालत से झूठ बोला. सर्वोच्च अदालत का यह काम नहीं है कि वह सरकार को यह बताए कि किस मंत्री को हटाना है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही काफी थी.

परिसंघीय ढांचे का विचार पहले से अधिक मज़बूत हो गया है. भारत अपने आपको बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की तरह प्रदर्शित कर रहा है, जो कांट्रैक्ट के आधार पर एक-दूसरे के साथ हैं

www.kamalmorarka.com

संविधान और गणतंत्र की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है

जिस तरह से इन दो मंत्रियों ने अपनी शक्ति, पद और सत्ता का दुरुपयोग किया है, वह निंदनीय है. हमें किसी भी हालत में संविधान और गणतंत्र की रक्षा करना है, क्योंकि यह हमारा फ़र्ज़ है. एक विचारोत्तजक टिप्पणी...

कमल मोरारका

पिछला हफ्ता दो मंत्रियों और उनके इस्तीफ़े की मांग को लेकर ख़बरों से भरा हुआ था. अंत में, इन मंत्रियों ने मई 10 को इस्तीफ़ा दे ही दिया, लेकिन सही ढंग से इस मुद्दे को समझने में सांसद और प्रेस, दोनों ही असफल रहे. दरअसल, इस मुद्दे की गंभीरता को वे नहीं समझ सके. यह एक त्रासदी से कम नहीं है. श्री बंसल के मामले, किसी को पदोन्नत करने के लिए कुछ रिश्वत लेने के मामले को साबित होना बाकी है या खुद बंसल को उसके बारे में पता हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था. यह सब जांच का विषय है. इसकी अभी सीबीआई द्वारा जांच की जानी है, लेकिन क़ानून मंत्री के मामले में तो यह साफ़ था कि उन्होंने अपनी शक्ति, पद और सत्ता का दुरुपयोग किया है और वह भी ज़बरदस्त तरीक़े से बेशर्मी और अभिमान के साथ. इस्तीफ़े के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ग़लत नहीं किया. मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया.

अब सवाल यह उठता है कि अगर उन्होंने कुछ ग़लत नहीं किया है, तो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस मसले पर अपनी राय बतानी चाहिए कि क्या उनकी राय में किसी क़ानून मंत्री को अदालत में पेश किए जाने वाले किसी जांच रिपोर्ट को देखने या उसमें बदलाव करने का अधिकार है.

वैसे, यह क़ानूनी सवाल भी है. अगर प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अश्विनी कुमार ने ग़लत नहीं किया है, तो तय मानिए कि वे गहरी मुसीबत में हैं, क्योंकि यहां खुलेआम संविधान का उल्लंघन हुआ है. कल किसी राज्य का होम मिनिस्टर पुलिस आयुक्त या एक थानेदार को कॉल करता है और हत्या की जांच रिपोर्ट को दिखाने के लिए और उसमें परिवर्तन के लिए कहता है या वित्त मंत्री कर विभाग में कॉल करके किसी व्यक्ति के कर असेसमेंट में बदलाव या उसे दिखाने को कहता है, तो क्या यह सही होगा? ज़ाहिर है, यह हमारे संविधान की योजना नहीं है. हमारा संविधान मंत्रालयों को सीबीआई या आयकर विभाग या पुलिस विभाग पर केवल प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है. उन्हें व्यक्तिगत मूल्यांकन या जांच में दख़ल देने की कोई शक्ति नहीं मिली है. यही संविधान की योजना है.

और अगर इस सरकार के प्रधानमंत्री या क़ानून मंत्री जांच रिपोर्ट में बदलाव के लिए कहते हैं, तो ज़ाहिर है कि

> क़ानून मंत्री के मामले में तो यह साफ था कि उन्होंने अपनी शक्ति, पद और सत्ता का दुरुपयोग किया है और वह भी ज़बरदस्त तरीके से, बेशर्मी और अभिमान के साथ. इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया.

हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र गहरी मुसीबत में है. श्री अश्विनी कुमार जो मुद्दा उठा रहे हैं, वह पवन कुमार बंसल के मुद्दा से ज्यादा गंभीर मसला है. कुमार ने सर्वोच्च अदालत से झूठ बोला. सर्वोच्च अदालत का यह काम नहीं है कि वह सरकार को यह बताए कि किस मंत्री को हटाना है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही काफी थी. फिर सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही थी. सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है. प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है. मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि वे क्या कहते हैं. क्या सोचते हैं. प्रधानमंत्री ने कुमार के उस बयान का एक तरह से समर्थन ही किया कि उन्होंने कुछ ग़लत नहीं किया है. भाजपा ने भी परिपक्व विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि वे मामले की गंभीरता समझ नहीं पाए. उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि दोनों मंत्री इस्तीफ़ा दे. कुमार ने जो किया, वह अवैध, असंवैधानिक था. इस्तीफ़ा देने का नहीं, बल्कि उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की जानी चाहिए थी. यह रिश्वतखोरी का सवाल नहीं है. दरअसल, रिश्वतखोरी की तुलना में यह ज्यादा गंभीर मसला है.

आज की स्थिति आपातकाल की तरह है. लेकिन मुझे यकीन है कि आपातकाल में भी किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा. बेशक उस समय एक स्वतंत्र प्रेस नहीं था, इसलिए बहुत सी बातें सामने नहीं आई होंगी. लेकिन फिर भी ऐसा बेशर्म काम नहीं हुआ होगा, जैसा आज हुआ है. वक्त आ गया है कि श्री मनमोहन सिंह सारी स्थिति को खुद के हाथ में ले और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें. आम चुनाव नज़दीक है. फिर से यूपीए-3 की सरकार बनाने के लिए लाबिंग शुरू हो गई है. अगर सचमुच यूपीए-3 इस सिद्धांत के साथ सत्ता में आ जाती है कि उसका कोई मंत्री किसी जांच या मूल्यांकन में हस्तक्षेप कर सकता है, तो हमें 1950 में अपनाई गई इस संविधान को अलविदा कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. गणतंत्र क्या है? जनता की संपत्ति, यही गणतंत्र है.

कांग्रेस अध्यक्ष को क्रेडिट देना चाहिए कि वह इस बात को ले कर डट गई कि गलत छवि के साथ कांग्रेस चुनाव में नहीं जा सकती और इसलिए उन दो मंत्रियों को मजबूरन मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा. लेकिन अब जो भी सत्ता में आए, वह गणतंत्र को उसके मूल व उचित स्वरूप में बहाल करने के लिए काम करे. हर पांच साल बाद लोग मतदान करेंगे और सरकार आती-जाती रहेगी. लेकिन संविधान और इस गणतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

गोरे अंग्रेज गए, काले आ गए?

ठाकुरदास बंग

feedback@chauthiduniya.com

किसानों का शोषण शुरू हुआ. साहूकारों के हाथ में बड़े-बड़े खेतों के चक आए. उधर कई किसान भूमिहीन हो जाने और किसान-मज़दूरों के ग्रामीण धंधे टूट जाने से इन साहूकारों या इंग्लैंड की राजस्व-नीति से पैदा हुए (नवनिर्मित) ज़मींदारों के खेतों में काम करने लगे. बचे हुए किसान-मज़दूर भारत के मुंबई जैसे नए औद्योगिक नगरों, असम के चाय-बगानों और सुदूर मॉरिशस या दक्षिण अफ्रीका के देशों में कुली बनकर जाने लगे. दरअसल, इस तरह सस्ता अनाज, सस्ता कच्चा माल और सस्ते मज़दूर की उपलब्धि इस नई औद्योगिक नीति के कारण सुलभ हो पाई.

दरअसल, यूरोप के अन्य देशों ने भी इसी शोषणकारी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया. इतना ही नहीं, 1917 में क्रांति हो जाने पर रूस के सामने भी औद्योगीकरण के लिए पूंजी निर्माण का प्रश्न उठा. वहां के कम्युनिस्ट शासकों को भी किसानों पर ज़बरदस्ती करनी पड़ी और इसीलिए हज़ारों किसानों को मार डाला गया, लाखों को ज़बरदस्ती साइबेरिया के कॉन्सट्रेशन कैंप में भेजकर, उनके खेत छीनकर ज़बरदस्ती सहकारी बड़े-बड़े फार्म बनाए गए. इसके बाद अनाज की क़ीमतें भी घटाई गईं और कच्चा माल सस्ते में मिले, इसकी व्यवस्था की गई. कारखानों के लिए लगने वाली पूंजी का निर्माण कृषकों के शोषण से किया गया. अमेरिका के पास ढाई गुना ज़मीन है और जनसंख्या आधी से भी कम है, लेकिन उसे भी आधुनिक उद्योग में लगने वाली पूंजी, सस्ता कच्चा माल पाने और पक्का माल बेचने के लिए अंततः विशाल मंडियों की ज़रूरत महसूस हुई. अतः अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका के देशों पर अपना आर्थिक साम्राज्य लादा. प्रख्यात समाजवादी रोजा लक्सेम्बुर्ग ने 20वीं सदी के प्रारंभ में यह भविष्यवाणी की थी कि जिस देश के पास गुलाम देश या उपनिवेश नहीं रहेंगे, वह देश अपने ही राष्ट्र के अंदर गांव के रूप में उपनिवेश पैदा करेगा, यानी अपने देश के अंदर गांवों के रूप में नव-उपनिवेश पैदा किए जाएंगे. अंततः वैसा ही हुआ.

दुनिया में आज ऐसा कोई देश नहीं है, जिसने औद्योगीकरण से निर्मित पूंजी के प्रश्न का, अपने देश के ग्रामीणों के शोषण या विदेशों के शोषण से भिन्न, दूसरा किसी प्रकार का हल निकाला हो. मार्क्स के ख्याल में भी औद्योगिक मज़दूरों के शोषण का प्रश्न आया था. यूरोप में ग्राहकों के शोषण का प्रश्न भी अन्यों के ख्याल में आया. इस पर समाजवाद एवं सहकारिता का हल निकाला गया, लेकिन ग्रामीणों या किसान-मज़दूरों के शोषण का सवाल उनके ख्याल में नहीं आया. अतः शोषण-मुक्त औद्योगीकरण की रीति क्या हो और पूंजी निर्माण के प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं, इसका उत्तर पूंजीवादी, समाजवादी, सहकारी या कल्याणकारी शासन-पद्धति में से किसी के पास नहीं है.

> गांवों के शोषण की दो सौ साल पुरानी नीति जारी रहे. गोरे अंग्रेज गए, लेकिन काले अंग्रेजों ने वही किया, जो गोरे अंग्रेज करते थे. 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी और उसमें विचार रखा गया कि देश के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि कृषि वस्तु मूल्य नीचे के स्तर पर स्थिर रखे जाने चाहिए, यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के शोषण की जो बात कही थी और जिस शोषण को मिटाने के लिए हम स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे, वह शोषण फिर से जारी रहा.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने महात्मा एवं राष्ट्रपिता बनाए जाने के अनेक वर्षों पूर्व इस शोषण को देखा और समझा था. साथ ही इस औद्योगीकरण से पैदा होने वाली बेरोज़गारी, विषमता एवं इससे निर्माण होने वाली भोगवादी संस्कृति यूरोप, अफ्रीका और भारत में अनुभव भी की थी. इसलिए उन्होंने इसका हल गांवों के कृषि औद्योगिक समाज के रूप में बताया. उत्पादन के औज़ारों में सुधार अवश्य हो, लेकिन उससे बेरोज़गारी न फैले और औज़ार को भारी- भरकम पूंजी न लगे. इस तरह से सुधार किया जाए, जिससे कि औज़ार उत्पादक के हाथ में ही रहे. उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच मधुर संबंध हों. जहां कच्चा माल पैदा होता हो, वहीं गांवों में उद्योग चलें आदि, औद्योगीकरण की दिशाएं उन्होंने बताईं. ऊपर की मर्यादाओं के अंदर चरखे में संशोधन सुझाने वाले को उन्होंने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया. किसान को अपना पेट काटकर, यानी भूखे रहकर बाज़ार में अनाज, दूध, घी, सब्जी एवं फल पैसों के लिए बेचने पड़े और उन पैसों से वह सरकार के भारी-भरकम कर और टाटा-बिड़ला का विलास चलाता रहे, इस पद्धति का उन्होंने जोरदार विरोध किया. गांधी की औद्योगीकरण की पद्धति का बाद में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुमाखर ने मध्यम या उचित तंत्र विद्या, यह नामकरण किया. इस पद्धति में बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं है. इसलिए किसान का माल सस्ता ख़रीदने और उसे पक्का माल महंगा बेचने की बाध्यता नहीं है. पैसा गांवों में ही रहेगा और इसका उपयोग नए उद्योगों या औजार सुधार में लगने वाली पूंजी में ही करके गांवों में उद्योग चलेंगे.

1947 में भारत आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन भारत के नेताओं ने गांधी जी के इस शोषण-मुक्त औद्योगीकरण के विचार पर ख्याल ही नहीं किया. हमारे नेता पश्चिम के विचारों में पले हुए थे. चूंकि उनके हृदय में गांधी और दिमाग में अंग्रेज था, इसलिए नव-स्वतंत्र भारत जल्द से जल्द पश्चिम की नकल पर अपने देश में बड़े-बड़े यंत्रों द्वारा नगरों में सब चीजें कैसे बनाए, इस पर चिंतन शुरू हुआ. इसके लिए लगने वाली विशाल पूंजी कहां से आए? देश के पश्चिमी विचारों से अनुप्राणित अर्थशास्त्रियों ने शासन को सलाह दी कि किसान का माल सस्ता खरीदा जाए. गांवों के शोषण की दो सौ साल पुरानी नीति जारी रहे. गोरे अंग्रेज गए, लेकिन काले अंग्रेजों ने वही किया, जो गोरे अंग्रेज करते थे. 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी और उसमें विचार रखा गया कि देश के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि कृषि वस्तु मूल्य नीचे के स्तर पर स्थिर रखे जाने चाहिए, यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के शोषण की जो बात कही थी और जिस शोषण को मिटाने के लिए हम स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे, वह शोषण फिर से जारी रहा. अंग्रेजों के इस शोषण के विरुद्ध गांधी जी ने जो आंदोलन किया, उसका प्रतीक चरखा ज़रूर बन गया था, लेकिन वह सब बात आज़ादी के बाद पुरानी हो गई. विकास यानी नगरों में बड़े-बड़े कल-कारखाने, यह समीकरण बन गया. ■

पाठकों की दुनिया

भाजपा की तुच्छ राजनीति

राजनीति जो न कराए कम ही है. भारतीय जनता पार्टी भी अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने साल 2002 के नरोडा पाटिया हत्याकांड में पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के लिए फांसी की सज़ा मांगे जाने की बात कही थी. उस वक़्त हिंदुत्ववादी संगठनों ने मोदी का काफ़ी विरोध भी किया था. लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और वहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, तो मोदी भी अपनी बात से साफ़ मुकर गए. अब एसआईटी दंगे के दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग नहीं करेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने फांसी की मांग की जो इजाजत दी थी, उस पर रोक लगा दी गई है. ग़ौरतलब है कि बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को जब अदालत ने दोषी क़रार दिया, तो एसआईटी ने गुजरात सरकार से दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग करने की इजाजत मांगी और सरकार ने इसकी इजाज़त दे भी दी. लेकिन अब मोदी ने यू-टर्न लेते हुए एसआईटी को दी इजाज़त पर रोक लगा दी है. हालांकि मोदी सरकार अब यह दलील दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़, किसी भी केस में सरकार को अपील में जाने के लिए एडवोकेट जनरल से सलाह-मशविरा करना ज़रूरी रहता है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. क़ाबिले-ग़ौर है कि गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद में स्थित नरोडा पाटिया इलाक़े में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी. ये नरसंहार 28 फ़रवरी 2002 को हुआ था. इस दंगे में 33 लोग घायल भी हुए थे.

-सईद, दिल्ली

शहीदों को भूला देश

चौथी दुनिया में प्रकाशित फ़िरदौस ख़ान की पुस्तक समीक्षा- हे अमर बलिदानी तुझे शत-शत प्रणाम पढ़ी. पुस्तक की समीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि काफ़ी बड़ी सामग्री से पाठक को कम शब्दों में ही परिचय करवा देना अपने आप में चुनौती है. यह कार्य इस पुस्तक की समीक्षक ने बख़ूबी किया है. समीक्षक ने देश की वर्तमान दशा की ओर संकेत करते हुए बलिदानियों की देश के प्रति बलिदान की मनोदशा का बड़ा सुंदर श्रद्धापूर्वक वर्णन किया है कि अमर बलिदानी पंडित चन्द्रशेखर आज़ाद के मन में देश के प्रति किस तरह बलिदान की भावनाएं हिलोरे लेती थीं. देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी प्रवाह नहीं की. देश के लिए अपने जीवन में जो भी अधिक से अधिक हो सका, उन्होंने किया और आख़िर में अपना जीवन ही देश के लिए बलिदान करके चले गए. लेकिन क्या देश उनके बलिदान को सार्थक कर पाया है? बेशक, नहीं कर पाया है. आज शहीदों की चिताओं पर मेले, तो क्या दीपक भी नहीं जलते हैं. उन बलिदानियों के परिवारों को रोटी के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. कितना गिर गया है हमारा समाज और हमारी व्यवस्था, जहां अपने बलिदानियों को भी सम्मान नहीं दिया जाता है. समीक्षक ने केवल इस पुस्तक की समीक्षा ही नहीं, बल्कि देश की दुर्दशा और बलिदानियों के प्रति घटते सम्मान के प्रति अपने हृदय की वेदना को भी मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है. निश्चित ही समीक्षा की अंतिम पंक्तियां बड़ी मार्मिक हैं, अपितु बलिदानियों के प्रति उनकी श्रद्धा भी निवेदित कर रही हैं. पुस्तक के लेखक को तो साधुवाद है ही, साथ ही मैं समीक्षक को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने समीक्षा के बहाने ही देश की युवा पीढ़ी को देश प्रेम का संदेश दिया है.

-डॉ. वेद व्यथित, फ़रीदाबाद, हरियाणा

सियासी दल करें पहल

देश से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए अन्ना हजारे से लेकर कई समाजसेवी अपनी तरफ़ से हरसंभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार पूरी तरह तो दूर, कण भर भी समाप्त नहीं हो सका है. देश के नेता न केवल भ्रष्टाचार की गंगा में ख़ुद नहा रहे हैं, बल्कि साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी डुबकियां लगवा रहे हैं. ऐसे हालात में देश से भ्रष्टाचार को दूर करने की बातें मात्र काग़ज़ी ही साबित होती हैं. दरअसल, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक देश से भ्रष्टाचार को बाहर करना सपने देखने के बराबर है. सरकार को सबसे पहले अपना दामन साफ़ करने के लिए दाग़ी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर देश की जनता को यह संदेश देना होगा कि देश से इस समस्या को मिटाने के लिए सियासी दल मात्र बातें ही नहीं करते, बल्कि उस पर अमल भी करते हैं.

-शिबली रामपुरी, सहारनपुर, उत्तर

विद्वता का बखान

चौथी दुनिया में प्रकाशित निमर्लेंदु का आलेख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-तब और अब पढ़ी. लेखक ने संघ के बारे में अपनी विद्वता का बखान किया है. अपने देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि मैकाले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें रंगे लोगों को भारतीयता, हिंदुत्व, संस्कृति, सभ्यता और स्वदेश से संबंधित बातें अटपटी लगती हैं. इसलिए निष्पक्ष आकलन का ईमानदार प्रयास होता ही नहीं, उल्टे विद्वता का स्वांग रचकर दिन के उजाले में भी अंधकार का ही आभास करते हैं. नेहरू परिवार और नेहरूवादियों के लिए देश में संघ से संबंधित चीज़ें दुश्मनी से भरी हैं, जितना पाकिस्तानी भी नहीं मानता.

-काली मोहन सिंह, भोजपुर, बिहार

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ बग़ावत करनी होगी

कर्नाटक के चुनाव ने फिर एक सत्य को स्थापित किया कि हिंदुस्तान की जनता प्रचार के भुलावे में नहीं आने वाली या नहीं आती है. दरअसल, सारे देश में नरेंद्र मोदी को लेकर मीडिया ने ऐसा समा बांधा कि सभी देखते ही रह गए. ज़ाहिर है, इसके पीछे बड़े पैसे की भूमिका रही होगी या फिर बड़ी पब्लिक रिलेशन कंपनियों के संपर्कों का जादू रहा होगा, जिसने सारे देश में न केवल नरेंद्र मोदी को एकमात्र विकल्प के रूप में खड़ा किया, बल्कि उनका क़द इतना बढ़ा दिया कि वह क़द पार्टी से अधिक बढ़ने लगा. लेकिन कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी भी छोटे हुए और भारतीय जनता पार्टी भी छोटी हुई. सवाल यह नहीं है कि वहां कांग्रेस क्यों जीती और कैसे जीती या वहां के लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अच्छा माना और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बुरा माना. हां, सवाल यह ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी के प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बुरी स्थिति में कैसे पहुंच गई. इसका मतलब नरेंद्र मोदी की अपील सारे देश में नहीं है. उन्हें सारा देश प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, यह भी सत्य नहीं है.

और कई सवाल हैं. क्या कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार का सवाल कपूर की तरह विलीन हो गया है. क्या कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अच्छा माना या कांग्रेस का कैंपेन करने वाले राहुल गांधी की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस को इतने वोट मिले. वैसे तो सारे सवालों का जवाब न केवल कर्नाटक के लोग, बल्कि सारे देश के लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ये नेता हमारी दलीय व्यवस्था में साठगांठ कर लोगों को वोट देने के लिए बंधुआ बना दिया है. उनके पास विकल्पों की कमी हो सकती है और उनके पास संभावनाओं की भी कमी हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह कमी नहीं है. दरअसल, इस नक़ली कमी को ही वास्तविकता बनाकर इन राजनीतिक दलों ने जनता को भ्रमित करने की सफलतापूर्वक कोशिश की, जिसका उदाहरण चुनाव है. याद रहे, इससे पहले कर्नाटक में भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस हारी थी. कर्नाटक में जनता दल (एस) भ्रष्टाचार की वजह से हारा और अब भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार की वजह से ही हारी. लेकिन फिर भी लोगों ने कांग्रेस को वोट इसलिए दिया, क्योंकि उनको लगा कि उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, जिसे जनता का विकल्प माना जा सके, क्योंकि यह लोकतंत्र पार्टियों के द्वारा ही चल सकता है या शासित हो सकता है. सच तो यह है कि कांग्रेस को इसी सोच का फ़ायदा मिला और इसी वजह से कर्नाटक की जनता ने हाल में किए गए भ्रष्टाचार के उदाहरणों को एक तरफ़ कर दिया और पहले किए गए भ्रष्टाचार के उदाहरण को उन्होंने वोट देकर अपना लिया.

इसका मतलब यही हुआ कि अगर जनता के पास विकल्प हो, तो जनता इन दलीय आधार पर लड़ने वाली पार्टियों के ख़िलाफ़ वोट दे सकती है. हक़ीक़त में विकल्प मौजूद हैं और वे हैं ग़ैर राजनीतिक पार्टियां, लेकिन राजनीतिक दलों ने आपस में मिलकर जनता को ही अवैध क़रार दे दिया है. कर्नाटक में अगर वहां के लोगों को यह पता होता कि वे किसी पार्टी के मुक़ाबले अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं और ये संपूर्ण पार्टी सिस्टम संविधान की व्याख्या और संविधान की भावना के ख़िलाफ़ है, तो वे ज़रूर एक दूसरा फ़ैसला लेते.

हालांकि अब दूसरा फ़ैसला लेने का वक़्त आ गया है, लेकिन हम बात यहां नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी के आगे कुछ राज्य हैं, जहां वह चुनाव प्रचार करने जाएंगे. वहां राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे. कहीं पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो कहीं पर कांग्रेस जीतेगी. और मैं फिर कह रहा हूं कि इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि देश नरेंद्र मोदी को सुनने आता है या उनकी जगह राहुल गांधी की बात पर ज़्यादा भरोसा करना चाहता है. याद रहे, दो ही लोगों के ऊपर यह मुल्क भरोसा नहीं कर रहा है.

दरअसल, संविधान में लिखी बातों का डिटेल जिस दिन जनता को पता चल गया, उसी दिन से राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो जाएगी. संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है. संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं के दिमाग़ में यह साफ़ था कि हम जनतंत्र ला रहे हैं या हम लोकतंत्र ला रहे हैं और देश को गणराज्य बना रहे हैं, तो संसद में लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिए न कि पार्टियों के प्रतिनिधि होने चाहिए. और लोगों एवं जनता के प्रतिनिधि को एक जगह इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी के स्तंभ की पैदाइश कर दी. यहां यह भी बता दें कि भारतीय लोकतंत्र में पार्टी सिस्टम संवैधानिक दृष्टि से अवैध है. पर हैरानी की बात तो यह है कि यह अवैध काम 1952 से हिंदुस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान की जनता को 1952 से अवैध रूप से राजनीतिक दलों को चुनना पड़ रहा है. राजनीतिक दल अवैध ढंग से इस देश की जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं.

मैंने दुनिया के गणराज्य का अध्ययन किया. दुनिया का पहला गणतंत्र या लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य था. उस गणतंत्र में लोगों के प्रतिनिधि तो थे, लेकिन पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं थे. दरअसल, लोकतंत्र में लोग और पार्टी एक दृष्टि से सामने खड़े हो जाते हैं. आज हिंदुस्तान में पार्टियों का शासन है और पार्टियां जनता के हित के किसी भी सवाल को अपना मुद्दा नहीं बना रही हैं. उनका मुद्दा एक ही है कि वे किस तरह से सत्ता में आएं, लोगों को भरमाएं, वह जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या फिर उन्हें शराब बांटकर या पैसा देकर अपने वश में किया जाए और उनका वोट हासिल किया जाए. पार्टी ने इस क्रम में जाति को भी खड़ा किया, वोटों के सवालों को भी खड़ा किया और अभी थोड़े दिनों पहले तक बूथ कैप्चर करने वाले सिस्टम को भी पोषित किया था. ये सारे तरीक़े लोकतंत्र से विपरीत थे और जनता को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि इनके ख़िलाफ़ भी खड़ा हुआ जा सकता है या इनको भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है.

इलेक्शन कमीशन ने बूथ कैप्चरिंग को आंशिक रूप से रोक दिया है, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने देश को गणतांत्रिक व्यवस्था देने की जगह पार्टी व्यवस्था दे दी और इसका पोषण करने में वह अपनी सारी ताक़त लगाता रहा है और आज भी लगा रहा है. इस पार्टी सिस्टम में हर चुनाव में कोई न कोई नया व्यक्तित्व सामने आता है. हालांकि जनता उस व्यक्तित्व को परख कर उसके बारे में अपना फ़ैसला देती है, पर ज़हर खाना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक सच यह भी है कि हम लोकतंत्र में ज़हर खा रहे हैं.

> हम यह नहीं जानते कि क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन कम से कम एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है या राहुल गांधी की ज़रूरत है. ये भी राजनीतिक तौर पर उतने ही अनपढ़ हैं, जितना इन्होंने दूसरों को अनपढ़ बनाए रखने की कोशिश की और जनता को, जनता ही नहीं अपने कार्यकर्ता को, अपने कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि अपने प्रदेश स्तर के नेताओं को भी इन्होंने राजनीतिक रूप से अनपढ़ और अज्ञानी बना दिया है.

ये चुनाव जनता को शायद इस बात के लिए मजबूर करे कि अगर कहीं मुल्क इस संविधान की दिशा से चला होता, तो महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता था. अगर यह देश संविधान के हिसाब से चल रहा होता, तो अच्छे प्रतिनिधियों को संसद में जाने का मौक़ा मिलता. पर विडंबना तो यह है कि इस देश में संविधान को लेकर ही जब भ्रम फैलाए जाते हैं, तो फिर उन समस्याओं से हाल फ़िलहाल छुटकारे का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता.

जिस लोकतंत्र को इस देश में सर्वपूज्य होना चाहिए था, इन राजनीतिक दलों की वजह से उसी लोकतंत्र के ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं. नक्सलवादियों ने तो सीधा सवाल उठाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग़रीब की क्या कोई सुनवाई है. क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश के अल्पसंख्यक लोग, जिनके पास विकास की रोशनी नहीं पहुंचती है या आगे नहीं पहुंचेगी, क्या उनके लिए कोई काम है? नक्सलवादी साफ़ कहते हैं कि हिंदुस्तान की व्यवस्था में ग़रीब के लिए कोई स्थान नहीं है और ग़रीब को अपना स्थान बंदूक़ के बल पर बनाना पड़ेगा. नक्सलवादियों की यह थ्योरी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को तब समझ में आ जाती है, जब वे देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर उनके ऊपर शासन कर रहे लोग भयानक लूटपाट में व्यस्त हैं. लोगों को न केवल बांट रहे हैं, बल्कि उन्हें देश के बारे में सोचने से भी रोक रहे हैं. उन्होंने नौजवानों को बांटा, महिलाओं को बांटा, जाति के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, धर्म के नाम पर बांटा और लालच के नाम पर भी बांटा. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ये राजनीतिक दल सचमुच लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं या ये अपने लूट के पैसे से ख़ुशी मनाने के लिए इस पूरे देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं.

नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के पास क्या इन सवालों का कोई जवाब है? क्या ये दोनों जनता को बताएंगे कि उन्होंने संविधान समझ लिया है और संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के लिए जगह है? क्या उन्होंने समझ लिया है कि हमारे देश के सारे क़ानून, जिनका रिश्ता संविधान से नहीं है, अवैध माने जाने चाहिए? क्या इसके ऊपर इन दोनों के बीच मतैक्य है या इन दोनों ने संविधान नहीं पढ़ा है? यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या इन दोनों ने ख़ुद संविधान पढ़ा है?

हम यह नहीं जानते कि क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन कम से कम एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है या राहुल गांधी की ज़रूरत है. ये भी राजनीतिक तौर पर उतने ही अनपढ़ हैं, जितना इन्होंने दूसरों को अनपढ़ बनाए रखने की कोशिश की और जनता को, जनता ही नहीं अपने कार्यकर्ता को, अपने कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि अपने प्रदेश स्तर के नेताओं को भी इन्होंने राजनीतिक रूप से अनपढ़ और अज्ञानी बना दिया है.

इसीलिए इस देश की जनता को खड़ा होने की ज़रूरत है. उसे संविधान पढ़ने की ज़रूरत है और यह जानने की ज़रूरत भी है कि उसे कौन-सा सिस्टम चाहिए. अगर उसे संविधान सम्मत सिस्टम चाहिए, तो उसे राजनीतिक दलों के वर्चस्व से निकलना होगा और राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ बग़ावत करनी पड़ेगी और अपने बीच में से उम्मीदवारों को खड़ा कर जिताना होगा, ताकि ये लोकसभा में जाएं और वहां जाकर उनके हित के क़ानून बनाएं. राजनीतिक पार्टियां क़ानून अपने हित के हिसाब से बनाती हैं कि वे किस तरीक़े से जीत सकती हैं, किस तरीक़े से लोगों को हरवा सकती हैं और किस तरह से लोगों को लुभा सकती हैं. राजनीतिक पार्टियां उसे ध्यान में रखते हुए न केवल कानून बनाती हैं, बल्कि संसद और विधानसभाओं का इस्तेमाल भी करती हैं. अब जनता के ऊपर यह निर्भर करता है कि वह आगामी चुनाव में किस तरह का फ़ैसला लेती है. हालांकि यह भी मानना पड़ेगा कि जिस तरीक़े से जनता में जागृति आ रही है, इस बात का फ़ैसला वैसा नहीं होगा, जैसा अभी तक के पंद्रह आम चुनावों का हुआ है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कार्यपालिका अब विश्वास खो चुकी है

जिस दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और कांग्रेस को जीत हासिल हुई, उसी दिन संसद स्थगित कर दी गई. उस दिन का सेकेंड हॉफ बहुत खराब रहा, क्योंकि कार्यपालिका ने अपना सम्मान खो दिया. भारत में इस समय न तो वैधानिक कार्यपालिका है और न ही काम करने वाली विधायिका. न्यायपालिका ने कांग्रेस के बारे में जो टिप्पणी की है, वह कार्यपालिका के बारे में सही जानकारी देती है. उसी तरह भाजपा ने संसद की कार्रवाई रोकने में जो भूमिका निभाई, वह विधायिका की कार्यक्षमता दर्शाती है. केवल न्यायपालिका ही ऐसी संस्था है, जिस पर लोगों का विश्वास है और संविधान को स्वीकार करते समय जिस तरह की उम्मीद उससे की गई थी, वह उस पर अभी खरी उतर रही है. राजनीतिक दल आजकल न्यायालय की बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं. एक मंत्री मीडिया के सामने यह कहते हुए दिखाई पड़े कि कांग्रेस जनता की अदालत में जीत गई. उनके लिए केवल यही बात मायने रखती है कि चुनाव में उनकी स्थिति कैसी रहती है. देश के संविधान द्वारा बनाई गई न्यायपालिका की उन लोगों द्वारा उपेक्षा की जा सकती है, जो यह सोचते हैं कि पांच सालों में होने वाले चुनाव उन्हें अत्यधिक ताकत दे देते हैं.

वैसे, कांग्रेस इसे पहले से ही मानती रही है. इंदिरा गांधी ने बहुमत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था. उनका मानना था कि चुनावी विजय सरकार को असीमित ताकत देती है, जिसके बाद संविधान को भी उसी तरह बदला जा सकता है, जैसा कि सरकार चाहती है. उन्होंने यह दिखा और समझा भी दिया कि ऐसा कैसे किया जा सकता है. भारत कभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया है. दरअसल, कांग्रेस जब-जब सरकार में आती है, आपातकाल आता है. हालांकि यह आपातकाल दूसरे तरीके का होता है, लेकिन होता आपातकाल ही है. इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष की स्थिति इससे बेहतर है. वह तो एक कार्यकाल से ज़्यादा सत्ता में रह ही नहीं पाया. सत्ता में आने पर किस तरह का व्यवहार किया जाए, इसे लेकर दोनों की स्थिति एक जैसी ही है. इसलिए हम लोग अगले बारह महीनों तक इसी तरह से रहेंगे, जब तक कि अगला चुनाव यह निर्णय नहीं कर देता है कि सत्ता किसके हाथ में होगी, जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है या फिर कोई दूसरा, जो अभी उभर रहा है. कौन जीतेगा, यह प्रश्न अगले बारह महीनों तक सभी के मन में हलचल पैदा करता रहेगा.

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम ने इस मुद्दे पर बहुत हल्का प्रकाश डाला है. भाजपा ने तीन राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं कर्नाटक में हार का सामना किया है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उसकी हार का अंतर कम था, लेकिन कर्नाटक में हार का अंतर बहुत बड़ा रहा. कर्नाटक में कांग्रेस को येदियुरप्पा का फ़ायदा मिला, जिनके कारण भाजपा के वोट कटे और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम का फ़ायदा कांग्रेस को मिला. इसलिए इन चुनावों से 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. अगर अनुमान लगाने की कोशिश करें, तो वह इस तरह लगाया जा सकता है. जैसे मान लें कि भाजपा तीसरी बार पराजित होती है और किसी भी बड़ी पार्टी को 150 से अधिक सीटें नहीं मिलती हैं और ऐसे में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है. आगे यह अनुमान लगाएं कि कांग्रेस को 110-120 सीटें मिलती हैं और भाजपा को 130-140 सीटें. कर्नाटक के चुनाव में जनता दल (एस) की स्थिति अच्छी रही. इसके अलावा, बहुत कम ही राज्य हैं, जहां दोनों में से किसी भी बड़ी पार्टी की स्थिति बेहतर हो.

परिसंघीय ढांचे का विचार पहले से अधिक मज़बूत हो गया है. भारत अपने आपको बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की तरह प्रदर्शित कर रहा है, जो कांट्रैक्ट के आधार पर एक-दूसरे के साथ हैं और इसके लिए चुनावी लोकतंत्र को धन्यवाद देना चाहिए. इन तथ्यों के आधार पर देखा जाए, तो राज्यस्तरीय दलों के पास ही निर्णायक ताकत होगी. 1977-80 में जनता पार्टी का विभाजन लोकतांत्रिक राजनीति के लिए वास्तविक त्रासदी थी. उसने कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाया और उसकी व्यक्ति आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया. जब 1989 में कांग्रेस की पराजय हुई थी, तो कोई अकेला विकल्प देश के पास नहीं था. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प बनने का अच्छा मौक़ा था. उसके पास आज भी मौक़ा है, लेकिन अगर वह नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर उलझी रहती है, तो यह मौक़ा उसे नहीं मिलने वाला है. एक और विकल्प तीसरे मोर्चे का है, जिसमें दोनों में से कोई बड़ा दल उसे बाहर से समर्थन करेगा. हालांकि यह विकल्प पहले विफल हो चुका है, लेकिन इससे क्या? अगर भारत में बदलाव आता है, तो फिर यह विकल्प भी मौजूद है. ■

feedback@chauthiduniya.com

न्यूयॉर्क में फुटपाथ पर रहने वाले एक बेघर व्यक्ति को भी यह पता नहीं था कि कब उसकी क़िस्मत जग जाएगी.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

न डरें, आरटीआई का इस्तेमाल करें

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

कई बार ऐसी ख़बरें भी आती रहती हैं कि अमुक व्यक्ति को सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने पर धमकी मिली या जेल में ठूंस दिया गया या फ़र्ज़ी केस में फंसा दिया गया. ज़ाहिर है, सालों से ज़ंग लगी व्यवस्था और सामंती मानसिकता वाली नौकरशाही इस बात को हज़म ही नहीं कर पाती कि कोई आम आदमी उनसे सवाल पूछे. आम आदमी उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके या सवाल न पूछ सके, इसीलिए ये लोग साम, दाम, दंड, भेद का सहारा भी लेने से नहीं चूकते. हालांकि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. हां, थोड़ी समझदारी से काम ज़रूर लेना होगा. दरअसल, चौथी दुनिया आपको बताएगा कि ऐसे अधिकारियों से कैसे निपटना है, इनसे क्या पूछना है और कैसे पूछना है. बस, आप सवाल करने से डरें नहीं.

सूचना मिलने के बाद क्या करें?

यह अक्सर देखा गया है कि सवाल पूछने भर से ही कई बिगड़ी बातें रास्ते पर आने लगती हैं. उदाहरण के लिए, केवल अपनी अर्ज़ी की स्थिति पूछने भर से आपको अपना पासपोर्ट या राशन कार्ड मिल जाता है. यदि आपने आरटीआई से किसी भ्रष्टाचार या ग़लत कार्य का पर्दाफ़ाश किया है, तो आप सतर्कता एजेंसियों, सीबीआई को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं या एफ़आईआर भी करा सकते हैं. लेकिन देखा गया है कि सरकार दोषी के विरुद्ध लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती. यद्यपि कोई भी सतर्कता एजेंसियों पर शिकायत की स्थिति आरटीआई के तहत पूछकर दबाव अवश्य बना सकता है, लेकिन ग़लत कार्यों का पर्दाफ़ाश मीडिया के ज़रिए भी किया जा सकता है. एक बात तय है कि इस प्रकार सूचनाएं मांगना और ग़लत कामों का पर्दाफ़ाश होने से अधिकारियों को स्पष्ट संदेश जाता है कि उस क्षेत्र के लोग अब और अधिक सावधान हो गए हैं और भविष्य में इस प्रकार की कोई ग़लती पूर्व की भांति छुपी नहीं रहेगी.

क्या ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है, जिन्होंने आरटीआई का प्रयोग कर भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश किया है?

हां, ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जिनमें लोगों को शारीरिक हानि उस समय पहुंचाई गई, जब उन्होंने भ्रष्टाचार का बड़े पैमाने पर पर्दाफ़ाश किया. लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रार्थी को हमेशा ऐसा भय झेलना होगा. अपनी शिकायत की स्थिति या मामलों की जानकारी लेने के लिए अर्ज़ी लगाने का अर्थ आ बैल मुझे मार नहीं है. दरअसल, ऐसा तब होता है, जब कोई सूचना नौकरशाह-ठेकेदार की मिलीभगत या किसी माफ़िया का पर्दाफ़ाश करती हो.

तो फिर, मैं ऐसी स्थिति में आरटीआई का प्रयोग क्यों करूं?

पूरा तंत्र इतना सड़-गल चुका है कि यदि हम सभी अकेले या मिलकर अपना प्रयत्न नहीं करेंगे, तो फिर यह तंत्र कभी नहीं सुधरेगा. यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हमें करना है. लेकिन हमें ऐसा एक रणनीति बना कर और जोखिम को कम करके करना होगा.

ये रणनीतियां क्या हैं?

आप आगे आएं और किसी भी मुद्दे पर आरटीआई आवेदन दाख़िल करें. साधारणतया, कोई आपके ऊपर एकदम हमला नहीं करेगा. पहले वे आपकी ख़ुशामद करेंगे, ताकि आप अपना आवेदन वापस ले लें. आप जैसे ही कोई असुविधाजनक आवेदन डालते हैं, तो कोई आपके पास बड़ी विनम्रता के साथ उस आवेदन को वापस लेने की विनती करने आएगा. आपको उस व्यक्ति की गंभीरता और स्थिति का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए. यदि आप इसे काफ़ी गंभीर मानते हैं, तो अपने 15 मित्रों को भी तुरंत उसी कार्यालय में वही सूचना मांगने के लिए आरटीआई आवेदन डालने को कहें. बेहतर यही होगा कि यदि ये 15 मित्र भारत के विभिन्न भागों से हों. अब आपके देश भर के 15 मित्रों को डराना किसी के लिए भी मुश्किल होगा. यदि वे 15 में से किसी एक को भी डराते हैं, तो और लोगों से भी अर्ज़ियां दाख़िल कराएं. आपके मित्र भारत के अन्य हिस्सों से अर्ज़ियां डाक से भेज सकते हैं. इसे मीडिया में व्यापक प्रचार दिलाने की कोशिश करें. इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको वांछित जानकारी मिलेगी और आप जोखिमों को कम कर सकेंगे.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा, सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र भी लिख सकते हैं. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ख़ासकर उदर से संबंधित समस्या का ध्यान रखें. अपने मन की सोची रणनीति को किसी से उजागर न करें और केवल उस पथ पर अपना कार्य करते चलें. किसी शुभ कार्य में थोड़ा विलंब होगा. सामाजिक रूप से आपका उत्तरदायित्व बढ़ेगा, व्यापारी और नौकरीपेशा दोनों वर्ग अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

आप अहंकार से बचें. इस सप्ताह आपके प्रगति के रास्ते खुले रहेंगे. धनोपार्जन अच्छा होगा. धन के आगमन के कारण आप पारिवारिक लोगों का भी ख़ास ध्यान रख पाएंगे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे. स्वास्थ्य हल्के उतार-चढ़ाव के साथ ठीक रहेगा. कोई पुराना मित्र आपके लिए सहयोगी बनकर खड़ा रहेगा.

मिथुन 21 मई से 20 जून

इस सप्ताह व्यापारी आम तौर पर ख़ुश रहेंगे. यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा और आप आर्थिक लाभ भी हासिल करेंगे. मानसिक स्थिति आपकी मज़बूत होगी. आप परिवार को ध्यान देने वाले बनेंगे. नम्रता से पेश आएंगे और सबके प्रति आपका सौहार्द्रपूर्ण रवैया रहेगा. नौकरीपेशा लोग अपने स्थानांतरण को लेकर चिंतित रहेंगे.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह अचानक यात्रा का योग है. आप अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. कभी-कभी थोड़े सख्त समय को भी देखेंगे और आप डटकर उसका मुक़ाबला करेंगे. शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अंततः विजय प्राप्त करेंगे. व्यापारियों को व्यावसायिक तनाव रहेगा.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

आपको अपनी प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी. आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी और आपका आत्मविश्वास जागृत होगा. नए-नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे और विपरीत स्थिति भी आपके पक्ष में आएगी. पारिवारिक स्थिति आपके साथ होगी. अपनी प्रतिभा से आप सारी समस्याओं पर नियंत्रण कर लेंगे.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

आपका पूरा ध्यान अपने कार्यों पर होगा और पूरे सप्ताह आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे. परिवार के सदस्यों का सौहार्द्रपूर्ण वातावरण आपके साथ होगा. वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा. आपको क़ानूनी मामलों में भी विजय प्राप्त होगी. आगे के लिए कोई ठोस निवेश की योजना बनेगी. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

किसी पारिवारिक बुज़ुर्ग का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बनेगा. इस सप्ताह आप पारिवारिक ज़्यादा रहेंगे, यानी परिवार के प्रति आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा. निवेश और संपत्ति की ख़रीद पर ध्यान देंगे. पुराने लंबित कार्यों को आप निपटाएंगे. आर्थिक मामलों में मज़बूती आएगी. आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस सप्ताह पारिवारिक रूप से थोड़ी परेशानी बढ़ेगी. आप नई योजनाओ को लागू करने का प्रयास करेंगे. मेहनत थोड़ी ज़्यादा करेंगे और आपकी कार्यशैली में निखार आएगा. आपका लोगों से संपर्क बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे. स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह आप जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निर्णय न लें. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप नए उत्साह के साथ अपने कार्य में लगेंगे. कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी बढ़ेगी. संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों लोगों की स्थितियों में सुधार आएगा.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा. आप नई सोच को अंजाम तक पहुंचाएंगे. राजनीतिक और सामाजिक लोगों में आपकी पहुंच बढ़ेगी. आपके शत्रु परास्त होंगे और विरोधी पक्ष का स्वर नीचा रहेगा. पारिवारिक तौर पर उमंग का वातावरण रहेगा. व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

कुछ पुरानी समस्याएं पुनः उभर कर आएंगी और पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी. संतान से भी थोड़ी परेशानी बढ़ेगी. आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होगी और आप उसमें मज़बूती से अपनी बातों को रख पाएंगे. जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निर्णय न लें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों लोग फ़ायदे की स्थिति में रहेंगे.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

किसी के बहकावे में आकर कोई भी संपत्ति ख़रीदने का निर्णय न लें. क्रोध करने से बचें. आपको सगे-संबंधियों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा. कोई भी पूंजी निवेश परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों वर्ग अपने कार्यस्थल पर साथ कार्य करने वाले लोगों पर ध्यान रखें.

cshekhar_3@hotmail.com

ज़रा हट के

लिपस्टिक लगाने से बाधा

शादी से पहले हो या शादी के बाद हर किसी औरत को लिपस्टिक और नेल पेंट लगाने का बहुत शौक होता है. ऐसी बात नहीं है कि लिपस्टिक से सुंदरता छिप जाती है, बल्कि इसको लगाने से सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं. और लाल रंग की लिपस्टिक की बात ही कुछ अलग ही है. दरअसल, तुर्की ने अपनी सरकारी एयर होस्टेसों को लाल लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाने पर रोक लगा दी है. इस फरमान ने देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों को नाराज़ कर दिया है. टर्किश एयरलाइंस यूरोप की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइंस है. कंपनी ने एक बयान जारी कर यह कहा है कि एयर होस्टेसों का मेकअप और पहनावा सिंपल किया जा रहा है, ताकि यात्रियों के साथ संवाद को बढ़ाया जा सके, लेकिन धर्मनिरपेक्ष लोगों को फिक्र है कि देश ज़्यादा इस्लामिक हो रहा है. कंपनी की ओर से एक और बयान जारी कर यह कहा गया कि केबिन क्रू की जो मौजूदा यूनिफॉर्म है, उसमें लाल और गहरे गुलाबी रंग की नेल पॉलिश और लिपस्टिक को शामिल इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि ये रंग संवाद में बाधा बनते हैं. ■

मूंछों ने बनाया मालामाल

कहा जाता है कि हीरे की परख सिर्फ़ जौहरी को ही होती है. दरअसल, ख़ुद हीरे को भी यह नहीं पता होता कि वह कितना बेशक़ीमती है. ऐसा असल ज़िंदगी में भी लोगों के साथ हो सकता है. ग़ौरतलब है कि यह नहीं होता कि उनकी कौन-सी चीज़ कब उनकी क़िस्मत को चमका दे. न्यूयॉर्क में फुटपाथ पर रहने वाले एक बेघर व्यक्ति को भी यह पता नहीं था कि कब उसकी क़िस्मत जग जाएगी. जी हां, यह व्यक्ति रोज की तरह अपनी मूंछ के साथ करतब करने में मस्त होकर रास्ते में भटकता हुआ जा रहा था. तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नज़र उसके रोचक करतब पर पड़ी. उस व्यक्ति ने मूंछ के साथ करतब करने वाले की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए वीडियो बनाकर यू-ट्यूब पर डाल दिया.

बस फिर क्या था, लोगों को नाचती मूंछें इतनी पसंद आईं कि थोड़े ही दिनों में उसे लाखों हिट मिल गए. लोगों के बीच सुपरहिट होने के साथ वह मालामाल भी हो गया. इस काम के लिए उसे हाल ही में एक लाख का चेक और सर्टिफिकेट भी दिया गया है. ■

जल्द होगा इलाज

गांव में लोगों को इलाज कराने के लिए बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है, न ही उन्हें आसानी से साधन उपलब्ध होता है और न ही सही से दवाइयां उपलब्ध हो पाती हैं. लेकिन घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव के लोग अब जल्द ही घर के पास अपनी बीमारियों की जांच करा सकेंगे. ऐसा एक बहुत छोटी पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला के ज़रिए संभव हो पाएगा. यह इतनी छोटी है कि इसे आसानी से सूटकेस में रखकर, जहां चाहें ले जाया सकता है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है. इस जैव रासायनिक प्रयोगशाला को आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके अमित भटनागर ने बनाया है. ग़ौरतलब है कि भटनागर अमेरिका में नौकरी करते थे. उन्होंने इसके लिए हॉलीवुड के मशहूर यूनिवर्सल स्टूडियों की शानदार नौकरी छोड़ दी. इसे बनाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के तकनीकी विकास बोर्ड से चार करोड़ रुपये क़र्ज़ लिया. इस तकनीक से बहुत सारी बीमारियों के बारे में शुरुआती जांच में ही पता चल जाएगा. इस प्रयोगशाला में किडनी, लीवर, दिल, ख़ून की कमी, मधुमेह और गठिया सहित 23 बीमारियों की जांच की जा सकती है. यह प्रयोगशाला आने वाले दिनों में दूरदराज के इलाक़ों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगी. खासकर उनके लिए, जो जांच केंद्रों तक बहुत कम पहुंच पाते हैं और इसी वजह से कई बीमारियों का पता ही नहीं चल पाता. इस प्रयोगशाला की अधिकतम क़ीमत 3.5 लाख रुपये है, जिसमें ब्लड एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूग, माइक्रो पाइपेट, इंक्यूबेटर, लैपटॉप. जिसमें मरीज का डाटा मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और उपयोग की अन्य वस्तुएं हैं. इस पोर्टेबल लैब का इस्तेमाल सीमा सड़क संगठन अपने कारगिल, लेह, नगालैंड जैसे दूरदराज के चिकित्सालयों में कर रहा है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के जंगलों में इसका इस्तेमाल कर रही है. इसके अलावा, हरियाणा के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और केरल में प्रायोगिक तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है. ■

चुनाव से पहले पाकिस्तान के कई शहरों में बम विस्फोट किए गए. चुनाव के दौरान हुए हमलों में लगभग 110 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए.

नवाज़ से उम्मीद क्यों करनी चाहिए?

नवाज़ शरीफ़ के प्रधानमंत्री बनने से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या नवाज़ शरीफ़ भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे और अगर करेंगे, तो क्यों? क्या नवाज़ शरीफ़ भारत के प्रति नरम रुख़ रखते हैं या फिर भारत के साथ संबंध सुधारना पाकिस्तान के हित में है, इसलिए नवाज़ शरीफ़ को क्या इस ओर क़दम उठाना चाहिए? आख़िर भारत को नवाज़ से उम्मीद क्यों करनी चाहिए?

राजीव कुमार

rajiv@chauthiduniya.com

कट्टरपंथी संगठनों के हिंसात्मक विरोध के बीच पाकिस्तान में चुनाव हुए और लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ज़िंदा रखने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना चुनाव में हिस्सा भी लिया. राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और जनता अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए चुनाव में भाग लेती है. पाकिस्तान के चुनाव में साठ प्रतिशत मतदान हुआ, जिससे यह साफ़ हो गया है कि वहां की जनता को लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसा है न कि सैनिक तानाशाही पर. तानाशाही और लोकतंत्र के बीच सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर यही होता है कि तानाशाह को जनता की नहीं, बल्कि सेना की ताक़त चाहिए, जबकि लोकतांत्रिक सरकार को जनता की ताक़त चाहिए. ज़ाहिर है कि अगर जनता को साथ रखना है, तो उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा. सरकार अगर उसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखती है, तो वह उसे सत्ता से बाहर कर देगी. यही वह बात है, जो भारत के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा करती है.

पाकिस्तान की नई सरकार को जनता की ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा और इस समय जनता की सबसे बड़ी ज़रूरत आतंक से मुक्ति है, क्योंकि यही पाकिस्तान की समस्या की जड़ है, जो अन्य कई समस्याओं को पैदा करती है. अगर नई सरकार को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी है और फिर से सत्ता में आने की दावेदारी पेश करनी है, तो आतंकी संगठनों से पाकिस्तान को बचाना होगा और इसके लिए पाकिस्तान को भारत विरोध का राग अलापना बंद करना होगा. पाकिस्तान में आतंक की खेती होती है और इस खेती को बढ़ाने के लिए भारत विरोध नामक उर्वरक का उपयोग किया जाता है. जब तक इस उर्वरक को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के ख़तरे को रोका ही नहीं जा सकता है. एक लोकतांत्रिक सरकार इस ओर क़दम बढ़ा सकती है, क्योंकि उसे जनता को सुरक्षा मुहैया करानी है और जनता को सुरक्षा तभी मिलेगी, जब आतंकी संगठनों को कमज़ोर कर दिया जाएगा. आतंकी संगठन जेहाद के नाम पर वहां के युवाओं को भ्रमित करते हैं. पहले तो इन्हें कश्मीर के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन जब इनके नेता को लगता है कि पाकिस्तान सरकार या फिर वहां का समाज उनके अनुसार नहीं चल रहा है, तो ये भस्मासुर बन जाते हैं. पहले अमेरिका ने तालिबान को रूस के विरुद्ध उपयोग करने के लिए मदद की. जब तालिबान सशक्त हो गया और उसे लगा कि अमेरिका का हित उसके विरुद्ध जा रहा है, तो उसने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी. इसी तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को भारत में जेहाद के नाम पर तैयार किया गया, लेकिन अब स्थिति यह है कि ये जितना ख़तरा भारत के लिए बने हुए हैं, उससे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के लिए भी हैं.

अगर पाकिस्तान सरकार आतंक से अपनी जनता को सुरक्षा देना चाहती है, तो सबसे पहले उसे भारत के साथ छद्म युद्ध की नीति त्यागनी होगी. चूंकि नवाज़ शरीफ़ को जनता ने इसलिए चुना, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शासनकाल में सेना और न्यायपालिका के साथ लगातार सरकार का टकराव होता रहा. राष्ट्रपति ज़रदारी के ऊपर भ्रष्टाचार का मुक़दमा चलाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी को अपना पद त्यागना पड़ा. आतंकवाद पहले से अधिक बढ़ गया. वहां की जनता को लगा कि पीपीपी से उम्मीद करना बेकार है. जनता के पास दूसरा विकल्प इमरान ख़ान के रूप में उपलब्ध था, लेकिन इमरान पर सेना से गुपचुप समझौते का आरोप लग रहा था और वहां की जनता किसी भी तरह से सेना को शासन में शामिल नहीं करना चाहती थी. शायद इसलिए इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ख़ैबर-पख्तून-ख्वा में बहुमत मिला, लेकिन नेशनल एसेंबली में उसे बहुत कम सीटें मिलीं. जनता ने नवाज़ शरीफ़ को इसलिए मौक़ा दिया है, क्योंकि उनकी सेना के साथ लगातार अनबन होती रही है. उसे दो बार सत्ता खोनी पड़ी है. पहली बार वह तीन साल के लिए और दूसरी बार दो साल के लिए प्रधानमंत्री बने. उन्हें अपनी नीतियों को लागू करने का मौक़ा नहीं मिला, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पांच साल का मौक़ा मिला और उसने अपना चरित्र दिखा दिया. ऐसे में नवाज़ शरीफ़ को मौक़ा मिला है और अगर वह अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत के साथ संबंध सुधारना पड़ेगा. भारत विरोध की राजनीति त्यागने से आतंकवाद पर अंकुश लगेगा और इससे वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. अर्थव्यवस्था में सुधार से शिक्षा और रोज़गार सृजन के क्षेत्र में निवेश किया जा सकेगा. बेरोज़गारी और आतंकवाद एक दूसरे के समानुपाति हैं, क्योंकि बेरोज़गार युवकों को भ्रमित करना ज़्यादा आसान होता है.

नवाज़ शरीफ़ एक परिपक्व राजनेता हैं और उनसे इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वह अपना और पाकिस्तान की जनता के भविष्य का ख्याल रखेंगे. हालांकि उन्होंने साफ़ तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कश्मीर है और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना दूसरे रिश्ते नहीं सुधर सकते. नवाज़ की बात सही है और इस पर बात होनी भी चाहिए. दोनों देश इस मुद्दे को एक तार्किक परिणति तक पहुंचाएं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीक़े से. नवाज़ शरीफ़ भी यह कह रहे हैं और भारत सरकार का भी यही मानना है, इसलिए अच्छे रिश्तों की उम्मीद तो की ही जा सकती है. पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते सुधरने से दोनों का व्यापार बढ़ेगा, भारत की तकनीकी जानकारी और बड़े बाज़ार का लाभ पाकिस्तान को होगा. पाकिस्तान के कपास, उर्वरक, खेल के सामान आदि का बहुत बड़ा बाज़ार भारत में है. इसलिए भारत के साथ संबंध सुधारने से ही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता तैयार होता है और अगर तरक्की होगी, तो जनता को शासन पर भरोसा होगा और इसी भरोसे से लोकतंत्र मज़बूत होगा. नवाज़ शरीफ़ इस लोकतंत्र की उपज हैं और वह इस बात को जानते भी हैं. यही कारण है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार आदि के इतने आरोपों के बावजूद उसकी सरकार गिराने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि उसे अपना कार्यकाल पूरा करने दिया. हालांकि नवाज़ के आने से इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान का भारत के प्रति रुख़ बिल्कुल नरम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो नरम होगा ही, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और नवाज़ शरीफ़ का भविष्य भी सुरक्षित होगा और इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों की बहाली का फ़ायदा जनता को भी मिलेगा. एक बार अगर जनता को भारत के साथ अच्छे संबंधों का फ़ायदा दिखाई देने लगेगा, तो भारत के प्रति उनकी कड़वाहट में कमी आना लाज़िमी है. इसलिए धीरे-धीरे दोनों को आगे बढ़ना होगा. इसके अलावा, सैनिक शासन की वापसी को रोकने के लिए भी नवाज़ भारत के मुद्दे को सुषुप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाहों का सबसे बड़ा मुद्दा भारत विरोध ही रहा है. नवाज़ अपने राजनीतिकि भविष्य को बचाए रखने के लिए भारत के प्रति नीति में परिवर्तन लाएंगे और उन्होंने चुनाव के बाद इसका संकेत भी दे दिया है. ■

पाकिस्तान की नई सरकार को जनता की ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा और इस समय जनता की सबसे बड़ी ज़रूरत आतंक से मुक्ति है, क्योंकि यही पाकिस्तान की समस्या की जड़ है, जो अन्य कई समस्याओं को पैदा करती है. अगर नई सरकार को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी है और फिर से सत्ता में आने की दावेदारी पेश करनी है, तो आतंकी संगठनों से पाकिस्तान को बचाना होगा और इसके लिए पाकिस्तान को भारत विरोध का राग अलापना बंद करना होगा. पाकिस्तान में आतंक की खेती होती है और इस खेती को बढ़ाने के लिए भारत विरोध नामक उर्वरक का उपयोग किया जाता है.

यह अवाम की जीत है

पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हो गए. नवाज़ शरीफ़ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) सबसे बड़ी पार्टी बनी. लेकिन इस चुनाव में जीत किसकी हुई? देखा जाए, तो बेशक नवाज़ शरीफ़ जीते हैं, लेकिन इस चुनाव में वास्तविक जीत लोकतंत्र की हुई है और इस जीत का श्रेय जनता को जाता है. जनता ने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए लोकतंत्र की इस मुहिम को सफल बनाया है, उससे इस बात का संकेत मिलता है कि अब जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई है. पाकिस्तानी तालिबान ने इस चुनाव का विरोध किया था. चरमपंथी संगठनों ने इस चुनाव को विफल बनाने का भरसक प्रयास किया. चुनाव से पहले पाकिस्तान के कई शहरों में बम विस्फोट किए गए. चुनाव के दौरान हुए हमलों में लगभग 110 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए. पार्टी के दफ्तरों के पास भी बम

विस्फोट किए गए, यहां तक कि चुनाव के समय भी कई जगहों पर बम विस्फोट किए गए. चुनाव शुरू होने के क़रीब दो घंटे के बाद ही कराची में अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर के पास बम विस्फोट हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई तथा लगभग 60 लोग घायल हो गए. पाकिस्तानी तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी भी ली. इन घटनाओं के बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने देश में लोकतंत्र बहाल करने के प्रति अपनी कटिबद्धता दिखाई और घरों से बाहर निकलकर वोट डाले. पाकिस्तान के इस चुनाव में मतदान साठ प्रतिशत रहा, जिसे बहुत अच्छा माना जा सकता है. भारत जैसे देश में भी इसके आसपास ही वोट डाले जाते हैं, कुछ प्रदेशों में तो 50-55 प्रतिशत वोट डाले जाते हैं. पाकिस्तान की जनता ने साहस के साथ इन चरमपंथी संगठनों का सामना किया और अपनी जान की परवाह किए बिना वोट डाले. वोट डालने के लिए जाने वाले लोगों से जब कुछ पत्रकारों ने हिंसा के बारे में पूछा, तो उनमें से कुछ का कहना था कि वे या तो मतदान करेंगे या फिर मतदान करते हुए मारे जाएंगे. उनका कहना था कि मतदान करने के लिए जाते हुए मरना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाए इसके कि पांच साल तक हर दिन मरते रहें. देखा जाए, तो पाकिस्तान के इस चुनाव में किसी दल की नहीं, बल्कि अवाम की जीत हुई है, जो किसी भी हालत में फिर से सैनिक शासन नहीं चाहती है.

जम्मू से पहलगाम 315 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां एसआरटीसी की बसों और निजी टैक्सियों से पहुंचा जा सकता है.

बाबा का जीवन और चरित्र

भक्तों की साई बाबा में अटूट आस्था थी. उनके लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस (काशी), महाकालेश्वर एवं गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई. साई बाबा का जीवन चरित्र जानने के लिए पढ़िए बाबा के जीवन और चरित्र के बारे में.

अगर हम साई बाबा के जीवन और चरित्र का अवलोकन करेंगे, तो पाएंगे कि उन्होंने उस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना हम सबके लिए अत्यंत दुष्कर है. शांति उनका आभूषण था और वह ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे. वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे. दानवीरों में वह राजा कर्ण के समान दानी थे. वह समस्त सारों के सरारूप थे. सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था. सच तो यह है कि अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था. उनका हृदय शीशे के समान उज्ज्वल था. उनके श्रीमुख से सदैव अमृतवर्षा होती थी. अमीर और ग़रीब उनके लिए एक समान थे. मान-अपमान की उन्हें रंचमात्र भी चिंता नहीं थी. वह निर्भय होकर सम्भाषण करते, भांति-भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते और मनोरंजन भी करते थे. इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि रंचमात्र भी भंग नहीं होती थी. अल्लाह का नाम सदा उनके होंठों पर होता था. जब दुनिया जागती, तो वह सोते और जब दुनिया सोती, तो वह जागते थे. उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था. न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था. कहने के लिए तो वह एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों-व्यापारों का उन्हें भली-भांति ज्ञान था. उनके दरबार का रंग ही निराला था.

वह प्रतिदिन अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति बिल्कुल विचलित नहीं होती थी. वह सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे. वह प्रातः, मध्यान्ह एवं सायंकाल लेंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते, तो ऐसे में भी वह सदा आत्मस्थित ही रहते थे. स्वतः सिद्ध होकर भी वह साधकों के समान आचरण करते थे. वह विनम्र, दयालु एवं अभिमान रहित थे. उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया. ऐसे थे श्री साईबाबा, जिनके श्रीचरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई. उसका महत्व असाधारण हो गया. शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साई चरणांबुजों का स्पर्श और उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. भक्तगणों के लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस (काशी), महाकालेश्वर एवं गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई. श्री साई का दर्शन करना ही भक्तों का वेदमंत्र था, जिसके परिणामस्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था. उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे. उनकी चरण सेवा करना त्रिवेणी (प्रयाग) स्नान के समान था और चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी. उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद समान थी. प्रसाद और उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी. वही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की. वह ही हमारे परब्रह्म थे. वह कभी निराश-हताश नहीं होते थे. वह सदा आत्मस्थित, चैतन्यघन एवं आनंद की मंगलमूर्ति कहलाते थे. कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक फैला था. साई बाबा की कीर्ति दिन-प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह-जगह से उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे. केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध हृदय के हों या अशुद्ध, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी. उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था, जैसा पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है. यह कोई अतिश्योक्ति नहीं है, क्योंकि हर भक्त का अनुभव यही कहता है. ■

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे. दानवीरों में वह राजा कर्ण के समान दानी थे. वह समस्त सारों के सरारूप थे. सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था. सच तो यह है कि अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था. उनका हृदय शीशे के समान उज्ज्वल था.

आस्था

...भगवान शिव का भ्रमण...

अनंतनाग, पहलगाम, पिस्सु टॉप, शेषनाग झील आदि. क्या है इन सभी स्थानों का महादेव से संबंध, जानने के लिए पढ़िए किस तरह भगवान शिव ने भ्रमण किया.

विभा कुमारी
feedback@chauthiduniya.com

एक बार हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की. उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसे स्थान की खोज की, जहां कोई भी प्राणी न हो. दरअसल, इस स्थान की खोज में उन्होंने जिन स्थान का भ्रमण किया, वे उनके कारण अमर हो गए. भगवान शिव अमरत्व का रहस्य केवल पार्वती को ही बताना चाहते थे, इसीलिए ख़ुद से हमेशा लिपटे रहने वाले अनंत नागों को उन्होंने जहां छोड़ा, वह स्थान अनंतनाग कहलाया. इससे पहले अपने नंदी बैल को उन्होंने पहलगाम (बैलगाम) में छोड़ा. आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने मस्तक का चंदन उतार दिया और यह स्थान चंदनबाड़ी कहलाया. अन्य पिस्सुओं को जिस पहाड़ी पर छोड़ा, वह पहाड़ी आज भी पिस्सु टॉप के नाम से जानी जाती है. अपने प्रिय शेषनाग को उन्होंने झील में वास करने को कहा और वह नीले पानी की झील शेषनाग झील कहलाई. मान्यता है कि शेषनाग आज भी उसी झील में वास करते हैं. धूल, पानी, अग्नि, हवा, आकाश आदि पंच महाभूतों को उतारते ही यह स्थान पंचतरणी कहलाया.

अमर हुआ कबूतरों का जोड़ा : लोक मान्यताओं के अनुसार, निर्जन स्थान की खोज करते हुए भगवान शिव उस पवित्र गुफ़ा में पहुंचे और मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य समझाने लगे. इस दौरान एक कबूतरी का अंडा उस गुफ़ा में मौजूद था, जिसकी तरफ़ भगवान शिव का ध्यान नहीं गया. उस अंडे से कबूतरों के जोड़े ने जन्म लिया और वह अमर हो गया. मान्यता है कि अब भी श्रावण मास के दौरान कबूतरों का वह जोड़ा किसी सौभाग्यशाली श्रद्धालु को नज़र आ जाता है.

पहला पड़ाव जम्मू : श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से रेलमार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए प्रथम पड़ाव होता है जम्मू, जिसके लिए भगवती नगर में यात्री निवास का निर्माण किया गया है. जम्मू रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यात्रा के दौरान यात्री निवास तक के लिए विशेष मिनी बसों की व्यवस्था रहती है. इसके अलावा, ऑटो रिक्शा से भी वहां तक पहुंचा जा सकता है. यात्री निवास में न केवल यात्रियों के ठहरने की नि:शुल्क व्यवस्था होती है, बल्कि भोजन और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था भी रहती है.

यात्रा रूट : श्री अमरनाथ यात्रा के लिए दो रूटों से यात्रा की जा सकती है. पहला रूट पहलगाम से शुरू होता है, जबकि दूसरा बालटाल से.

पहलगाम से यात्रा : श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिहाज़ से पहलगाम मार्ग से ही यात्रा करने की सलाह देता है. हालांकि यह मार्ग थोड़ा लंबा, लेकिन बालटाल की तुलना में कम जोखिम भरा है.

जम्मू से पहलगाम 315 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां एसआरटीसी की बसों और निजी टैक्सियों से पहुंचा जा सकता है. पहलगाम से चंदनबाड़ी 16 किलोमीटर, चंदनबाड़ी से पिस्सु टॉप 3 किलोमीटर, पिस्सु टॉप से शेषनाग 9 किलोमीटर, शेषनाग से पंचतरणी 12 किलोमीटर और पंचतरणी से गुफ़ा का रास्ता 6 किलोमीटर का है.

बालटाल से यात्रा : समय बचाने के लिए कुछ लोग बालटाल मार्ग का चयन करते हैं. जम्मू से ऊधमपुर, काजीगुंड, अनंतनाग, श्रीनगर और सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचा जा सकता है. बालटाल से पवित्र गुफ़ा महज़ 14 किलोमीटर की दूरी पर है. बालटाल से 2 किलोमीटर पर दोमेल, दोमेल से 5 किलोमीटर पर बरारी मार्ग, यहां से संगम 4 किलोमीटर और संगम से गुफ़ा मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ■

लोक मान्यताओं के अनुसार, निर्जन स्थान की खोज करते हुए भगवान शिव उस पवित्र गुफ़ा में पहुंचे और मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य समझाने लगे. इस दौरान एक कबूतरी का अंडा उस गुफ़ा में मौजूद था, जिसकी तरफ़ भगवान शिव का ध्यान नहीं गया. उस अंडे से कबूतरों के जोड़े ने जन्म लिया और वह अमर हो गया.

दरअसल...

समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए

दिलीप कुमार
feedback@chauthiduniya.com

यह बहुत पहले की बात है. एक पागल हाथी ने अचानक एक व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया. परेशान व्यक्ति जी जान से भागने की कोशिश कर रहा था, ताकि हाथी उसे पकड़ न सके. लेकिन हाथी धीरे-धीरे उसके और निकट आता जा रहा था. अचानक दौड़ते-दौड़ते उस व्यक्ति की नज़र एक सूखे कुएं पर पड़ी. उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए उसने कुएं में छलांग लगा दी. छलांग लगाने के बाद कुएं के नीचे घूमते सर्पों पर उसकी दृष्टि गई. पीपल की एक मोटी डाली उसके बिल्कुल निकट थी, इसलिए उसने उस डाल को ज़ोर से पकड़ लिया, ताकि वह नीचे न गिर जाए.

अब तक हाथी कुएं तक पहुंच चुका था. वहां पहुंच कर हाथी ने उस व्यक्ति को अपनी सूढ़ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था. वहां तक उसकी सूढ़ नहीं पहुंच सकती थी. अब उस व्यक्ति की नज़र हाथी पर पड़ी. दूसरी ओर उसने देखा कि एक सफ़ेद और एक काला चूहा डाली को काट रहे हैं. उस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि वह हर ओर से समस्याओं से घिर गया है. एक तरफ़ हाथी, दूसरी तरफ़ सांप और तीसरी ओर दो चूहे. उसे समझ में आ गया कि बचने का कोई मार्ग नहीं है. लेकिन फिर भी वह जीना चाहता था. वह समस्याओं से ज़रूर घिर गया था, लेकिन वह चिंतित नहीं था, क्योंकि वह एक साहसी कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था. वह पेड़ की डाल पर लटक कर इधर-उधर देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी. छत्ते से मधु टपक रहा था. निकट के एक पत्ते को उसने चाट लिया, जिससे मधु चू रहा था. अब उसकी जान में जान आई. वह अंदर से इतना प्रसन्न हो गया कि उसे एक बात सूझी. क्यों न मधुमक्खी के छत्ते को हिला दे. अब उसने जैसा सोचा, वैसा ही किया. दरअसल, पेड़ की टहनी हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगीं. मधुमक्खियों ने उस तरह धावा बोला, तो हाथी ही नहीं, चूहे भी वहां से भाग गए. अब ऊपर कोई नहीं था. वह धीरे-धीरे टहनी पकड़ कर ऊपर आ गया और अपने घर चला गया.

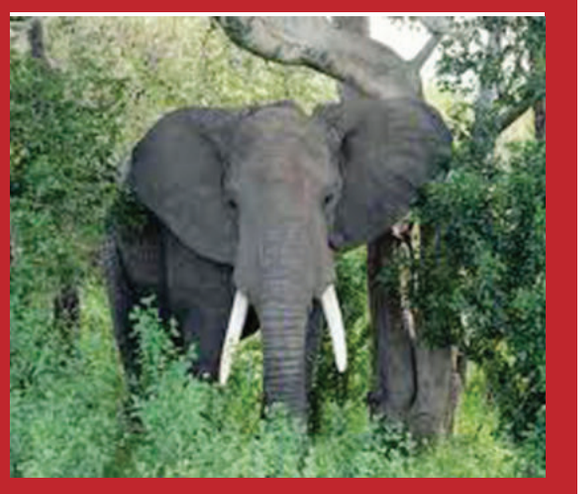

शिक्षा : इस छोटी-सी कहानी से हमें यही सबक़ मिलता है कि हमें समस्याओं से घिरने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुक़ाबला करना चाहिए.

महादेवी वर्मा ने सात साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था. उनके काव्य का मूल स्वर दुख और पीड़ा है, क्योंकि उन्हें सुख के मुक़ाबले दुख ज़्यादा प्रिय रहा.

अनंत विजय

लेखिकाएं सेक्स ऑब्जेक्ट न हों : तसलीमा

तसलीमा कुछ कहें और सेक्स और महिला अधिकार न हो, यह तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सेक्स और सेक्सुअल ऐक्ट तसलीमा के प्रिय विषय हैं और इन विषयों को वह जहां और जब मौक़ा मिलता है, फ़ौरन पेश कर देती हैं. आख़िर वह विवादास्पद बयान क्यों देती हैं?

हिंदी साहित्य में लंबे समय से इस बात पर लगातार विलाप किया जाता रहा है कि साहित्य के पाठक घट रहे हैं. मेरे एक मित्र का कहना है कि जब भी किसी साहित्यिक पत्रिका में उनकी कोई कहानी छपती है, तो ऐसे में सिर्फ़ बुज़ुर्गों की प्रतिक्रिया मिलती है. शायद उनका यही मानना है कि हिंदी साहित्य सिर्फ़ बूढ़े और साठ पार के लोग पढ़ते हैं. और अगर सचमुच ऐसा है, तो यह बेहद चिंता की बात है. दरअसल, हमारा देश युवाओं का है और अगर हिंदी साहित्य को लेकर हमारा युवा उदासीन है, तो ऐसी स्थिति में हमें गंभीरता से इस विषय पर विचार करना ही होगा. सच तो यह है कि न केवल सरकार को, बल्कि ग़ैर सरकारी संगठनों को भी युवाओं को हिंदी साहित्य की ओर प्रेरित करने के लिए क़दम उठाने ही होंगे. दरअसल, संयुक्त प्रयास से ही स्वीकार्यता और लोकप्रियता दोनों बढ़ेगी.

हिंदी साहित्य के लिए इस निराशाजनक माहौल में वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली के अरुण माहेश्वरी ने साहस दिखाते हुए युवा और कहानी संग्रह छपने के पहले ही ग़ैर साहित्यिक वजहों से चर्चित लेखिका ज्योति कुमारी के कहानी संग्रह दस्तख़त और अन्य कहानियों को हिंदी के युवा लेखकों के बीच का बेस्ट सेलर घोषित कर दिया. दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक छोटे, लेकिन गरिमामय समारोह में अरुण जी ने इस बात का ऐलान किया. उनका दावा है कि सिर्फ़ दो महीने में इस कृति की एक हज़ार प्रतियां बिक गईं. उन्होंने इस बात को भी साफ़ किया कि यह सरकारी थोक ख़रीद नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पाठकों द्वारा ख़रीदी गई हैं. यह एक ऐसे वक़्त में हुआ है, जब प्रकाशकों पर किताबों की बिक्री के आंकड़ों को छुपाने और रॉयल्टी नहीं देने के संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं. अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इसे हिंदी साहित्यिक प्रकाशन जगत में शुभ संकेत माना जाना चाहिए. हालांकि इस बात का जवाब आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है. लेकिन सवाल यह है कि एक हज़ार प्रतियों पर बेस्ट सेलर हो जाना, क्या शर्मिंदगी का सबब नहीं है. साठ करोड़ से ज़्यादा हिंदी भाषी के देश में यह संख्या कहां है, इसका अंदाज़ा पाठक लगा सकते हैं. दरअसल, हिंदी में बेस्ट सेलर की कोई परंपरा रही नहीं है और न ही इसको बनाने की कोशिश कभी की गई है. यह तो हम सभी जानते ही हैं कि बेस्ट सेलर की सूची कोई पत्रिका या फिर कोई अख़बार ही बनाता है. हक़ीक़त में, बेस्ट सेलर की अवधारणा तक़रीबन सवा सौ साल पुरानी है. आइए बता दें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई.

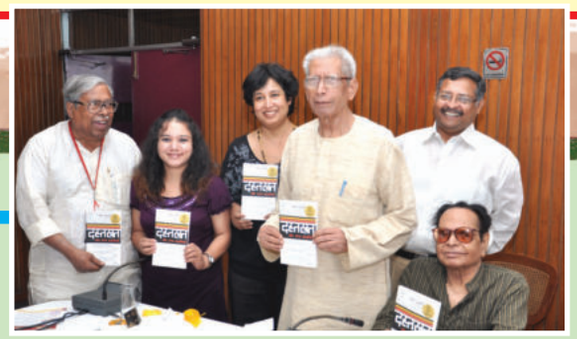

सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क से निकलने वाली पत्रिका द बुकमैन ने 1895 में अमेरिका के प्रमुख प्रकाशकों से बात करके एक सूची तैयार की थी. वह सूची लोगों ने काफ़ी पसंद की. नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की पत्र पत्रिकाओं ने उसकी ही तर्ज़ पर बेस्ट सेलर की सूची छापनी प्रारंभ कर दी. लेकिन हिंदी में किसी भी पत्र–पत्रिका ने यह साहस नहीं दिखाया या यह कहें कि कोई पहल नहीं हुई, लिहाज़ा हिंदी में बेस्ट सेलर की अवधारणा का विकास ही नहीं हो पाया. 1994 में अवध नारायण मुद्गल के संपादन में छाया मयूर में एक सूची प्रकाशित हुई थी, लेकिन पत्रिका का दूसरा अंक नहीं निकल सका और इसीलिए यह सूची आगे ही नहीं बढ़ सकी. ज्योति कुमारी के संग्रह पर पाठकों के रेस्पांस को लेकर प्रकाशक अरुण माहेश्वरी उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि अगर लेखक और प्रकाशक मिलकर काम करें, तो यह काम और भी आसान हो सकता है. समारोह में मौजूद नामवर जी ने भी लेखिका को प्रकाशक नहीं बदलने की सलाह दी.

इस कार्यक्रम में मशहूर, विवादास्पद और आजकल ट्विटर पर अजीबोग़रीब ट्वीट कर चर्चा में बनी रहने वाली लेखिका तसलीमा नसरीन भी पधारी थीं. तसलीमा कुछ कहें और सेक्स और महिला अधिकार न हो, यह तो मुमकिन ही नहीं है. लेकिन उत्साह में उन्होंने घालमेल कर दिया. पहले तो उन्होंने यह कहा कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लिखने का वक़्त कम मिलता है. तसलीमा के मुताबिक़, महिलाओं को घर के भी काम करने पड़ते हैं, इसलिए उनके पास लेखन के लिए पुरुषों की अपेक्षा कम वक़्त होता है. तसलीमा का यह तर्क न केवल बेहद हास्यास्पद लगा, बल्कि लचर भी. क्योंकि ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पुरुषों को घर के बाहर के काम नहीं करने पड़ते हैं. तसलीमा ने साहित्य जगत में महिलाओं की बराबरी की वकालत की. लेकिन तसलीमा नसरीन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि महिलाओं को साहित्य में बराबरी का दर्जा कैसे मिले.

दरअसल, तसलीमा की दिक्कत ही यही है कि वह कुछ घिसे–पिटे जुमलों के आधार पर अपनी दुकानदारी चलाती हैं. जिस उपन्यास लज्जा से उन्हें शोहरत और पहचान मिली, वह भी उपन्यास न होकर अख़बारी रिपोर्ट है. लेकिन तसलीमा इस कला में पारंगत हैं कि किस तरह से किसी कृति को या अपनी उपस्थिति को चर्चित या विवादास्पद बनाया जा सके. चाहे वह लज्जा हो या फिर उनकी आत्मकथा, जिसे साहित्य अकादमी के दिवंगत अध्यक्ष सुनील गंगोपाध्याय पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सनसनीख़ेज़ बनाया गया. बिक्री भी हुई और विवाद भी हुआ. उस दिन भी तसलीमा ने बोलते बोलते कह दिया कि वूमेन शुड नॉट बी मेड सेक्स ऑब्जेक्ट. ज़ाहिर तौर पर वह यह बात साहित्य के संदर्भ में कह रही थीं. लेकिन यहां भी उन्होंने सामान्यीकरण करते हुए यह बात कही और आगे निकल गईं. तसलीमा को यह बात साफ़ करनी चाहिए थी कि किस भाषा में, किस साहित्य में महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाया और समझा जाता है. मुझे दरअसल, यह लगता है कि हिंदी की कई लेखिकाओं पर गाहे–बगाहे यह आरोप लगते रहते हैं कि वे ग़ैर साहित्यिक वजहों और द्वंद्व–फंद की वजह से साहित्य के केंद्र में बनी रहती हैं. पुरस्कार से लेकर तमाम सम्मान हासिल करती हैं. अपना इस्तेमाल करते हुए प्रसिद्धि पाती हैं. हो सकता है कि इसमें सच्चाई नहीं हो, लेकिन कई प्रतिभाहीन लेखिकाएं जिस तरह से हिंदी जगत में छाती चली जा रही हैं, उससे यह शक और गहराता है. लेकिन यह प्रवृत्ति सिर्फ़ साहित्य में नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति साहित्य के अलावा, समाज के तक़रीबन हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, चाहे वह राजनीति हो, फिल्म हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो! सेक्स और सेक्सुअल एक्ट तसलीमा के प्रिय विषय हैं और इन विषयों को वह जहां और जब मौक़ा मिलता है, फ़ौरन पेश कर देती हैं. तसलीमा को अब मैच्योर लेखक की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन लंबे समय से निर्वासन और देश निकाले का दंश झेलने की वजह से उनकी मन:स्थिति को समझा जा सकता है. सेक्स जीवन का अनिवार्य तत्व ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ के पीछे सिर्फ़ सेक्स ही हो, यह कहना उचित नहीं होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

चांद-सी उज्ज्वल कविताएं

हाल में शिल्पायन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने चेतन कश्यप का कविता संग्रह चांद के दर पर दस्तक प्रकाशित किया है. तमाम कविताएं मन को छू लेने की तासीर रखती हैं. क्या है इस किताब में ख़ास?

फ़िरदौस ख़ान firdaus.journalist@gmail.com

मन की कोमल भावनाओं को शब्दों में पिरोना ही काव्य कहलाता है. कविताएं दो तरह की होती हैं, एक छंदयुक्त और दूसरी मुक्तछंद. दरअसल, छंद कविताओं को प्रभावी बनाते हैं और इन कविताओं को गाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मुक्तछंद कविताएं गाई नहीं जा सकती हैं. ऐसा नहीं है कि मुक्तछंद कविताएं प्रभाव नहीं छोड़तीं, क्योंकि अच्छी कविताएं पाठक पर गहरा असर डालती ही हैं. ग़ौरतलब है कि मुक्तछंद कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देन हैं. कहा जाता है कि काव्य की दुनिया में एक वक़्त ऐसा आया कि कवि छंद पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और कविता पर कम. ऐसे में कविता में छंद तो रहा, लेकिन कविता ग़ायब–सी होने लगी. तब निराला मुक्तछंद कविताओं की शुरुआत करके काव्य जगत में नई क्रांति लेकर आए. हालांकि उस वक़्त उनका काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन उस विरोध का उन पर कोई असर नहीं हुआ. आज भी छंद के पैरोकार मुक्तछंद कविताओं को काव्य मानने से इंकार करते हुए इन्हें गद्य क़रार देते हैं. मगर इस सबके बावजूद मुक्तछंद कविताओं ने एक लंबा सफ़र तय किया है और इनकी लोकप्रियता दिन–ब–दिन बढ़ती ही जा रही है. मुक्तछंद कविताओं के आए दिन प्रकाशित हो रहे काव्य संग्रह इनकी जनप्रियता के ही प्रतीक हैं.

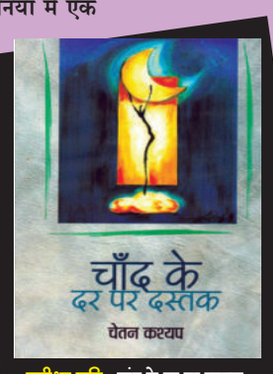

समीक्ष्य कृति : चांद के दर पर दस्तक
कवि : चेतन कश्यप
प्रकाशक : शिल्पायन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
क़ीमत : 150 रुपये

हाल में शिल्पायन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने चेतन कश्यप का कविता संग्रह चांद के दर पर दस्तक प्रकाशित किया है. अपने नाम की मानिंद इस कविता संग्रह में शामिल तमाम कविताएं मन को छूने की तासीर रखती हैं. इनमें जहां एक ओर ज़िंदगी की जद्दोजहद है और दुख–सुख की धूप–छांव है, तो वहीं दूसरी ओर वहीं इंद्रधनुषी सपनों को हक़ीक़त में बदलने की ललक भी दिखाई पड़ती है. चांद के दर तक पहुंचकर दस्तक देने का जज्बा तो चेतन जैसे कवियों में ही हो सकता है. दरअसल, उनकी कविताएं नए मिज़ाज की ऐसी कविताएं हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि इनमें शब्दों का सौंदर्य है, तो अनुभूतियों की गहराई भी है. वह बख़ूबी जानते हैं कि अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए उन्हें किन शब्दों का चयन करना है. यह उनकी ख़ासियत है कि उन्होंने आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावनाओं को बेहद नफ़ासत के साथ कविताओं में ढाला है.

उनकी कविता उदासी को ही देखिए–

आधा अधूरा चांद
कुम्हलाया हुआ
दिखता है
क़िले की दीवार से सर टिकाए हुए
ये कोई आईना है
जिसमें मेरा अक्स दिखता है
या ये कोई पाती है
कि जिसमें तुम्हारी ख़बर आती है

यह किसी रचनाकार की सबसे बड़ी कामयाबी है कि पाठक उसकी रचना से सीधे जुड़कर उससे रिश्ता क़ायम कर लेता है. उनकी कविताएं गहरी छाप छोड़ती हैं. जैसे–

एक अरसे बाद
दिल ने चाहा
कि दुआ मांगी जाए
आंखें ख़ुद–ब–ख़ुद बंद हो गईं
हाथ ख़ुद–ब–ख़ुद जुड़ गए
और मन ने कहा–
सभी इसी तरह ख़ुश रहें, यूं ही ख़ुश रहें
सदा, सर्वदा

चेतन कश्यप की रचनाएं पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं. बहरहाल, उनकी कविताएं पढ़कर पाठकों को सुकून की अनुभूति होगी. किताब का आवरण बेहद आकर्षक है. ■

एक संन्यासिनी कवयित्री महादेवी वर्मा

बीसवीं सदी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान हैं. वह एक कवयित्री, लेखिका और विचारक हैं.

प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है. होली के दिन 26 मार्च, 1907 को उत्तर प्रदेश के फ़र्रुख़ाबाद में जन्मीं महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है. वह कवयित्री होने के साथ एक विशिष्ट गद्यकार भी थीं. उनके काव्य संग्रहों में नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा शामिल हैं. गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उल्लेखनीय हैं. उनके विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध और निबंध में श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध शामिल हैं. क्षणदा उनका ललित निबंध है. उनके पुनर्मुद्रित संकलन में यामा, दीपगीत, नीलाम्बरा और आत्मिका शामिल हैं. गिल्लू उनका कहानी संग्रह है. उन्होंने बाल कविताएं भी लिखीं. उनकी बाल कविताओं के दो संकलन भी प्रकाशित हुए, जिनमें ठाकुर जी भोले हैं और आज ख़रीदेंगे हम ज्वाला शामिल हैं.

ग़ौरतलब है कि महादेवी वर्मा ने सात साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था. उनके काव्य का मूल स्वर दुख और पीड़ा है, क्योंकि उन्हें सुख के मुक़ाबले दुख ज़्यादा प्रिय रहा. ख़ास बात यह है कि उनकी रचनाओं में विषाद का वह भाव नहीं है, जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, बल्कि संयम और त्याग की प्रबल भावना है.

मैं नीर भरी दुख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा कभी न अपना होना
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी थी कल मिट आज चली

उन्होंने ख़ुद लिखा है, मां से पूजा और आरती के समय सुने सुर, तुलसी तथा मीरा आदि के गीत मुझे गीत रचना की प्रेरणा देते थे. मां से सुनी एक करुण कथा को मैंने प्राय: सौ छंदों में लिपिबद्ध किया था. पड़ोस की एक विधवा वधु के जीवन से प्रभावित होकर मैंने विधवा, अबला शीर्षकों से शब्द चित्र लिखे थे, जो उस समय की पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए थे. व्यक्तिगत दुख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा. करुणा बाहुल होने के कारण बौद्ध साहित्य भी मुझे प्रिय रहा है.

उन्होंने 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की. उन्होंने पंडित इला चंद्र जोशी की मदद से संस्था के मुखपत्र साहित्यकार का संपादन संभाला. देश की आज़ादी के बाद 1952 में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य चुनी गईं. 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया. 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट दी. इससे पहले उन्हें नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार और 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्रदान किया गया. 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारती पुरस्कार से भी नवाज़ा गया. यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादेमी फेलोशिप भी प्रदान की गई.

उन्होंने एक आम विवाहिता का जीवन नहीं जिया. 1916 में उनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज क़स्बे के निवासी वरूप नारायण वर्मा से हुआ. महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी, इसलिए पति से उनका कोई वैमनस्य नहीं था. वह एक संन्यासिनी का जीवन गुज़ारती थीं. उन्होंने पूरी ज़िंदगी सफ़ेद कपड़े पहने. वह तख्त पर सोईं. कभी श्रृंगार नहीं किया. 1966 में पति की मौत के बाद वह स्थाई रूप से इलाहाबाद में ही रहने लगीं. 22 सितंबर, 1987 को प्रयाग में उनका निधन हुआ. बीसवीं सदी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार रहीं महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान हैं. ■

किताब मिली

पुस्तक	लेखक	प्रकाशक	मूल्य
दया की देवी	राजेन्द्र रत्नेश	प्राकृत भारती अकादमी	200 रुपये

यह साध्वी यशकुंवर के पशुबलि विरोधी अहिंसक आंदोलन की गाथा है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

कार की लंबाई 4.3 मीटर है, और इस कार में 1.2 लीटर क्षमता का कापा टर्बो जीडीआई इंजन का प्रयोग किया गया है. अपनी शानदार लंबाई और बेहतरीन लुक के चलते यह कार भारतीय सड़कों पर शानदार प्रदर्शन को बेताब है.

27 मई–02 जून 2013
चौथी दुनिया

एमयूवी हेक्सा स्पेस

ह्युंडई की यह नई एमयूवी एक बेदह ही शानदार कार है. आठ सीटों वाले इस वाहन को शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा. कार की लंबाई 4.3 मीटर है, और इस कार में 1.2 लीटर क्षमता का कापा टर्बो जीडीआई इंजन का प्रयोग किया गया है.

देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ह्युंडई अपनी शानदार एमयूवी हेक्सा स्पेस को भारतीय बाज़ार में कुछ समय बाद पेश करने की योजना बना रही है. कुछ समय पहले इस एमयूवी को बीते दिनों दिल्ली ऑटो एक्स्पो में देश के सामने पेश किया गया था. कंपनी इस कार को अगले वर्ष तक बाज़ार में पेश कर देगी. जब इस कार को दिल्ली ऑटो एक्स्पो में पेश किया गया था, उस दौरान ह्युंडई मोटर इंडिया (एचएमआइएल) ने जल्द ही इस कार को बाज़ार में पेश करने की बात कही थी. इस समय कंपनी अपने रिसर्च सेंटर पर इन दोनों ही कारों के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. ह्युंडई की यह नई एमयूवी एक बेदह ही शानदार कार है. इस आठ सीटों वाले इस वाहन को शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा. इस कार की लंबाई 4.3 मीटर है, और इस कार में 1.2 लीटर क्षमता का कापा टर्बो जीडीआई इंजन का प्रयोग किया गया है. अपनी शानदार लंबाई और बेहतरीन लुक के चलते यह कार भारतीय सड़कों पर शानदार प्रदर्शन को बेताब है. हालांकि कंपनी ने अपनी इस कार की क़ीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

लूमिया 928

नोकिया ने विंडोज़ 8 फोन सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए लूमिया 928 उतारा है. नोकिया यह स्मार्टफोन वेरिज़ोन वायरलेस के साथ ला रही है. इस फोन में प्योरव्यू टेक्नोलॉजी है. नोकिया इससे पहले 808 प्योरव्यू टेक्नोलॉजी ला चुकी है. नोकिया का दावा है कि लूमिया 928 से कम रोशनी में भी बढ़िया और ब्लर-फ्री फोटो और वीडियो लिए जा सकते हैं. दरअसल, इस फोन में 8.7 मेगापिक्सल वाला वाइडऐंगल कार्लज़ेस लेंस लगा हुआ है. इसमें ज़ेनॉन फ्लैश भी लगा है. 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है, जो 720 पिक्सल के एचडी वीडियो ले सकता है. इस फोन में 1280 गुणा 768 रेजोल्यूशन वाली 4.5 इंच की एचडी ओलेड स्क्रीन भी है. इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज का ड्युल कोर क्वॉलकॉम प्रोसेसर लगा है. 1 जीबी रैम और 32 जीबी की इंटरनल मेमोरी भी है. ■

होंडा की नई फैमिली कार सेडान अमेज

देश में प्रीमियम श्रेणी की कारों का विनिर्माण करने वाली अग्रणी कंपनी होंडा कार्स इंडिया (एचसी आइएल) ने पिछले दिनों भारतीय बाजार में पेश की अपनी बहुप्रतीक्षित फैमिली सेडान होंडा अमेज. यानी अमेज के साथ ही होंडा ने भारतीय कार बाजार की डीजल श्रेणी में भी कदम रख दिया है. कंपनी ने अपनी नवीनतम आई डीटैक डीजल इंजन तकनीक से लैस अमेज को सबसे पहले भारत में पेश किया है. इसके अलावा, कंपनी ने अमेज को बेहद सफल रहे आई वीटैक पेट्रोल इंजन के साथ भी पेश किया है. विकास के बारे में होंडा मोटर कंपनी के प्रबंध अधिकारी और प्रतिनिधि (एशिया व ओशिएनिया क्षेत्र में विकास, खरीद और उत्पादन) श्री योशियुकी मात्सुमोतो ने कहा कि होंडा अमेज भारतीय बाजार में हमारा सबसे अहम रणनीतिक मॉडल है और इसका विकास खासतौर पर भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. होंडा अमेज और काम्पेक्ट आई डीटैक डीजल इंजन इंजीनियरिंग का करिश्मा है और हमें पूरा भरोसा है कि हम ग्राहकों की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे. इस अवसर पर होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी श्री हीरोनोरी कनायामा ने कहा कि होंडा अमेज के लॉन्च के साथ ही हम भारतीय बाज़ार में नए आयामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. भारतीय बाजार में अमेज को आकर्षक और किफायती कीमत पर पेश करने की खातिर हमने समयसीमा, तकनीक और लागत के मोर्चे पर कई चुनौतियों से पार पाकर बेहद आक्रामक तरीके से स्थानीयकरण पर ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि बेहतरीन पेट्रोल और डीजल तकनीक के साथ हमें पूरा भरोसा है कि हम भारत में हमारे कारोबार में खासा इज़ाफ़ा करने के लिए तैयार हैं. नई अमेज में है 1.5 एल4 सिलंडर डीओएससीआई डीटीईसी डीजल इंजन, जो इसे देश में ईंधन की सबसे कम खपत करने वाली कार बनाता है और परीक्षण के नतीजों के आंकड़ों के अनुसार यह 26.8 किलोमीटर लीटर माइलेज देती है.

होंडा अमेज का विनिर्माण एक्सीआईएल के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा संयंत्र में किया जा रहा है और इसके स्थानीयकरण का स्तर 90 फीसद से ज्यादा है. बॉडी पैनल, आई वीटैक व आई डीटैक इंजन के लिए क्रिटिकल इंजन पुर्जे और मैनुअल ट्रांसमिशन का विनिर्माण एचसीआईएल के तपुकरा संयंत्र में हो रहा है, जहां से इनकी आपूर्ति ग्रेटर नोएडा संयंत्र को की जा रही है.

गूगल ग्लास से सिरदर्द

आप गूगल ग्लास तेज रोशनी में पहनेंगे, तो आपको इस दौरान कम दिखाई देगा, जो काफी मुश्किलें पैदा करता है. गूगल ग्लास में कोई भी सेटिंग एडजस्ट नहीं की जा सकती है ...

टेक वर्ल्ड में गूगल ग्लास को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जहां पहले इसे भविष्य के अनोखे आविष्कार के रूप में देखा जा रहा था, वहीं अब इसको लेकर कुछ नकारात्मक बातें सुनने को मिल रही हैं. कुछ लोगों ने गूगल ग्लास का प्रयोग किया, तो उन्हें इसमें कई खामियां मिलीं. गूगल ग्लास का प्रयोग करने वाले एल्वोसन शॉटेल के अनुसार, गूगल ग्लासेस को पहनने के बाद आप अपने आस-पास के लोगों पर ध्यान नहीं दे सकते. इसके अलावा, इसे ज़्यादा देर तक लगाने में सिरदर्द जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है. ज़्यादा तेज रोशनी में स्क्रीन में देखना भी काफी मुश्किल हो जाता है. अगर आप गूगल ग्लास तेज रोशनी में पहनेंगे, तो आपको इस दौरान कम दिखाई देगा, जो काफी मुश्किलें पैदा करता है.गूगल ग्लास में कोई भी सेटिंग एडजस्ट नहीं की जा सकती है, जैसे वॉल्यूम कम और तेज करना, डिस्प्ले ब्राइटनेस कम करना, वाईफाई और ब्लूटूथ आनऑफ करना. इसके अलावा, आप ग्लास में साइलेंट और वाइब्रेट मोड भी नहीं लगा सकते. ■

जीपैड जी 2 फैबलेट

भारतीय बाज़ार में चाइनीज मैन्यूफैक्चरों का हमेशा से ही दबदबा रहा है फिर वह चाहे फोन ही क्यों न हो. हैंडसेट बाज़ार में इतना कड़ा मुक़ाबला होने के बावजूद चाइनीज कंपनियां नए हैंडसेट लॉन्च करने में लगी हुई हैं, जिनमें से चाइना की गियोनी ने पिछले महीने नया जीपैड जी 2 फैबलेट लॉन्च किया है, जी पैड 2 बाज़ार में 13,990 रुपए में लॉन्च किया है. ड्युल सिम सपोर्ट के साथ जीपैड 2 फैबलेट में 5.3 इंच की क्यूएचडी स्क्रीन दी गई है, जो 960540 रेज्योल्यूशन प्रोवाइड करती है. जी पैड 2 में 1.2 गीगाहर्ट का क्वॉड कोर कार्टेक्स ए 7 प्रोसेसर दिया गया है साथ में 1 जीबी रैम भी इनबिल्ड है. गियोनी ने अपने नए फैलबेट में 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया है, जिसकी मदद से आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और स्काइप में वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं. ■

डाउन टू अर्थ

दिल्ली में मोरारका ऑर्गेनिक का बारहवां फ्रेंचाइजी स्टोर खुला

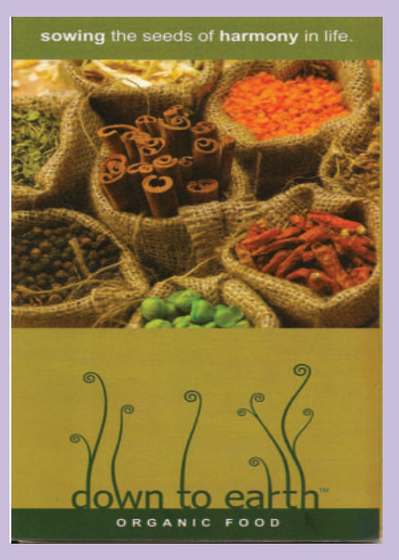

यह हम सभी जानते हैं कि खेती में इस्तेमाल हो रहे केमिकल व कीटनाशक से हमारा भोजन प्रभावित हो रहा है और इसलिए लोगों को अनेक रोगों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में ऑर्गेनिक फूड एक बेहतर विकल्प के रूप में लोगों के बीच आ रहा है. दरअसल, इन दिनों इसकी मांग तेज़ी से बढ़ने लगी है. इसी कड़ी में दिल्ली के पंजाबी बाग़ इलाक़े में मोरारका ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड का बारहवां डाउन टू अर्थ फ्रेंचाइजी स्टोर खुला. ग़ौरतलब है कि इस स्टोर में मोरारका के सभी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. दिल्ली-एनसीआर में कंपनी के कुल बीस फ्रेंचाइजी स्टोर चल रहे हैं. इस अवसर पर मोरारका ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि डाउन टू अर्थ खाद्य पदार्थों की एक बड़ी रेंज उपलब्ध करवाता है, जिनमें अनाज, दालें, मसाले, मसाला मिक्सेस, खाने के तेल, प्रोसेस्ड फूड्स, कुकीज, विभिन्न तरह की चटनियां, रोस्टेड स्नैक्स आदि शामिल हैं. एक ओर जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट एक विकराल समस्या के रूप में सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर ख़ुशी की बात यह है कि ग्राहकों के सामने ऑर्गेनिक फूड्स एक बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध है. अग्रवाल ने बताया कि डाउन टू अर्थ के सभी उत्पाद विभिन्न प्रकार की कठोरतम गुणवत्ता जांचों से होकर गुज़रते हैं, जो कि एनओपी यूएसए, भारत सरकार की एनपीओपी तथा ऑर्गेनिक प्रमाण के लिए यूरोपीय संघ आदि शामिल हैं. आज खेती में प्रयोग होने वाले कीटनाशक, उर्वरक और रसायन हमें लगातार हानि पहुंचा रहे हैं. इन दिनों गेहूं से लेकर दालों और सब्ज़ियों से लेकर फलों तक सबकी पैदावार बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ रहा है. डाउन टू अर्थ के फ्रेंचाइजी स्टोर प्योर ऐंड श्योर की संचालिका कंचन साहनी का मानना है कि शहर में लोगों में ऑर्गेनिक फूड उत्पादों के प्रति रुझान इन दिनों धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. दिल का दौरा, कैंसर, मधुमेह और तमाम दूसरी बीमारियां भी हमारे खान-पान के बदलते तरीक़ों और खाद्य पदार्थों में मिलावट से जुड़ी हुई हैं. एक सच यह भी है कि ऐसे में अब मध्यम वर्ग भी ऑर्गेनिक फूड के प्रति जागरूक होने लगा है. कंपनी दिल्ली-एनसीआर में जल्द ही 6 नए फ्रेंचाइजी स्टोर खोलने जा रही है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

एक टीम की क़ीमत एक करोड़!

क्रिकेट को टक्कर देगा बैडमिंटन

क्रिकेट को जुनून तक चाहने वाले इस देश में अब बैडमिंटन खेलने वाले युवाओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है. बैडमिंटन की लोकप्रियता का आलम यह है कि आईपीएल की तर्ज़ पर बैडमिंटन में भी अब लीग का आयोजन होने जा रहा है...

धीरेंद्र शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

बैडमिंटन में अभी तक चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग और कोरियाई खिलाड़ियों का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन अब इस क़िले में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सेंध लगा दी है. साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गट्टा, अरुंद्धति पटावने, पी कश्यप, आनंद पवार, अजय जयराम गुरु साईदत्त, सौरव वर्मा, चेतन आनंद, अनूप श्रीधर, अरविंद भट्ट जैसे शटलर देश का नाम रोशन कर रहे हैं. जहां एक ओर साइना साइना नेहवाल महिलाओं की विश्व रैंकिंग में नंबर दो पर क़ाबिज़ हैं, वहीं दूसरी ओर 17 वर्षीय नई सनसनी पीवी सिंधु करियर टॉप 20 में पहुंच गई है. हाल ही में उन्होंने चाइना मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन भी किया है. चाइना मास्टर्स में उन्होंने लंदन ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता ली झुरेई को हराया.

महिला वर्ग में नई खिलाड़ी अरुंद्धति पटावने बेशक इस समय विश्व रैंकिंग में 92 नंबर पर हैं, लेकिन भविष्य में उनमें भी काफ़ी संभावनाएं हैं. लंदन ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पी कश्यप से भी भारतीय बैडमिंटन जगत को काफ़ी आशाएं हैं. वह भले ही इंडियन ओपन सुपर सीरीज के पहले ही दौर में बाहर हो गए थे, लेकिन वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. वह विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडल्यूएफ) की रैंकिंग में छठे नंबर पर पहुंच गए हैं. भारतीय शटलर अजय जयराम 30वें और आरएमवी गुरुसाई दत्त और सौरव वर्मा 33वें और 36वें स्थान पर हैं. अभी हाल ही में संपन्न हुई इंडियन ओपन सुपर सीरीज से चर्चा में आए आनंद पवार फ़िलहाल विश्व रैंकिंग में 53वें नंबर पर हैं. दरअसल, जिस तरह से वे इस समय खेल रहे हैं, वह दिन दूर नहीं, जब वह टॉप टेन में पहुंच जाएंगे. आनंद पवार अपने पावरफुल गेम की बदौलत विश्व स्तर पर भारतीय परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है. इस टूर्नामिंट में भारतीय शटलर एचएस प्रणय ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी तौफ़ीक़ हिदायत को हराकर अपने खेल का परिचय दिया है. इसलिए उम्मीद यह जताई जा रही है कि प्रणय ऐसे ही सफल प्रदर्शन के बूते विश्व के बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे. क्रिकेट को धर्म मानने वाले इस देश में अब बैडमिंटन भी अपनी जड़े जमा रहा है. आज देश के प्रमुख शहरों में बैडमिंटन के कोचिंग सेंटर हैं. इन प्रशिक्षण केंद्रों पर युवा लड़के और लड़कियों की भीड़ उमड़ रही है. ज़ाहिर है कि इस परिदृश्य में बदलाव बीजिंग और लंदन ओलंपिक के बाद आया है. ख़ासकर लंदन ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के कांस्य पदक जीतने के बाद से बैडमिंटन की लोकप्रियता और खेलने वालों की संख्या दोनों में इज़ाफ़ा हुआ है. साइना के कोच पुलेला गोपीचंद ने भी माना कि साइना के मेडल जीतने के बाद से उनकी हैदराबाद स्थित पी गोपीचंद एकेडमी में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को एडमिशन के लिए ला रहे हैं और उन्हें मजबूरन एडमिशन बंद करने पड़े हैं.

दरअसल, बैडमिंटन को पहले लोग केवल फिट रहने और मनोरंजन के तौर पर खेलते थे, लेकिन सच तो यह है कि जब से इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के टॉप खिलाड़ियों को हराना शुरू किया है, तो ऐसे में क्रिकेट के पीछे भाग रहे युवाओं को समझ में आ गया कि इस खेल में भी बेहतर करियर बनाया जा सकता है. इस बारे में यमुना स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बैडमिंटन सिखा रहे एक कोच का कहना है कि अब उनके पास काफ़ी तादाद में लड़के-लड़कियां बैडमिंटन में करियर बनाने के लिहाज़ से सीखने के लिए आ रहे हैं. भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक तो बिखेर रहे हैं, लेकिन इस चमक को हमें लंबे समय तक क़ायम रखना ही होगा. वैसे तो हमारे पास बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन हमें इनका सही जगह, सही तरह से उपयोग करना होगा. इसलिए हमें एक ऐसा ढांचा बनाने की ज़रूरत है, जहां हमारे पास खिलाड़ियों की भरमार हो, ताकि दो-तीन खिलाड़ियों के चोटिल या ख़राब प्रदर्शन करने पर दूसरे खिलाड़ी इनकी जगह ले सकें.

भारत में बैडमिंटन का क्रेज इस क़दर बढ़ता जा रहा है कि अब क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज़ पर इसमें भी इंडियन बैडमिंटन लीग (आईबीएल) शुरू होने जा रही है. 24 जून से शुरू होकर 11 जुलाई तक चलने वाली इंडियन बैडमिंटन लीग में भारत और विदेश के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. महाराष्ट्र इस लीग का आयोजन करेगा. इस टूर्नामिंट में छह से आठ टीमें हिस्सा लेंगी. सिने अभिनेता आमिर ख़ान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इस बैडमिंटन लीग के ब्रांड अबेंसडर हैं. इस लीग के बारे में आयोजकों का कहना है कि अगर भारत में किसी प्रतियोगिता में कोई खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचता है, तो उसे औसतन इनामी राशि के रूप में 10000 रुपये मिलते हैं, लेकिन आईबीएल में उसे ढाई से तीन लाख रुपये मिलेंगे. आईबीएल की प्रत्येक फ्रेंचाइजी टीम में 12 खिलाड़ी होंगे, जिनमें से 4 विदेशी हो सकते हैं. आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) की तरह इस लीग के कामकाज के लिए भी एक संचालन परिषद (10 सदस्य) होगी. आईबीएल के लिए छह शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और लखनऊ की टीमें बनाई गई हैं. हर टीम की क़ीमत 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी क़रीब एक करोड़ रुपये रखी गई है. कहा जा रहा है कि सहारा समूह ने लखनऊ, नेस वाडिया ने मुंबई और पीवीआर वेंचर ने हैदराबाद की टीम ख़रीद ली है. आईपीएल की तर्ज़ पर ही इस लीग में भी खिलाड़ियों को नीलामी में बोली लगाकर ख़रीदा जाएगा. आयोजकों के मुताबिक़, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा ईनामी रक़म वाला बैडमिंटन मुक़ाबला होगा. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अखिलेश दासगुप्ता ने कहा है कि आईपीएल बेहद सफल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि बैडमिंटन भी इस रास्ते पर चलकर ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगा. पीवी सिंधु ने इस लीग के बारे में कहा कि 2012 ओलंपिक के बाद बैडमिंटन भारत में उफ़ान पर है. यही वजह है कि अब आईबीएल हो रहा है. मलेशिया और इंडोनेशिया ने अपने शीर्ष खिलाड़ियों के साथ इस मुक़ाबले में शामिल होने की मंज़ूरी दे दी है. साइना नेहवाल सहित पांच भारतीय खिलाड़ियों को अगले साल होने वाली 10 लाख डॉलर इनामी इंडियन बैडमिंटन लीग (आईबीएल) में छह शहर आधारित फ्रेंचाइजियों में से पांच का आइकन खिलाड़ी घोषित किया गया. साइना के अलावा, लंदन ओलंपिक में पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले पी कश्यप, विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी और उभरती हुई खिलाड़ी पीवी सिंधु को इस लुभावनी लीग का आइकन खिलाड़ी बनाया गया. साइना का आधार मूल्य 50000 अमेरिकी डॉलर तय किया गया है.

हालांकि फुर्ती और स्टेमिना के इस खेल में चीन का दबदबा है. बैडमिंटन की महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और युगल वर्ग की विश्व रैंकिंग में चीन के फ़िलहाल तीन-तीन खिलाड़ी हैं. महिला वर्ग में कुछ समय पहले चीन की छह खिलाड़ी थीं. भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का कहना है कि चीन के युवा खिलाड़ी इतने ज़बरदस्त हैं कि बाक़ी दुनिया के लिए चीन के खिलाड़ियों को हराना बहुत ही मुश्किल हो गया है. दुनिया की दूसरी नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना ने चीनी खिलाड़ियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि अगर आप एक या दो को किसी एक टूर्नामिंट में हरा भी दें, तो अगले टूर्नामिंट में कुछ दूसरे आपके सामने होंगे, तो ऐसे में उन्हें बार-बार हराना आसान नहीं है. साइना नेहवाल को हर बड़ी प्रतियोगिता में टॉप चीनी खिलाड़ियों से दो-दो हाथ करने ही पड़ते हैं. ■

बैडमिंटन को गंभीरता से लेने की ज़रूरत : साइना नेहवाल

विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर दो पर क़ाबिज़ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल से बैडमिंटन को लेकर हुई बातचीत के मुख्य अंश.

आपने बैडमिंटन खेलना कब शुरू किया?

मैंने बैडमिंटन बहुत कम उम्र से ही खेलना शुरू कर दिया था. तब मेरी उम्र सिर्फ़ नौ वर्ष की थी.

शुरू में किस तरह की परेशानियां आपके सामने आईं?

शुरू में मुझे काफ़ी कठिनाइयां आईं, लेकिन अब लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद से तो सब कुछ बदल ही गया है. कई बड़ी कंपनियां अब मुझे प्रायोजित कर रही हैं और मैं कई विज्ञापन भी कर रही हूं.

बैडमिंटन के लोकप्रिय होने के बाद भी हमारे यहां विश्व स्तर के गिने-चुने खिलाड़ी ही हैं. ऐसा क्यों?

हमारे देश में बैडमिंटन का खेल लोकप्रिय तो ज़रूर है, लेकिन यहां इस खेल को ज़्यादातर सिर्फ़ स्वास्थ्य ठीक रखने और फिटनेस बनाए रखने के लिए ही खेला जाता है. बहुत कम लोग ही ऐसे मिल पाएंगे, जो इस खेल को गंभीरता से प्रतियोगी स्तर पर खेलते हैं. किसी भी खेल को विकसित करने के लिए इसे पूरी गंभीरता से और प्रतियोगी भावना के साथ खेला जाना ज़रूरी है, तभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें बड़ी पहचान मिल सकेगी. खेल को इस ऊंचे स्तर पर ले जाए जाने के लिए बड़े और गंभीर कारगर प्रयासों की ज़रूरत है.

क्या यह बात सही है कि चीनी खिलाड़ियों से आपका सबसे कठिन मुक़ाबला होता है?

यह सही है कि चीनी खिलाड़ियों को हराना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है. फिर भी मैंने लगभग हर चीनी खिलाड़ी को अलग-अलग प्रतियोगिताओं में हराया है.

आप किस खिलाड़ी से प्रभावित हैं?

महिला बॉक्सर मैरी कॉम से बेहद प्रभावित हूं, जिन्होंने दो बच्चों की मां होने के बावजूद ज़बरदस्त दृढ़ संकल्प दिखाया और लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक भी जीता.

आप अभ्यास कैसे करती हैं?

मैंने पूरे दिन को तीन सत्रों-सुबह, दोपहर और शाम में बांटा हुआ है. हर रोज़ छह से सात घंटे तक ट्रेनिंग कर रही हूं. हमारे कुछ ट्रेनिंग कार्यक्रमों को ऑन कोर्ट और ऑफ कोर्ट कहा जाता है, जिसमें वेट लिफ्टिंग और ताक़त बढ़ाने संबंधी व्यायाम शामिल हैं. हम पूरे हफ्ते में छह दिन इसी कार्यक्रम के अनुसार काम करते हैं.

ख़ाली समय में आप क्या करती हैं?

मेरे पास ख़ाली समय बहुत कम होता है, क्योंकि मेरा अधिकांश समय प्रशिक्षण में ही बीत जाता है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

27 मई–02 जून 2013

जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन रिएलिटी शो सारेगामा के बाद कल्याणजी ने मुझे मुंबई आने की सलाह दी.

साशा ने खोला राज़!

यशराज की फिल्म औरंगजेब में सलमा आगा की बेटी साशा आगा अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी. यह उनकी पहली फिल्म है. औरंगजेब का निर्देशन अतुल सब्बरवाल कर रहे हैं, यह उनकी भी पहली फिल्म है. फिल्म में अर्जुन कपूर के अलावा मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन, अमृता सिंह, सिकंदर खेर और श्रवा भास्कर मुख्य भूमिका में हैं. साशा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनका सपना स्टार सिस्टर्स करिश्मा और करीना की तरह स्टार बनने का है. पिछले दिनों साशा ने यह राज खोला कि करीना और करिश्मा उनकी कजन सिस्टर्स हैं. दरअसल, इससे पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए जब उन्होंने ये बातें किसी पत्रकार को कही तो वो वरिष्ठ पत्रकार चौक गए. लेकिन साशा ने उन्हें समझाया कि राजकपूर जी सगे मामा थे, मेरी मम्मी के नाना के. इस लिहाज से करीना और करिश्मा मेरी कजन सिस्टर्स हैं. करीना और करिश्मा मशहूर अभिनेत्रियां हैं और उन्हें देखकर ही मुझे यह खयाल आया कि मुझे भी अभिनेत्री बनना है. अब देखना यह है कि वह करिश्मा और करीना की तरह स्टार बनती हैं या फिर अपनी मां सलमा की तरह एकाध फिल्मों के बाद कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं. गौरतलब है कि साशा आगा की नानी नसरीन आगा भी एक अभिनेत्री थीं और उन्होंने केएल सहगल के साथ फिल्म शाहजहां में काम किया था. नसरीन की मां अनवरी बेगम भी अभिनेत्री थीं और उनका निकाह जुगल किशोर मेहरा से हुआ था, जो राजकपूर केसगे मामा थे. इस लिहाज से साशा करीना और करिश्मा की दूर के रिश्ते की बहन लगती हैं. ■

श्रेया घोषाल ने कहा...

आइटम के बहाने अश्लील गाने कभी नहीं गाऊंगी

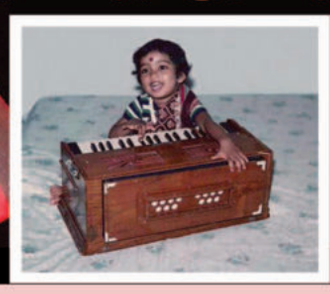

कोई भी इंसान सफल तभी होता है, जब वह समय और परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है. सुरों की मल्लिका श्रेया घोषाल का कहना है कि उन्होंने ख़ुद को ऑडियंस के डिमांड के मुताबिक अब ढाल लिया है. सच तो यह है कि श्रेया की आवाज़ दिल को सुकून पहुंचाती है. आज की फिल्मों की एक बहुत बड़ी डिमांड है आइटम सॉन्ग्स. यही वजह है कि एक तरफ उन्होंने देवदास का सिलसिला ये चाहत का..., ऐ मेरी जिंदगी..., चलो तुमको लेकर चलें...जैसे गीतों से लोगों को दिवाना बनाया, तो वहीं दर्शकों के आइटम सॉन्ग्स के प्रति बढ़ते क्रेज को देखते हुए उन्होंने ओ बलमा..., ऊ ला ला..., चिकनी चमेली..., चलाओ ना नैनों से बाण रे..., तेरा इश्क बड़ा तीखा...जैसे गाने भी गाए. लेकिन वह कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आइटम के नाम पर अश्लील गाने कभी नहीं गाएंगी, श्रेया ने कहा, और अगर ऐसे मौके आए, तो मैं उन गीतों को ठुकराने से परहेज भी नहीं करूंगी. हाल ही में एक रियालिटी शो के सिलसिले में दिल्ली आईं श्रेया घोषाल की चौथी दुनिया की संवाददाता *प्रियंका प्रियम तिवारी* से हुई बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश :

हर वर्ग के लोगों की आप पसंद हैं, पहले और अब के गानों के बारे में आप क्या कहेंगी.

पुराने दौर के संगीत की बात करें, तो तब संगीत में मेलोडी थी. ख़ासकर रोमांटिक मेलोडी, लेकिन आज के गीतों में वह बात, वह कशिश नहीं है. पहले के गानें दिल को छू लेने वाले होते थे, लेकिन आज के गानों में उस स्तर की मेलोडी नहीं होती है. वैसे, दरअसल, तब अच्छे गीतकार भी थे. हालांकि अच्छा लिखने वाले आज भी हैं, लेकिन एक सच तो यह भी है कि उनसे काम नहीं लिया जा रहा है. इसकी वजह यह है कि फिल्मकारों को लगता है कि आज के समय में तड़कते–भड़कते गाने ही लोगों को पसंद आ रहे हैं, शायद इसीलिए वैसे गीत न केवल लिखे, बल्कि गाए भी जा रहे हैं.

एक गायिका के रूप में कौन–सी बात आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है ?

जब मैं बाहर जाती हूं किसी मॉल में, पार्टी में, शादियों में और देखती हूं कि लोग मेरे गीतों को एंज्वाय कर रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती है.

आपको लगता है कि समय की मांग के मुताबिक हॉट सॉन्ग्स गाना अब गायकों की मजबूरी बन गई है?

हां, आप यह कह सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यह किसी चैलेंज से कम नहीं है. यह काफी मुश्किल काम है. अच्छे मेलोडी वाले सॉन्ग्स आप दिल से गाते हैं, जबकि ऐसे गीत, जिनमें न समझ आने वाले शब्द हों, बिना भाव वाले वाक्य हों, उन पर गाना और यह भी उम्मीद करना कि वह सबको पसंद आए, वाकई मुश्किल काम है. 3 मीनट का गीत या तो छा जाता है, या फिर एकदम बाहर हो जाता है, यानी तुरंत खारिज हो जाता है. दरअसल, अब वह ट्रेंड बिल्कुल नहीं रहा, जब कोई गीत धीरे–धीरे लोगों की जुबान पर आता था और फिर उसे सुना जाता था.

क्या आप भी इस तरह के गीत गाएंगी?

नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी. मैंने कुछ गानों को तो गाने से इंकार भी कर दिया है. हर चीज की एक सीमा होती है. सच तो यह है कि जिन गानों के साथ मैं सहज महसूस नहीं कर सकती, उन गानों को मैं नहीं गा सकती.

आप कई अन्य भाषाओं बांग्ला, असमी, राजस्थानी, तेलुगू में भी गाती हैं?

जी हां, मैं कई भाषाओं में गा सकती हूं, क्योंकि हर भाषा को मैं एंज्वाय करती हूं. मैं बांग्लाभाषी हूं, इसलिए घर में बांग्ला में ही बोलती हूं. चूंकि राजस्थान में मेरी परवरिश हुई है, इसलिए यहां के लोकसंगीत और जीवन से मैं भलीभांति परिचित हूं. मुझे दूसरी भाषाओं से भी गाने का ऑफर मिल रहा है. हां, जो भाषा मैं नहीं जानती, उसके साथ थोड़ी समस्या मुझे ज़रूर होती है, लेकिन लगातार कोशिश करने से कोई भी काम असंभव नहीं होता. भारतीय फिल्मों में बहुत–सी धुनें और गीत लोकसंगीत से ही प्रभावित होते हैं.

ऐसे कौन से गीत हैं, जिन्हें आप गाना चाहेंगी?

कोई एक नहीं, ऐसे बहुत से गाने हैं, जिन्हें मैं गाना चाहूंगी. उनमें से कुछ हैं, बहारों मेरा जीवन भी संवारो..., माई री कासे कहूं..., हमारी याद आएगी..., किस तरह भूलेगा दिल..., ये जिंदगी उसी की है..., मेघा छाए आधी रात..., इन आंखों की मस्ती के..., पिया तोसे नैना लागे रे..., ये सब गाने आज भी मेरे पसंदीदा हैं, जो मेरे मन को छू लेते हैं.

आपकी जिंदगी का वह पल, जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी?

जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन रिएलिटी शो सारेगामा के बाद कल्याणजी ने मुझे मुंबई आने की सलाह दी. और दरअसल, इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई. इसके बाद जिस पल मुझे फिल्म देवदास में पारो की आवाज के लिए चुना गया, वह पल वाकई मेरे जीवन का सबसे यादगार पल था. सच तो यह है कि इसके बाद मेरा जीवन और इसके मायने ही बदल गए. हालांकि मैं हर गीत को अपने लिए एक नया अवसर मानती हूं. दरअसल, मेहनत, लगन, भक्ति ही किसी भी इंसान को इस उचाई पर बैठाती है. मेरी मेहनत और मां पापा के आशीर्वाद के कारण ही मैं यहां तक पहुंच पाई हूं.

फिल्मों में लोगों की पसंद लगातार बदलती रहती है. कुछ समय पहले सूफी गीत चलन में थे, लेकिन आजकल आइटम सॉन्ग की डिमांड है. आगे कैसे गीत चलन में होंगे?

मुझे लगता है कि लोग शायद फिर से रोमांटिक गीतों को सुनना पसंद करेंगे. वैसे, ड्यूट सांग बहुत सुने जा रहे हैं इन दिनों. मैं अपने शो में भी देखती हूं कि ज्यादातर फरमाइशें रोमांटिक गीतों को लेकर ही होती हैं.

किस तरह के गाने आप गाना पसंद करती हैं?

मैं हर तरह के गाने गाती हूं, ठुमरी से लेकर क्लब नंबर तक, लेकिन मुझे इमोशनल और दिल को छू जाने वाले गाने ज्यादा लुभाते हैं.

आप एक रिएलिटी शो से आई हैं. इस तरह के शो के बारे में आप क्या सोचती हैं?

जब मैंने टैलेंट हंट शो में हिस्सा लिया था, तब ये शो इतने ऑडियंस बेस्ड नहीं होते थे. आजकल टैलेंट हंट शो के चलते ही प्रतियोगी रातोंरात पॉपुलर हो जाते हैं. खुद फिल्म इंडस्ट्री भी नए–नए टैलेंट को ढूंढती रहती है. इन टैलेंट हंट शो में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी अगर मेहनत करें, तो वे अपना करियर खुद बना सकते हैं.

भविष्य के लिए आपकी योजना क्या है?

जिंदगी में हमेशा गाती रहूं, यही मेरी योजना और तमन्ना है. दरअसल, मैं समाज के लिए अच्छा करना चाहती हूं, इसीलिए अभी एक अच्छे मीडियम की तलाश में हूं. ■

...और लता जी की बात सच हुई

श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को बहरमपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था. उनका बचपन राजस्थान कोटा के पास एक छोटे से कस्बे रावतभाटा में बिता. पिता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नाभिकीय ऊर्जा संयत्र इंजीनियर के रूप में काम करते हैं. मां साहित्य में स्नातकोत्तर हैं. चार साल की उम्र में श्रेया ने अपनी मां के साथ हारमोनियम सीखना शुरू किया. संगीत के प्रति उनके लगाव को देखते हुए उनके माता–पिता ने उन्हें कोटा में महेशचंद्र शर्मा के पास शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजा. सारेगामा में उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कल्याणजी ने उन्हें मुंबई में आकर रहने के लिए कहा. श्रेया ने 18 महीने तक कल्याण जी से संगीत की शिक्षा ली. श्रेया एक प्रतियोगी के रूप में जीटीवी के शो सारेगामा से सुर्खियों में आई थीं. तब वह छोटी–सी बच्ची थी. उस दौरान शो के जज कल्याण जी थे और कार्यक्रम की मेजबानी की थी सोनू निगम ने. लता जी ने श्रेया के अद्भूत प्रतिभा को देखकर तभी कहा था कि यह बच्ची काफी आगे जाएगी. लता जी की बात सच साबित हुई और श्रेया आज सर्वश्रेष्ठ गायिकाओं में गिनी जाती हैं. वह अपनी पहली ही फिल्म के बाद स्टार बन गईं. हुआ यह कि जब दूसरी बार उन्होंने सारेगामा में भाग लिया, तब वह वयस्क हो चुकी थीं. तब संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म देवदास की तैयारी में लगे थे. उन्होंने श्रेया को सारेगामा में सुना और उन्हें देवदास के पारो, जिसकी भूमिका ऐश्वर्या राय निभा रही थीं, की आवाज के लिए चुन लिया. देवदास के गाने के लिए उन्हें उस साल केसर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी दिया गया. गौरतलब है कि उसी साल उभरती हुई गायिका का आरडी बर्मन पुरस्कार भी उन्हें दिया गया.

यशराज के लिए गाएंगे आयुष्मान

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना यशराज फिल्म्स की नई फिल्म में एक गीत गाने वाले हैं. वह इससे पहले भी कई फिल्मों में गा चुके हैं. वह पानी दा रंग...और साड्डी गली आजा... जैसे गीत गा चुके हैं. जॉन की फिल्म विक्की डॉनर में उन्होंने पहली बार गाया था, जबकि दूसरी फिल्म नौटंकी साला के लिए दो गीत साड्डी गली... और तू ही तू... गा चुके हैं. फिल्म में सोनम कपूर और ऋषि कपूर भी बतौर कलाकार शामिल हैं. पिछले दिनों एक मुलाकात के दौरान उन्होंने चौथी दुनिया से बहुत कुछ शेयर किया. खासकर अपने परिवार के बारे में. उन्होंने भारतीय सिनेमा में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारी फिल्मों की कहानियों और विषयों के साथ ही साथ फैशन में भी उल्लेखनीय बदलाव आए हैं. चाहे वह अमिताभ जी के जमाने का बेलबॉटम पैंट हो, या जितेंद्र जी के जमाने का चुस्त पैंट. सच तो यह है कि सिनेमा हमेशा से ही फैशन को बढ़ावा देता आया है और इसी वजह से हम भी फैशन से प्यार करते हैं. अपनी हालिया रिलीज फिल्म नौटंकी साला के बारे में उन्होंने कहा कि इसे दर्शकों की मिली–जुली प्रतिक्रिया मिली है. वह कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं, क्योंकि उनके अभिनय की, जिन लोगों ने फिल्म देखी, तारीफ की. आयुष्मान ने कहा, मैंने नौटंकी साला के किरदार के लिए काफी मेहनत की. मेरे और कुणाल रॉय कपूर के बीच की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चंडीगढ़ में उनकी परवरिश जरूर हुई, लेकिन बाद में वह अपनी ऐक्टिंग की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वह मुंबई में आ गए. यहां उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी. परिवार के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अपने एक साल के बेटे विरजर के साथ चंडीगढ़ में ही रहती हैं. बातों ही बातों में आयुष्मान ने बताया कि उन्हें अपने परिवार की न केवल याद बहुत आती है, बल्कि कई बार उनकी यह इच्छा भी होती है कि वह पत्नी ताहिरा और अपने बेटे के साथ ही मुंबई में रहें, लेकिन चूंकि उनकी पत्नी अपने पैतृक शहर में पीएचडी कर रही हैं और वह भी अपने काम में काफी व्यस्त रहती हैं, इसलिए आयुष्मान नहीं चाहते कि पत्नी की पढ़ाई में कोई बाधा आए! ■

जस्टिन के साथ खुश हूं : सेलेना

हॉलीवुड की चर्चित गायिका और अदाकारा सेलेना गोमेज 56 शहरों के विश्व दौरे पर 14 अगस्त से निकलेंगी. इसमें खास बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत वह अपने ब्वायफ्रेंड जस्टिन बीबर के गृह प्रदेश से शुरू करेंगी. वे और जस्टिन दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर हैं. सेलेना कहती हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे जस्टिन जैसा शख्स मिला. दोनों कलाकार पिछले एक साल से दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं. हालांकि 17 वर्षीय बीबर का कहना है कि शादी की जिम्मेदारी निभाने के लिए वह काफी छोटे हैं और युवा होने के बाद ही परिवार बनाने के बारे में सोचेंगे. सेलेना कहती हैं कि मैं अपने पूर्व के रिश्तों में इतनी खुश नहीं थी, जितनी मैं बीबर के साथ खुशी महसूस कर रही हूं. वहीं बीबर का भी कुछ यही हाल है. बीबर और सेलेना का कुछ दिनों पहले बलगाव हो गया था. इस रिश्ते के टूटने का दर्द उनके संगीत में भी दिखा. उस दौरान बीबर ने एक गाना भी लिखा. इस गाने के बोल हैं– नथिंग लाइक अस, नथिंग कैन एवर, एवर रिप्लेस यू, नथिंग कैन मेक मी फील लाइक यू डू...गेव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग आई हैड टू गिव, गर्ल, वाई वुड यू पुश मी अवे?, एट द एंड ऑफ द डे, देयर इज नथिंग लाइक अस, यू नो? दैट्स जस्ट इट, इट इस वाट इट इस. पीपल आर गोइंग टू रिलेट टू दैट. नथिंग लाइक. वहीं उनका एक और गाना बी ऑलराइट भी गोमेज को लेकर ही था. ■

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

27 मई–02 जून 2013

www.chauthiduniya.com

नीतीश को जाना होगा : लालू

पटना के गांधी मैदान में जुटी भीड़ ने यह एहसास करा दिया है कि आज भी लालू प्रसाद यादव का जादू बरक़रार है. रैली की कामयाबी से उत्साहित लालू का कहना है कि अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि नीतीश की सरकार जाने वाली है. क्या वाक़ई इतनी आसान है लालू की राह?

सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

चिलचिलाती धूप में अगर लगभग डेढ़ लाख लोग किसी नेता को सुनने के लिए घंटों इंतज़ार करते रहें, तो इसे उस नेता का जादू ही कहा जाएगा. न पानी का मुकम्मल इंतज़ाम और न ही बैठने की सही व्यवस्था. फिर भी लालू प्रसाद ज़िंदाबाद के नारों से पूरे गांधी मैदान को गुंजा देने का जज्बा रखने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की फ़ौज लालू के साथ है, जो उनकी एक आवाज़ पर कुछ भी कर गुज़रने को तैयार है. पटना के गांधी मैदान में राजद की परिवर्तन रैली में ऐसे ही समर्थकों को देखकर लालू प्रसाद गदगद थे. उन्होंने कहा कि आप अपने साधन से आए और इस चिलचिलाती धूप में मेरे लिए ज़िंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं. मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि नीतीश कुमार की सरकार जाने ही वाली है. इस लिहाज़ से कहा जाए, तो बिहार की सियासी ज़मीन पर जिस राजनीतिक ऑक्सीजन की दरकार लालू प्रसाद सत्ता से बेदख़ल होने के बाद महसूस कर रहे थे, उसे उन्होंने रैली की मार्फ़त बहुत हद तक हासिल कर लिया है.

भीड़ के लिहाज़ से देखा जाए, तो यह रैली जदयू की अधिकार रैली के बराबर थी. इस नज़रिए से यह राजद के लिए राहत की बात है. लेकिन जिस सामाजिक ताने-बाने की बात लालू प्रसाद पिछले दिनों करते रहे हैं, उसकी झलक रैली में नहीं दिखी. जो लोग आए, उनमें अधिकांश लालू प्रसाद की बिरादरी के थे. हालांकि मुसलमानों की संख्या ठीक-ठाक ही थी. दरअसल, रैली ने एक बार फिर साफ़ कर दिया कि लालू प्रसाद का माय समीकरण आज भी बरक़रार है. लेकिन इसके अलावा, वह जिस सामाजिक समूह को जोड़ने की बात कर रहे थे, उसकी कमी रैली में साफ़ दिखी. हालांकि लालू प्रसाद घूम-घूमकर यह कहते रहे हैं कि राजद से कुछ ग़लतियां हुईं और उन ग़लतियों को अब दोहराया नहीं जाएगा. लेकिन लगता है कि लालू प्रसाद की इस अपील का कुछ ख़ास असर दूसरी जातियों पर फ़िलहाल नहीं हुआ है. उनकी उपस्थिति थी, पर वह उनके अपने निजी कारणों से. दरअसल, यही वह खेल है, जिसे लालू प्रसाद जीतना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले ज़ख़्म इतने गहरे हैं कि भर ही नहीं रहे हैं. रैली में भाषण के दौरान इसका एहसास लालू प्रसाद को हुआ भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे राज में ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या नहीं हुई. मैंने सीबीआई जांच की मांग की है. कुछ लोगों ने मुझे और मेरी पार्टी को बेवजह बदनाम किया. लेकिन मैं एक बार फिर आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अगर सत्ता में आए, तो सभी का बराबर सम्मान होगा. लालू इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि केवल माय के भरोसे सत्ता पर क़ब्ज़ा होना मुश्किल है. अति पिछड़ा वोट उनके पाले से खिसक चुका है. ऐसे में अगड़ी जातियों को शामिल किए बिना बात नहीं बनेगी. कम से कम परिवर्तन रैली में इन बिरादरियों को लाने में वह सफल नहीं हो पाए. इसलिए इस मोर्चे पर अभी उन्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है. इस पर काम पार्टी ने शुरू कर दिया है. राजद के रणनीतिकार जल्द ही बड़े स्तर पर इन जातियों का सम्मेलन कर सकते हैं. फ़िलहाल महाराजगंज उपचुनाव में राजपूतों को एकजुट कर अपने पाले में करने के लिए मोर्चाबंदी कर दी गई है. भले ही इसमें प्रभुनाथ सिंह का नाम काम आ रहा है. लेकिन शायद लंबे अरसे बाद महाराजगंज में राजपूत व यादव एक साथ एक उम्मीदवार को वोट गिराते नज़र आएं, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ, तो फिर राजद पूरे सूबे में राजपूतों के अलावा दूसरी जातियों को भी लुभाने के लिए एड़ी और चोटी का ज़ोर लगा देगा.

जनाधार को विस्तार देने के लिए लालू प्रसाद ने युवाओं को पचास फ़ीसद टिकट देने की बात भी रैली में दोहराई. अगले विधानसभा चुनाव तक लालू प्रसाद सत्तर साल के हो जाएंगे. ऐसे में अगर वह अपने बेटे को सामने ला रहे हैं, तो इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है. वह जानते हैं कि ज़माना युवाओं का है, इसलिए लकीर पीटने से बात बनेगी नहीं. संकेत यही है कि आलोचनाओं की परवाह किए बग़ैर वह आने वाले दिनों में अपने बेटों को धीरे-धीरे बड़ी ज़िम्मेदारियां देंगे. वह अपने स्कूल में ही अपने बेटों को राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ताकि चूक की गुंजाइश न के बराबर रहे. अब यह उनके बेटों पर है कि वे कितना आगे निकल पाते हैं, क्योंकि राजनीति की दौड़ में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता. परिवर्तन रैली से लालू प्रसाद को संगठन के स्तर पर एक लाभ ज़रूर हुआ. विधानसभा के लिए दो बार चुनावी शिकस्त खाने के बाद राजद के कार्यकर्ता सुस्त पड़ गए थे. पार्टी केवल बयान देने तक ही सीमित रह गई थी. विधानसभा में संख्या बल कम रहने के कारण भी लाचारी की स्थिति थी. ऐसे में इस रैली ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया. लोग अपने साधन से आए और नेता को सुनने के लिए घंटों धूप में खड़े रहे. हालांकि लालू ने उन्हें निराश भी नहीं किया. उन्होंने कहा कि जल्द ही नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. वह यह जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को बरक़रार रखने के लिए उन्हें आंदोलन करना ही होगा. उन्होंने अपने भाषण में नियोजित शिक्षकों के ज़ख़्मों पर भी मरहम लगाया. उन्होंने कहा कि सत्ता में आए, तो सबको नियमित कर देंगे. नीतीश कुमार को आरएसएस का तोता कहकर उन्होंने मुसलमानों को यह संदेश दिया कि वे किसी भ्रम में नहीं रहें. लालू ने हमेशा सांप्रदायिक ताक़तों को कुचलने का काम किया है और मरते दम तक वह अपने क़दम पीछे नहीं खींचेंगे. रैली में लालू प्रसाद के लिए एक अच्छी बात यह भी रही कि बिहार के सभी ज़िलों से लोग इसमें आए.

> **जनाधार को विस्तार देने के लिए लालू प्रसाद ने युवाओं को पचास फ़ीसद टिकट देने की बात भी रैली में दोहराई. अगले विधानसभा चुनाव तक लालू प्रसाद सत्तर साल के हो जाएंगे. ऐसे में अगर वह अपने बेटे को सामने ला रहे हैं, तो इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है. वह जानते हैं कि ज़माना युवाओं का है, इसलिए लकीर पीटने से बात बनेगी नहीं. संकेत यही है कि आलोचनाओं की परवाह किए बग़ैर वह आने वाले दिनों में अपने बेटों को धीरे-धीरे बड़ी ज़िम्मेदारियां देंगे. वह अपने स्कूल में ही अपने बेटों को राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ताकि चूक की गुंजाइश न के बराबर रहे. अब यह उनके बेटों पर है कि वे कितना आगे निकल पाते हैं, क्योंकि राजनीति की दौड़ में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता.**

राजद नेता विनोद चौधरी कहते हैं कि यही तो लालू प्रसाद का जादू है. कोने-कोने से लोग उनके बुलावे पर चले आए. पार्टी राज्य परिषद के सदस्य और कानू समाज के बड़े नेता गोपाल गुप्ता कहते हैं कि लालू प्रसाद ने कानू समाज को जो सम्मान दिया है, उसके लिए यह समाज उन्हें हमेशा दिल से धन्यवाद देता रहा है. उनके बुलावे पर पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में कानू समाज के लोग गांधी मैदान में जमा हुए थे. आगे जो भी आदेश होगा, उसका पालन होगा. कोसी के युवा राजद नेता अजय सिंह मानते हैं कि तेजप्रताप व तेजस्वी यादव को लेकर युवाओं में ज़बरदस्त आकर्षण है और बिहार के युवा चाहते हैं कि दोनों आगे आकर राजद की नीतियों को मज़बूत करें और ग़रीबों, दलितों व अल्पसंख्यकों की समस्याओं से रूबरू हों. राजद के नेता जो भी कहते हों, पर नीतीश कुमार ने रैली को लेकर दिलचस्प बयान देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में राज्यहित के काम में लगे थे, इसलिए उन्हें रैली की कोई जानकारी नहीं है. अब कोई उनकी इस बात पर कैसे भरोसा कर सकता है कि राज्य के मुखिया को पटना के गांधी मैदान में हुई रैली की जानकारी न हो. राजद नेता सम्राट चौधरी कहते हैं कि दरअसल, नीतीश कुमार रैली की सफलता से घबरा गए हैं. अहंकार में चूर नीतीश कुमार को पता ही नहीं चल रहा है कि सूबे के कोने-कोने में उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नाराज़गी है. परिवर्तन रैली में तो लोगों ने केवल इसकी छोटी-सी झांकी दिखलाई है. इसके तुरंत बाद महाराजगंज उपचुनाव में नीतीश कुमार को लालू प्रसाद की राजनीतिक ताक़त का अंदाज़ा लग जाएगा. महाराजगंज में इसकी बानगी दिखने भी लगी है. रैली के बाद राजद के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं. प्रभुनाथ सिंह पूरे इलाक़े में घूम-घूमकर ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव मर्द की तरह लड़ा जाएगा. राजपूत व यादव एक साथ वोट करने की क़समें खा रहे हैं. जितेंद्र स्वामी की उम्मीदवारी पर प्रभुनाथ सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार के इशारे पर जितेंद्र स्वामी को खड़ा किया गया है. लेकिन कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा. श्री स्वामी वोटकटवा की भूमिका में ही रह जाएंगे. लालू प्रसाद का यहां ज़बरदस्त प्रभाव है और हर जात व बिरादरी के लोग राजद को वोट देंगे. नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए वह कहते हैं कि उन्होंने बिहार की भोली-भाली जनता को ठगने के अलावा और कोई काम ही नहीं किया है. महाराजगंज की जनता इस बार नीतीश कुमार को करारा सबक़ सिखाएगी. पी के शाही को डमी उम्मीदवार बतलाते हुए प्रभुनाथ सिंह कहते हैं कि दरअसल, यहां पूरी नीतीश सरकार चुनाव लड़ रही है. लेकिन जनता की ताक़त के सामने पूरी सरकार बौनी साबित होगी. परिवर्तन रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि जनता अब इस शासन से ऊब चुकी है और नीतीश सरकार को जाना ही होगा. कहा जाए, तो प्रभुनाथ सिंह के इन दावों को परिवर्तन रैली की सफलता से ताक़त मिल रही है. उधर, भाजपा नेता व सांसद सी पी ठाकुर ने परिवर्तन रैली को सफल बताकर हवा में कई तीर छोड़ दिए. लालू प्रसाद के लिए यह करो या मरो वाली रैली थी और उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनमें अभी बहुत दम बाक़ी है. लेकिन यह भीड़ वोट में कैसे तब्दील होगी, इस पर लालू प्रसाद व उनके साथियों को गंभीर चिंतन करना चाहिए. चूंकि इसी मोर्चे पर राजद कमज़ोर होता जा रहा है. उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद व उनके साथी इस कमज़ोरी को दुरुस्त कर लेंगे, ताकि नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ चुनावी गोल दाग़ा जा सके. ■

पिछले क़रीब तीन दशकों से बिहार झारखंड की सीमावर्ती इलाक़े में माओवादियों की सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है.

चतरा के कुंद थाना के लकड़मंदा जंगल में हुई मुठभेड़ में माओवादियों के दस्ते ने टीपीसी के दस्ते पर हमला कर दिया.

खगड़िया ज़िला अध्यक्ष पद पर अनुभवहीन महिला की नियुक्ति पर सियासत शुरू

कहीं गरम, कहीं नरम

एक ओर जहां जदयू के जिलाध्यक्ष पद पर एक महिला के आसीन होने से कई नेता दुखी हैं और मानते यही हैं कि इससे पार्टी पर असर पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि इससे महिलाएं पार्टी के साथ जुड़ेंगी.

मनेंद्र कुमार feedback@chauthiduniya.com

अशोक सिंह | साधना देवी | बिंदेश्वरी सिंह | सोने लाल मेहता | सुनील कुमार | राज कुमार फोगला

जदयू प्रदेश नेतृत्व ने खगड़िया ज़िले में पार्टी में हो रही गुटबाज़ी को विराम देते हुए ज़िला अध्यक्ष पद पर एक महादलित महिला की ताजपोशी कर सभी बड़े नेताओं को आश्चर्य में डाल दिया है. ऐसे में चर्चा हो रही है कि आख़िर प्रदेश जदयू की क्या मजबूरी थी कि तेज़-तर्रार नेताओं को कमान न देकर एक अनुभवहीन महिला को ज़िले की कमान दे दी. इस मनोनयन की वजह से ज़िले में भले ही फ़िलहाल जदयू की राजनीति पर गुटबंदी के माहौल पर विराम लग गया है, लेकिन याद रहे कि भविष्य में यह चुनावी परिणाम पर असर डाल सकती है.

ग़ौरतलब है कि जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर गुटबाज़ी का दौर कई महीनों से चल रहा था. ज़िला अध्यक्ष पद के लिए समता पार्टी का जनाधार खड़ा करने वाले खगड़िया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह मथुरापुर के पूर्व मुखिया अशोक सिंह का नाम चर्चा में था, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी को विकास की उम्मीद थी. इतना ही नहीं, सांसद दिनेश चंद्र यादव का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था, लेकिन अचानक आए बदलाव के कारण इस संभावना को अंततः ख़ारिज कर दिया गया. माना जाता है कि अशोक सिंह की अपनी बिरादरी में अच्छी पकड़ है, क्योंकि वह बुरे समय में भी नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी नहीं हो पाई. वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष सोनेलाल मेहता की पार्टी पर पकड़ मज़बूत होने के कारण वह लगातार कई वर्षों से इस पद पर क़ाबिज़ थे, लेकिन इस बार उनका सिक्का नहीं चल पाया. बेलदौर विधायक पन्ना लाल पटेल तथा अलौली विधायक रामचंद्र सदा उनके पक्षधर थे और पुनः उन्हें जिलाध्यक्ष बनाने की जुगत में थे. दरअसल, उनके नेतृत्व में पार्टी ने ज़िले का काफ़ी विकास किया. लोकसभा एवं विधानसभा के तीन सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता एवं पार्टी जनाधार को मज़बूत किया. मेहता का कहना है कि मेरे नेतृत्व में पार्टी का विकास हुआ है और ज़िले में जदयू का जनाधार भी बढ़ा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ज़िला परिषद उपाध्यक्ष सुनील कुमार का कहना है कि पार्टी पर मेरी पकड़ मज़बूत है, क्योंकि मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया था. मैं आमजन के समर्थन से ज़िला परिषद सदस्य पद से चुनाव जीत कर उपाध्यक्ष पद पर क़ाबिज़ हुआ. अब यदि उनकी बातों पर ग़ौर किया जाए, तो ज़िले में जदयू की राजनीति गरम है. यदि सांसद दिनेश चंद्र यादव की बात की जाए, तो वह राजनीतिक दाव-पेंच के माहिर खिलाड़ी हैं. उनकी पहचान कोसी क्षेत्र में न केवल एक दमदार नेता के रूप में है, बल्कि उनका गुट भी खगड़िया में सक्रिय है. उनके सभी कार्यक्रमों में अशोक सिंह, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष सुनील कुमार, नगर उपसभापति राजकुमार फोगला, प्रदेश महासचिव अरुण कुमार यादव, शंभू झा और दीपक सिन्हा उपस्थित थे. बता दें कि ये सांसद के चहेते माने जाते हैं. वह इन्हीं गुटों में से किसी एक को अध्यक्ष पद पर क़ाबिज़ करना चाहते थे. आख़िर तमाम राजनीतिक गुटबाज़ी को एक तरफ़ रखकर प्रदेश नेतृत्व द्वारा नए चेहरे को कमान देकर सभी को पुनः एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोकसभा चुनाव में चुनावी गणित बिगड़ न पाए, लेकिन यदि कमज़ोर नेतृत्व हुआ, तो पार्टी की बड़ी चूक को भुगतना पड़ेगा.

ग़ौरतलब है कि ज़िले के सातों प्रखंडों में एक ही जाति के लोगों का प्रखंड अध्यक्ष पद पर क़ाबिज़ होना कई नेताओं को खल रहा है. वे चाहते हैं कि दूसरे जाति के लोगों को भी यह पद मिले, ताकि जातीय समीकरण सामान्य रहे. हालांकि इन गुटों के आरोप-प्रत्यारोप पर विराम लगाते हुए पार्टी को मज़बूत करने का प्रयास किया जा रहा है. किसान प्रकोष्ठ के ज़िला कार्यालय के उद्घाटन के दिन सभी गुटों के नेताओं ने एक साथ उपस्थित होकर प्रकोष्ठ को मज़बूत करने का संकल्प लिया. इससे पता चलता है कि एकजुट होने के कारण किसी तीसरे की ताजपोशी हो जाना गुटबंदी का ही कारण है. किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को उठाया जाएगा एवं निदान करने का प्रयास भी किया जाएगा. इसीलिए मेरा संगठन मज़बूत हुआ है, जबकि बिंदेश्वरी सिंह की ज़िले में एक अलग पहचान है. वह मज़बूत नेता के रूप में उभर कर आए हैं. वहीं वर्तमान जिलाध्यक्ष साधना देवी का कहना है कि नीतीश जी ने मुझ पर यक़ीन दिखाया है. उनके इस विश्वास की ख़ातिर अपनी जान की बाज़ी लगाने से भी पीछे नहीं हटूंगी. वहीं जदयू नेता पंकज गुप्ता कहते हैं कि ज़मीनी नेताओं को दरकिनार कर एक महिला को अध्यक्ष बनाने से पार्टी संगठन पर प्रभाव पड़ेगा. नगर पंचायत उपसभापति राजकुमार फोगला का कहना है कि साधना देवी के अध्यक्ष बनने से पार्टी को मज़बूती मिलेगी. उनका चयन सोच-समझकर किया गया है तथा महिला आरक्षण का लाभ भी उन्हें मिला है. तमाम नेताओं की बातों पर ग़ौर करें, तो आने वाले दिनों में पार्टी को एकजुट रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. ■

ख़ूनी संघर्ष तेज़ होने के आसार

सरकार अंकुश लगाने में नाकाम!

बिहार-झारखंड सीमा क्षेत्र में माओवादी और टीपीसी के वर्चस्व की लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं. जनता इन दिनों आतंक के साए में जी रही है और सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है. पढ़िए चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और इससे अलग हुई तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) के बीच वर्चस्व की लड़ाई में क़रीब एक दर्जन शीर्ष माओवादी नेताओं के मारे जाने के कारण पुलिस ने भले ही राहत की सांस ली है, लेकिन बिहार-झारखंड की सीमा क्षेत्र के लोग अब भी दहशत में हैं. यहां के लोगों का मानना है कि नक्सलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ख़ूनी संघर्ष और तेज़ हो सकता है. मालूम हो कि माओवादी और टीपीसी के वर्चस्व की लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं. इस बार माओवादियों को अपने ही क्षेत्र में दर्जन से अधिक शीर्ष नेताओं के मारे जाने की घटना ने हिला कर रख दिया है. झारखंड के चतरा ज़िले के कुंदा थाना क्षेत्र में माओवादियों और प्रतिद्वंद्वी नक्सली संगठन टीपीसी के बीच हुई ख़ूनी भिड़ंत में क़रीब 15 लोग मारे गए, जिनमें से पुलिस ने 10 शव बरामद किए थे. ये सभी शव भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं के थे. चतरा के कुंद थाना के लकड़मंदा जंगल में हुई मुठभेड़ में माओवादियों के दस्ते ने टीपीसी के दस्ते पर हमला कर दिया. इस हमले में टीपीसी का एक सदस्य अमरेश पाल मारा गया. इसके बाद माओवादियों के प्रतिद्वंद्वी टीपीसी के दस्ते ने भी माओवादियों को घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें माओवादियों के शीर्ष नेता मारे गए. इसमें भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर ललेश यादव उर्फ़ प्रशांत उर्फ़ परमजीत उर्फ़ छोटे साहब, जोनल कमांडर धर्मेंद्र उर्फ़ वीरू, सबजोनल कमांडर प्रफुल्ल, जय कुमार, प्रमोद यादव, भोला यादव, धनंजय भुईयां, टोप्पो पासवान, अल्बर्ट उर्फ़ विजय गंझू और राजदेव यादव शामिल थे. इस ख़ूनी संघर्ष में मौत के शिकार होने वालों में ज़्यादातर माओवादी नेता गया ज़िले के शेरघाटी अनुमंडल के विभिन्न गांवों के रहने वाले थे.

पिछले क़रीब तीन दशकों से बिहार झारखंड की सीमावर्ती इलाक़े में माओवादियों की सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है. एक ओर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के माओवादियों के आधार क्षेत्र में पहुंचने के कारण नक्सलियों की गतिविधियां कुछ कम हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता की सहानुभूति भी नक्सलियों से अब कम होती जा रही है. इसका प्रमाण यह है कि माओवादी कमांडर और कई नक्सली कांडों के अभियुक्त रहे विजय यादव उर्फ़ संदीप जी के शेरघाटी थाना क्षेत्र के बाबूरामडीह स्थित घर को प्रतिद्वंद्वियों द्वारा पिछले साल बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया था. अब ग्रामीण भी माओवादियों की हरकतों का विरोध करने लगे हैं. वहीं चतरा की घटना में ललेश यादव उर्फ़ प्रशांत उर्फ़ परमजीत नाम के भाकपा माओवादी कमांडर के मारे जाने के बाद दर्जन से अधिक नक्सली घटनाओं का राज़ भी दफ़न हो गया है. बाराचट्टी थाना के चांदो गांव का रहने वाला ललेश यादव 2008 में रानीगंज कांड तथा इसी साल 22 फ़रवरी के रौशनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस जीप उड़ाए जाने की घटना में लिप्त है. तक क़रीब 5 दर्जन मामलों में पुलिस को ललेश की तलाश थी. पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या के मामले में भी पुलिस को ललेश यादव की तलाश थी. अपने शीर्ष नेताओं के एक साथ मारे जाने से आहत भाकपा माओवादी ने बिहार-झारखंड बंद का आह्वान किया था.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस बंद का व्यापक असर रहा और कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी हुईं. हालांकि बिहार और झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट कर दिया था और सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम भी किए थे. बावजूद इसके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन से लेकर आम जनजीवन पूरी तरह बंद से प्रभावित रहा. बिहार-झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग फ़िलहाल इससे दहशत में हैं, क्योंकि अपने बड़े नेताओं के मारे जाने की बौखलाहट में माओवादी किसी भी तरह की बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं. लोगों में दहशत बनाए रखने के लिए माओवादी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल अब उनके अस्तित्व का है. दरअसल, भाकपा माओवादी टीपीसी और पुलिस के अलावा, जीटी रोड पर वाहनों, सरकारी वाहनों, वीआईपी वाहनों, पुलिस थाने, सीआरपीएफ कैंप, सरकारी स्कूल भवन और पुलिस पिकेट आदि को सॉफ्ट टारगेट बनाकर बम से उड़ा सकते हैं. माओवादी और तृतीय प्रस्तुति कमेटी के वर्चस्व की लड़ाई और बीच में पुलिस के रोल से बिहार-झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में इन दिनों काफ़ी दहशत है. ■

कौन बड़ा है?

सिविल सर्जन या मुख्यमंत्री!

राज्य में अफ़सरशाही इस क़दर हावी है कि अगर लोग ख़ुद एकजुट होकर जनहित का कोई काम करना चाहते हैं, तो अधिकारी उनकी ज़रा भी मदद नहीं करते. और न ही इस बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हैं. आख़िर ऐसा क्यों होता है?

कुमार कृष्णन feedback@chauthiduniya.com

बिहार में चारों ओर सुशासन का शोर है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सुशासन पर अफ़सरशाही हावी है. यह बिहार में हर जगह देखने को मिल रहा है. यहां इस क़दर अफ़सरशाही हावी है कि ज़िले का सिविल सर्जन भी मुख्यमंत्री सचिवालय और राज्य मुख्यालय के अधिकारियों के पत्र का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता. मामला मुंगेर ज़िले का है. बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव सुदेश कुमार लाल ने मुंगेर के सिविल सर्जन को एक पत्र दिनांक 27 फ़रवरी, 2013 को लिखा. इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय जनता दरबार से प्राप्त संदर्भ सं.-000010405120206 का हवाला देते हुए कहा कि इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक-854(10), दिनांक 16.8.2012 एवं 1207(10) दिनांक 2.11.12 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. बात यहीं ख़त्म नहीं होती है. दरअसल, इससे पूर्व भी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव विश्वनाथ ठाकुर ने इसी तरह का एक पत्र भेजा था. इन सारे पत्रों में सिविल सर्जन मुंगेर को यह निर्देश दिया गया था कि वर्णित तथ्यों की जांच कर एक प्रतिवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराते हुए, इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग को भी दी जाए. राज्यपाल के विशेष सचिव सुधीर श्रीवास्तव ने भी अपने पत्रांक 1014. पीपीसीसी 2012 द्वारा इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा था. लगातार तीन पत्रों में सरकार के वरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन की मांग किया जाना और जवाब नहीं दिए जाने का मतलब यही है कि शासन और प्रशासन तंत्र पर हावी है अफ़सरशाही.

मामला हवेली खड़गपुर के अग्रहण के कोरावा मणिगांव में रामकृष्ण महाराण कन्हैया सिंह मेमोरियल अस्पताल ट्रस्ट द्वारा एक अस्पताल स्थापित किए जाने का है. अस्पताल स्थापित किए जाने की योजना कैसे बनी? कहते हैं कि रफ्तार ज़िंदगी की थम न जाए, चलो कुछ कर जाएं, वक़्त के फ़ासले कम हो रहे हैं, इसी वक़्त कुछ कर गुज़र जाएं. इस सोच और जज्बे के साथ मुंगेर ज़िले के हवेली खड़गपुर की अग्रहण पंचायत के मणिगांव निवासी कैंसर पीड़ित विष्णुदेव सिंह ने इसे मूर्त रूप देना आरंभ किया और इस नेक काम में उनके रिश्तेदारों ने भी उनकी मदद की. वह अपने इलाज के लिए भेलौर गए और इसी दौरान उन्हें यह ख्याल आया कि क्यों न गांव में एक अच्छा अस्पताल बनाया जाए, ताकि इलाज के अभाव में किसी की मौत न हो.

26 अक्टूबर, 2011 को विष्णुदेव सिंह के अलावा कपिल सिंह, श्यामसुंदर सिंह, पूछो सिंह, निरंजन सिंह, नित्यानंद सिंह, अविनाश, सुबोध, भुवनेश्वर सिंह, सच्चिदानंद सिंह, सुभाष सिंह तथा अन्य लोगों ने मिलकर साढ़े तीन बीघा ज़मीन रामकृष्ण महाराणा कन्हैया सिंह मेमोरियल अस्पताल ट्रस्ट को दान में दी. इसके बाद इंप्रूव लाइफ लाइन फाउंडेशन के प्रस्तावित अस्पताल के भूमि पूजन का कार्य ज़िला परिषद अध्यक्ष रंजू देवी और उपाध्यक्ष संजय सिंह ने किया. इसी दिन रामकृष्ण महाराणा कन्हैया सिंह मेमोरियल अस्पताल के निर्माण को लेकर संस्था के चेयरमैन रितेश कृष्ण ने ग्रामीणों के साथ बैठकर एक समिति का गठन किया. जनसहयोग से काम आरंभ हो गया. प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण में एक करोड़ रुपये व्यय होंगे. इस अस्पताल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक तीनों चिकित्सा पद्धतियों से मरीज़ों का इलाज किया जाएगा. इसके अलावा, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि लोगों को इलाज के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई न जाना पड़े. अस्पताल परिसर में हर्बल तथा आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के पौधे लगाए गए हैं. दरअसल, अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है. यह स्थान खड़गपुर, बरियारपुर, तारापुर, सुल्तानगंज और असरगंज से 12 से 14 किलोमीटर दूरी पर है. स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र पिछड़ा माना जाता है. ऐसे में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस किसी अस्पताल का निर्माण होता है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी. इस निर्माणाधीन अस्पताल के संस्थापक सह अध्यक्ष रितेश कृष्ण और सचिव बलराम ठाकुर का कहना है कि जनसहयोग से काम हो रहा है, लेकिन अधिकारी इसके प्रति उदासीनता बरत रहे हैं. हालांकि उन्होंने अपने मक़सद और कार्यों से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को वाक़िफ़ कराया है. मुख्यमंत्री ने अस्पताल के संदर्भ में प्रतिवेदन भी मांगा है, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय, स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन मुंगेर के बीच ही यह मामला उलझकर रह गया है. यदि सिविल सर्जन समय निकालकर स्थल का मुआयना करके अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को दे देते हैं, तो सरकार की भी मदद मिलती. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि जब वे सेवा यात्रा के दौरान मुंगेर आ रहे हैं और तारापुर में उनका रात्रि विश्राम होगा, तो कुछ समय प्रस्तावित अस्पताल के काम को देखने के लिए निकालें, ताकि उनके समक्ष सही तस्वीर आ सके. एक ओर राज्य सरकार लोगों से सूबे के विकास के लिए सहयोग देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम के लिए आगे आने वाले को अफ़सरशाही हतोत्साहित कर रही है. ■

» एक नज़र «

सम्राट अशोक विवि का भूमि पूजन

सम्राट अशोक के नाम पर देश के पहले विश्वविद्यालय का बिहटा खगौल मार्ग पर जैतीपुर गांव के समीप भूमि पूजन किया गया. संस्थान के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा की मां राजमणि देवी ने भूमि पूजन किया. इस मौक़े पर सम्राट अशोक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा के बिना न तो स्वच्छ समाज की स्थापना हो सकती और न ही देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है. बिहार में पहली बार निजी विशविद्यालय की स्थापना की जा रही है. मान्यता प्राप्त होने के 36 माह के भीतर भवन का निर्माण किया जाना है. लगभग 1.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में क़रीब 100 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा. ...

सदस्यता अभियान की समीक्षा

युवा राजद में उत्साह

एयर वाइस मार्शल का अभिनंदन

चार प्रतिशत स्मार्ट कार्ड ही उपयोगी

नौ दिवसीय श्रीराम कथा

जन्मभूमि पुनौरा धाम में नौ दिवसीय दिव्य रामकथा का आयोजन किया गया. चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य श्रीरामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा विधिवत 11 मई से कथा का श्रीगणेश किया गया. जानकी नवमी के उपलक्ष्य में आयोजित कथा में प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की. कथा में यजमान जानकी नंदन पाडेय के अलावा पुनौरा धाम जानकी मंदिर के महंत कौशल किशोर दास, पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू, मंजू देवी, विधायक गुड्डी देवी, सुशील अग्रवाल, किशन जी सुंदरका, नागेंद्र प्रसाद, राम विनय सिंह कुशवाहा, बबलू मिश्रा, कैलाश कुमार समेत कुछ और लोगों ने भागीदारी की.

महाआरती का आयोजन

सीतामढ़ी : जानकी नवमी के उपलक्ष्य में सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम में नौ दिवसीय ...

प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प होगा

सदस्यता अभियान

धरना आयोजित

चुनाव संपन्न

... जून माह के अंत तक करा लिया जाएगा. इस अवसर पर सुमन भारती, मनोज कुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार, रंजीत कुमार पासवान, राकेश कुमार, सुधीर, पंकज पासवान, शशि भारती, राकेश, सदानंद, प्रमोद ठाकुर, चंद्रशेखर प्रसाद, रंजना कुमारी, रेखा कुमारी, रंजीत कुमार, केशर आलम, अनंत पासवान, पिंकी कुमारी, सेमा कुमारी, प्रद्युम्न कुमार, राकेश कुमार सहित अन्य शिक्षक भी उपस्थित थे.

नामांकन शुरू

अनिवार्य शिक्षा के तहत अलाभकारी वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए प्रारंभिक वर्ग नर्सरी में 25 प्रतिशत बच्चों का निःशुल्क नामांकन शुरू कर दिया गया है. उक्त बातें एडीएस पब्लिक स्कूल खगड़िया के निदेशक डॉ. डीएस सिंह ने कही. उन्होंने बताया कि यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है. इसके तहत ज़िले के सभी प्राइवेट शिक्षण ...

स्वास्थ्य सेवा बदहाल

साइकिल राशि का वितरण

मुस्लिम वेलफेयर की बैठक

वार्ड पार्षद का पद रिक्त

राजद की बनेगी सरकार

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

परिवर्तन रैली में मिली सफलता के बाद जदयू के कार्यकर्ताओं के हौसले काफ़ी बुलंद हैं.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सीतामढ़ी मत्स्य बीज वितरण केंद्र

सरकारी लापरवाही से करोड़ों का नुक़सान

सीतामढ़ी ज़िले में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के तहत लाखों की लागत से सड़क एवं स्कूलों के कायाकल्प का कार्य जारी है, लेकिन दशकों पूर्व ज़िले के राघोपुर बखरी में स्थापित मत्स्य प्रजनन एवं मत्स्य बीज वितरण केंद्र को बदहाली से उबारने की दिशा में सरकार बिल्कुल उदासीन है. नतीजतन, विदेशी तकनीक से स्थापित करोड़ों का राजस्व देने वाला केंद्र महज़ चंद लाख रुपयों की आमदनी तक ही सिमट कर रह गया है. क्यों पढ़िए चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

वाल्मीकि कुमार
feedback@chauthiduniya.com

भारत–नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी ज़िले में तक़रीबन ढाई दशक पूर्व मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन सह वितरण केंद्र की स्थापना कराई गई. ग़ौरतलब है कि सीतामढ़ी–शिवहर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–104 के राघोपुर बखरी गांव में मुख्य सड़क से क़रीब एक किलोमीटर पूरब दिशा में उक्त केंद्र की स्थापना मत्स्य पालकों में सौग़ात बनकर आई थी. 16 अक्टूबर, 1986 को बिहार सरकार के तत्कालीन मत्स्य सह पशुपालन मंत्री मदन प्रसाद सिंह ने खाद्य दिवस के अवसर पर उक्त केंद्र का उद्घाटन किया था. यह केंद्र 50 एकड़ ज़मीन पर स्थापित की गई, जिसमें कुल डेढ़ दर्जन तालाब मौजूद हैं. प्रत्येक तालाब की खुदाई डेढ़ एकड़ ज़मीन में कराई गई. इन तालाबों में क़रीब एक दर्जन तालाब मत्स्य प्रजनक है. स्थापना काल में विश्व बैंक के तत्कालीन अभियंता एससी खोभारी चाइना से उक्त केंद्र का डिजाइन लेकर आए थे, लेकिन अभियंता खोभारी के निधन के बाद अब तक कोई भी अभियंता उक्त डिजाइन की नक़ल कर पाने में सफल नहीं हो सका है.

वर्ष 1980 में अभियंता नंद किशोर सिंह ने चाइना से प्रशिक्षण प्राप्त कर केंद्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. ग़ौरतलब है कि इस प्रकार का केंद्र संपूर्ण भारत में एक पटना और दूसरा राघोपुर बखरी में मौजूद था. इनमें से एक पटना वाले को बंद कर अब उसकी जगह एम्स की स्थापना करा दी गई है. दूसरा, राघोपुर बखरी अब भी साल में मात्र चार माह मत्स्य बीज प्रजनन का कार्य कर रहा है. केंद्र परिसर में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए 20 एचपी का दो समरसेबुल पंप लगाया गया है. 40 केबीए का 1 जेनरेटर एवं 80 हज़ार गैलन क्षमता वाली 1 पानी की टंकी भी उपलब्ध कराई गई है. उसके साथ ही 3 हैचिंग पुल एवं 2 ब्रिडिंग पुल का निर्माण भी कराया गया है. फ़िलहाल केंद्र को चलाने के लिए एक प्रभारी मो. अख्तर जमाल के अलावा, 3 चौकीदार भी प्रतिनियुक्त हैं, जबकि सरकारी स्तर पर केंद्र के लिए हैचरी प्रबंधक के अलावा, मत्स्य तकनीशियन 4, मछुआरे 6 और चौकीदार का 2 पद सृजित हैं. केंद्र के प्रभारी मो. जमाल की मानें, तो सबसे पहले वर्ष 1986 में उड़ीसा के बास्केट हैचरी से केंद्र का श्रीगणेश किया गया था, जो कि वर्ष 1989 तक काम करता रहा. वर्ष 1990 से चाइनीज सर्कुलर हैचरी कार्यरत हो गई. नतीजा यह हुआ कि लाखों की लागत से निर्मित बास्केट हैचरी का प्रयोगशाला अतीत का एक काला अध्याय बन कर रह गया. प्रयोगशाला का पाइप लाइन और भवन जर्जरता का शिकार होकर रह गया. भवन का किवाड़ सड़ने लगा तो खिड़कियों के शीशे भी पहले ही चटक कर गिर चुके हैं. जगह–जगह लगे मकड़े के जाल से बदहाल प्रयोगशाला अब खंडहर का पर्याय बनकर रह गया है. किसानों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर अवसर मुहैया कराने को लेकर स्थापित इस केंद्र पर पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के अलावा, देश के अन्य प्रांतों से भी फिशरी कॉलेजों के छात्र आकर मत्स्य प्रजनन पर प्रयोग करते हैं, लेकिन केंद्र के पास ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण छात्रों को महज़ चंद दिनों बाद ही वापस जाना पड़ता है. बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत 281 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. उक्त स्वीकृति के बाद बतख सह मछली, बाग़वानी सह मछली एवं गाय सह मछली पालन के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कराई जाएगी. इसके अलावा, फिशरी कॉलेज के छात्रों की सुविधा को लेकर एक छात्रावास के निर्माण की योजना भी है. अगर प्रस्तावित राशि केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाता है तो बहुत हद तक केंद्र के विकास में सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही बिहार के मत्स्य पालकों को आंध्र प्रदेश समेत अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए जाने की समस्या से निजात भी मिल सकती है. अब तक केंद्र में मई माह से लेकर अगस्त माह तक बीज प्रजनन का कार्य किया जाता है. केंद्र द्वारा उत्पादित बीज को किसानों के बीच 5 सौ रुपये प्रति लाख की दर से वितरित भी किया जाता है. इससे प्रति वर्ष केंद्र को तक़रीबन ढाई से 3 लाख रुपये तक आमदनी भी होती है. केंद्र के लिए सबसे बड़ी समस्या विद्युत की बताई जाती है. कहने को तो केंद्र परिसर में एक ट्रांसफॉर्मर भी मौजूद है, लेकिन बिजली दिन भर में दो घंटा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है. सच तो यह है कि बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड की मत्स्य प्रजनन एवं बीज वितरण केंद्र पर अगर राज्य सरकार समय रहते ध्यान नहीं देती है, तो करोड़ों का यह केंद्र आने वाले दिनों में सरकारी लापरवाही का जीवंत उदाहरण बनकर रह जाएगा, जो सीतामढ़ी ज़िले के साथ ही सूबे बिहार के हुक्मरानों के लिए शर्मनाक साबित हो सकती है. सूबे में विकास की दुंदुभी बजा रही वर्तमान सरकार इस दिशा में क्या कर पाएगी, इस पर ज़िले के आम लोग एवं किसानों के अलावा मत्स्य पालकों की नज़रें टिकी हैं. ■

चंपारण : चुनावी तैयारियों में लगीं पार्टियां

क्या ये सचमुच पाक–साफ़ हैं?

आगामी चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं. इसके तहत सभी पार्टियां पूर्व में किए गए अपने कुकर्मों को छिपाकर ख़ुद को पाक साफ़ बताने में लग गई हैं. पढ़िए चौथी दुनिया की रिपोर्ट कि जनता क्या चाहती है?

इंतेज़ारुल हक़
feedback@chauthiduniya.com

मिशन 2014 की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं. सम्मेलनों, रैलियों और बैठकों के बहाने वे अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. चंपारण में सत्ताधारी दलों के साथ-साथ ग़ैर सत्ता दलों के नेता अभी से ही इस मुहिम में न केवल चंपारण में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, बल्कि अपने समीकरण भी तैयार करने में लगे हुए हैं. प्राय: सभी दलों के नेता अलग-अलग मुद्दे को उठा रहे हैं. वे पंचायतों से लेकर प्रखंडों एवं ज़िला मुख्यालय तक कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच पहुंचने की क़वायद कर रहे हैं. जदयू बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए किए गए धरना-प्रदर्शन एवं आंदोलनों के साथ-साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों की बदौलत एक बार फिर जनता का दिल जीतने का प्रयास कर रही है. वह जनता को तरह-तरह के सपने दिखा रही है, तो दूसरी तरफ़ मुख्य विपक्षी दल राजद भी ख़ामोश नहीं है. दरअसल, परिवर्तन रैली में मिली सफलता के बाद जदयू के कार्यकर्ताओं के हौसले काफ़ी बुलंद हैं. रैली से वापसी के बाद पार्टी जनता के अन्य मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने की योजना बना रही है. यहां यह बता दें कि चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि होने के कारण शुरू से ही राजनेताओं के लिए प्रयोग स्थली के रूप में जाना जाता है. यही कारण है कि बाहर से आए नेता भी यहां आकर चुनाव जीत लेते हैं. हाल ही में स्थानीय शांति निकेतन जुबली स्कूल में संपन्न हुए युवा जदयू के ज़िला सम्मेलन एवं एमएस कॉलेज में संपन्न हुए महिला सम्मेलन में जदयू के संगठन प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद आरसीपी सिन्हा, राज्यसभा सांसद साबिर अली, युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ़ हुसैन, बिहार सरकार के मंत्री अवधेश कुशवाहा, एमएलसी सतीश कुमार आदि नेताओं के शामिल होने के बाद जदयू की युवा शक्ति हरकत में आ गई है. सरकार के कार्यों को ज़िला संयोजक साजिद रज़ा के नेतृत्व में जनता के बीच गिनाया जा रहा है.

उधर, राजद जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव, पूर्व प्रत्याशी राजेश गुप्ता उर्फ़ बबलू गुप्ता, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉ. शमीम अहमद, युवा जिलाध्यक्ष ई. एहतेशाम हुसैन, अनिरुद्ध साहनी, अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ़ पप्पू दुबे, नसीमा ख़ातून, मुन्नी लाल यादव आदि राजद के अनेक नेता लगातार बैठकें कर जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं. इस दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और सभी अपने आप को स्वच्छ बताने में लगे हैं. दूसरी तरफ़ जदयू के सहयोगी भाजपा भी अपने कैडरों को जगाकर बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील मणि तिवारी, स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह, विधायक प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, डॉ. लालबाबू प्रसाद आदि नेता भी नहले पे दहला मारते हुए केंद्र की यूपीए सरकार एवं पूर्व की लालू-राबड़ी की सरकार ख़ामियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है. इधर, वर्षों से चंपारण में अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही ज़िला कांग्रेस कमेटी भी सक्रिय हो गई है और बंजरिया पंडाल के प्रजापति आश्रम स्थित कार्यालय में लगातार बैठकें भी हो रही हैं. जिलाध्यक्ष उमर सैफ़ुल्लाह उर्फ़ बरकत खां, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला, शशिकांत मिश्रा, अनवर आलम अंसारी आदि नेता कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि चंपारण में लगातार बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार और लूट-खसोट से जनता परेशान है. मगर राजनेता जनता की समस्याओं के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है. ■

मोतिहारी

मीडिया आतंक को बढ़ावा देती है : सेराजी

इस्लाम में आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है. बेगुनाहों का ख़ून बहाने वालों का कोई चेहरा नहीं होता है. हमारे देश के रहनुमा वोट के लिए समाज को हमेशा बांटते रहे हैं और धर्म के नाम पर ख़ून बहाते रहे हैं. हरसिद्धि प्रखंड के घिउआढ़ार में आयोजित दो दिवसीय अशाअत इस्लाम कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना जरजिश सेराजी ने उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, जबकि मीडिया आतंक को किसी ख़ास मज़हब से जोड़कर बदनाम करती है. गैंग रेप और बलात्कार की बढ़ रही घटनाओं पर चिंता ज़ाहिर करते हुए उन्होंने नेताओं को कठघरे में खड़ा किया. कांफ्रेंस का संचालन वरिष्ठ पत्रकार ओजैर अंजुम ने किया, जबकि अध्यक्षता मौलाना ख़ुर्शीद आलम सलफी ने की. कार्यक्रम को मौलाना मोगीस अहमद यादव, डॉ. ख़लील अहमद, मौलाना ख़ुर्शीद अहमद आदि ने संबोधित किया. मौक़े पर ज़िला पार्षद यहिया ख़ां उर्फ़ नारंगी ख़ां, जय प्रकाश यादव, ओजैर अहमद आदि उपस्थित थे. ■

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

27 मई-02 जून 2013

www.chauthiduniya.com

वरुण गांधी पर यूपी सरकार मेहरबान क्यों

सपा की सियासी चाल कहें या कुछ और?

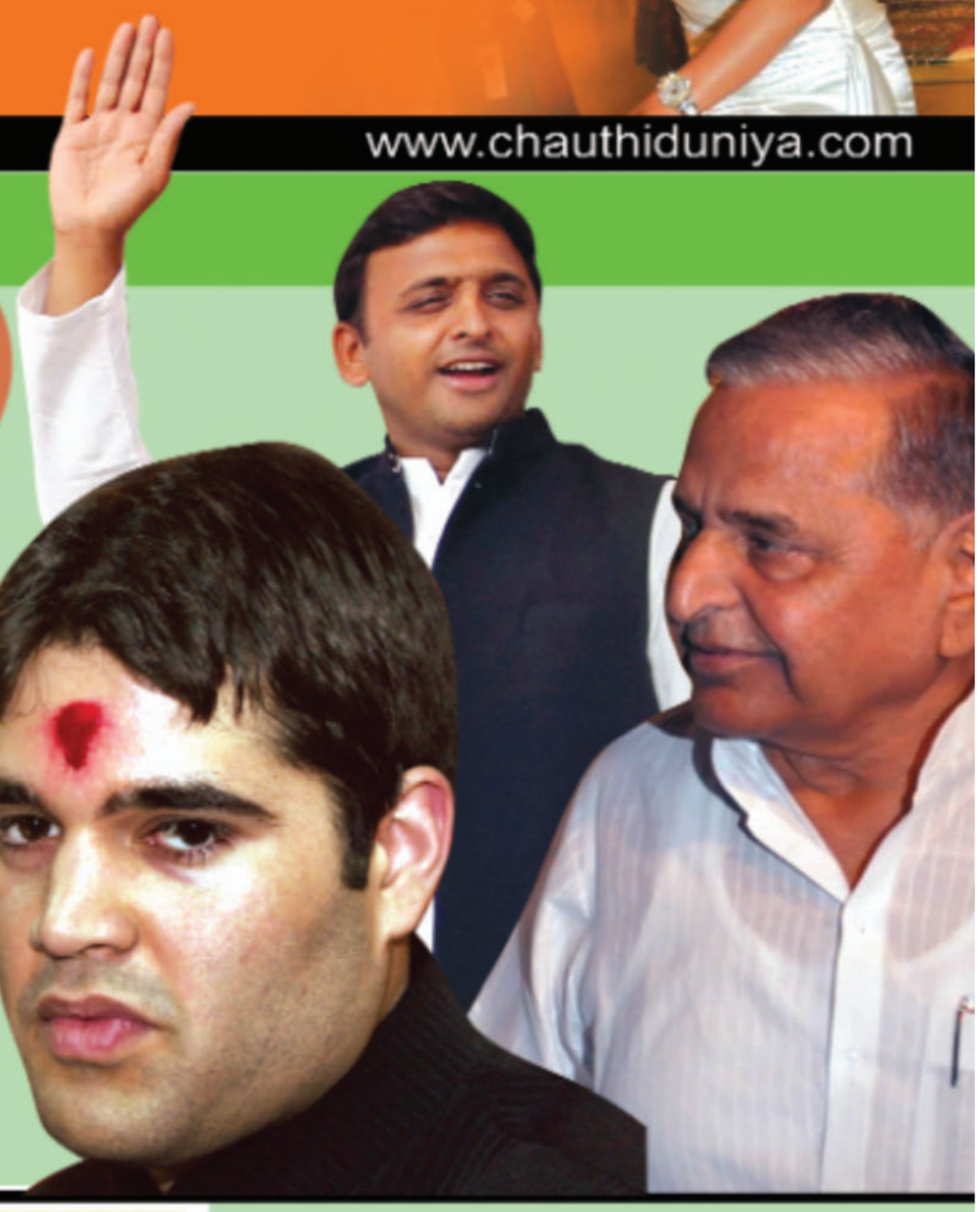

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बारे में यह अमूमन कहा जाता है कि वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं. कभी राम के नाम पर वह रहीम को खुश करते हैं, तो कभी अपने फ़ायदे के लिए राम-रहीम दोनों का इस्तेमाल करते हैं. पीलीभीत में भड़काऊ भाषण देने पर मुक़दमे झेल रहे भाजपा के युवा नेता वरुण गांधी को जिस तरह अदालत ने बाइज्जत बरी किया, उसमें भी लोगों को सपा प्रमुख की चाल नज़र आती है. आख़िर क्या है सपा-भाजपा के बीच अंदरख़ाने का याराना, जानिए इस रिपोर्ट में...

अजय कुमार

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में एक नई तरह की राजनीति इन दिनों पनप रही है, क्योंकि सपा सरकार जनहित की आड़ में आतंकवादियों, खूंखार अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों और लुटेरों के ख़िलाफ़ चल रहे मुक़दमे बंद कराने की साज़िश में लगी है. इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़े क़रीब तीन हज़ार लोगों के ख़िलाफ़ भी विभिन्न धाराओं में चल रहे आपराधिक मुक़दमों को वापस लेने के लिए पेपर वर्क शुरू हो गया है. इनमें से कुछ के ख़िलाफ़ भले ही पिछली मायावती सरकार ने पक्षपातपूर्ण तरीक़े से मुक़दमे ठोंक दिए थे,लेकिन अधिकांश लोगों की छवि साफ़-सुथरी नहीं रही है. हालांकि सपा नेतृत्व को अब यही लगता है कि आतंकवादियों पर दायर मुक़दमे हटाकर वह मुसलमानों का वोट हासिल कर सकती है. इतना ही नहीं, सपा सरकार ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बसपा राज में इन पर दर्ज किए गए एससी/एसटी के मुकदमों से छूट देने की बात कर रही है, तो ठाकुरों को ख़ुश करने के लिए पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे कई क्षत्रिय नेताओं के ख़िलाफ़ चल रहे मुक़दमे बंद करने की पहल भी कर चुकी है.

वैसे देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी की सफलता का पैमाना हमेशा जातीय समीकरण ही रहा है. यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि सपा सरकार प्रदेशवासियों का भला करने की बजाय उन्हें टुकड़ों में बांट कर सब्ज़बाग़ दिखाते हैं. यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन सपा का मात्र इतने से काम नहीं चलता है. समाजवादी पार्टी की सफलता का पैमाना काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी से भी जुड़ा है. भाजपा के उभार से सपा की राजनीति को खाद-पानी मिलता है. भाजपा जब हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है, तो सपा अल्पसंख्यकों को उसका खौफ़ दिखाकर उसे बरगलाती है. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी समय-समय पर भाजपा और पार्टी में मौजूद कट्टर हिंदुत्व छवि के नेताओं मसलन, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती,विनय कटियार, विहिप के अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेंकी थीं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को भाजपा के युवा नेता और महासचिव वरुण गांधी में अपनी सफलता का मंत्र दिखाई दे रहा है. एक तरफ भाजपा वरुण को यूपी का नरेंद्र मोदी बनाकर पेश करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी वरुण की राह में बिछे कांटे को हटाने में व्यस्त है, ताकि वह वरुण के सहारे अपनी राजनीति चमका सके.

ग़ौरतलब है कि सपा सरकार की मेहरबानी से वरुण गांधी के ख़िलाफ़ पीलीभीत में चल रहे वे सभी मुक़दमे ख़त्म हो गए हैं, जो वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के समय भड़काऊ भाषण देने के कारण उन पर दर्ज हुए थे. जानकारों का कहना है कि वरुण गांधी को यह राहत सरकार की लचर पैरवी के कारण मिला है. इस बाबत जब सपा प्रवक्ता और अखिलेश सरकार में काबीना मंत्री राजेंद्र चौधरी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया. उनके अनुसार, समाजवादी पार्टी अदालती मामलों में दख़ल नहीं देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हक़ीक़त ठीक इसके विपरीत है. याद रहे कि मुसलमानों के रहबर बनने का दावा करने वाले मुलायम सिंह यादव और उनकी सरकार ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने के बाद सुर्खियों में आए भाजपा के युवा नेता वरुण गांधी को अदालत से राहत मिलने के बाद लोगों के बीच से तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में ज़िला निर्वाचन अधिकारी की ज़िम्मेदारी संभाल रहे पीलीभीत के ज़िलाधिकारी ने स्वयं वरुण गांधी के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया था, लेकिन चार वर्षों के बाद वे अदालत में अपने बयान से मुकर गए. उसके बाद एक-एक करके सभी 14 गवाह अपने बयानों से मुकर गए. दरअसल, ये सभी लोग सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे.

गौरतलब है कि मार्च 2009 में पीलीभीत के डालचंद मोहल्ले में वरुण गांधी ने एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण दिया था. पीलीभीत पुलिस ने उसी दिन तत्कालीन ज़िलाधिकारी महेंद्र अग्रवाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें साफ़ लिखा हुआ था कि भाजपा नेता वरुण गांधी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इस बाबत वरुण के भड़काऊ भाषण की सीडी भी तैयार की गई थी. मामला मीडिया में उछला, तो ज़िलाधिकारी महेंद्र अग्रवाल फ़ौरन हरकत में आ गए. बतौर ज़िला निर्वाचन अधिकारी उन्होंने पीलीभीत कोतवाली में वरुण गांधी के ख़िलाफ़ 153 ए 295 ए 505(2) और 125 लोक प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा में मुक़दमा दर्ज करा दिया. मुक़दमा दर्ज होते ही मायावती सरकार ने वरुण गांधी को न सिर्फ़ गिरफ्तार किया, बल्कि उन पर रासुका लगाकर जेल भी भेज दिया गया.

हालांकि चार वर्षों में यह मुक़दमा कोतवाली थाने से अदालत की ड्योढ़ी पार करते-करते मरणासन स्थिति में पहुंच गया. दरअसल, वरुण को भड़काऊ भाषण से रिहा कराने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने अदा की, जिन्होंने वरुण के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराया था. वरुण गांधी को सज़ा दिलाने के लिए इन अधिकारियों को अदालत में मज़बूत गवाही देनी थी, लेकिन ज़िलाधिकारी और एडीएम समेत सभी 14 गवाह अदालत में अपने बयानों से ही मुकर गए. पीलीभीत के ज़िलाधिकारी (जो उस समय ज़िला निर्वाचन अधिकारी थे) वह इस बात से ही मुकर गए कि उन्होंने वरुण गांधी के ख़िलाफ़ कोई मुक़दमा लिखवाया था. वहीं एडीएम जमीर, जिन्होंने वरुण गांधी के भाषण की रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने भी अदालत में यही बयान दिया कि न वरुण गांधी की कोई सभा उन्होंने देखी या सुनी नहीं है. इस मामले में दो अहम गवाह इंस्पेक्टर मणि राम राव और राजवीर सिंह भी अपने बयान से पलट गए. बाकी बचे गवाहों में सब इंस्पेक्टर राजकुमार सरोज के अलावा, कांस्टेबल और थाने के मुंशी ने भी बयान बदल डाले. अदालती आदेश में इस बात का ज़िक्र भी किया गया था कि सरकार के गवाह किस तरह होस्टाइल यानी कि पक्षद्रोही हो गए.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आख़िर किसके कहने पर सरकारी अफसर और पुलिसकर्मियों ने अपने बयान बदल दिए. क्या यह महज इत्तेफ़ाक़ है या कुछ और. सपा नेताओं की बातों पर भरोसा करते हुए यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने वरुण के मुक़दमे में कोई दख़लंदाजी नहीं की, लेकिन इससे उनकी छवि पूरी तरह बेदाग़ नहीं हो जाती है. अखिलेश यादव सरकार आम जनता को यह बताएं कि वे कौन से कारण थे, जिनके चलते उनकी सरकार ने सत्र न्यायालय के आदेश के ख़िलाफ़ उच्च अदालत में अपील नहीं की. साथ ही अदालत में बयान बदलने वाले सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. सपा सरकार के इस रवैये से यह ज़ाहिर होता है कि मुलायम सिंह यादव वरुण के सहारे अपनी पार्टी को मज़बूत करना चाहते हैं.

बहरहाल, अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में राजनीति की बू आती है. एक तरफ बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दलील देते हुए कहते हैं कि उस समय हम सत्ता में थे और हमारी सरकार ने वरुण को ऐसा सबक सिखाया था. उनके मुताबिक़, सपा परोक्ष रूप से संघ के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रही है. वह मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है. अगर आज प्रदेश में बसपा का शासन होता, तो सभी अधिकारी और पुलिस वाले अपने बयान से पलटने की सोच भी नहीं सकते थे,लेकिन वह जानते हैं कि सपा राज में उन्हें संघ का एजेंडा ही पूरा करना है. कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने वरुण की रिहाई पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो होना ही था. उनके अनुसार, मुसलमानों को समय रहते सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें सपा का साथ देने की बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है. मुलायम पहले भी भाजपा से हाथ मिला चुके हैं और आगे भी वह ऐसा करेंगे. इसका पक्का प्रमाण है वरुण के ख़िलाफ़ चल रहे मुक़दमों की सपा सरकार के अधिकारियों द्वारा लचर पैरवी किया जाना. अधिकारी अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं. उन्हें कहीं न कहीं सपा सरकार से कोई संकेत मिला होगा. वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने वरुण को बरी किए जाने पर खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है. हालांकि वे इस बात पर खेद जताते हुए कहते हैं कि सपा सरकार आतंकवादियों और बड़े अपराधियों पर से मुक़दमे हटाकर उन्हें दहशत फैलाने का मौक़ा दे रही है. वाजपेयी कहते हैं कि किसी भी नेता के ख़िलाफ़ सामाजिक संघर्ष के दौरान या फिर दुर्भावनावश मुक़दमा दायर किया जाता है, तो उसे वापस लिया जाना उचित है, लेकिन उसकी आड़ में देशद्रोहियों को छोड़े जाने की सपा सरकार की साज़िश का भाजपा क़रारा जबाव देगी.

बात अगर मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं की करें, तो प्रसिद्ध इस्लामिक धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने न्यायप्रक्रिया पर तो कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन इस बात पर सवाल ज़रूर किया कि जिस साम्प्रदायिक भाषा का इस्तेमाल वरुण गांधी ने किया था, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया. लखनऊ ईदगाह के इमाम फिरंगी महली के भी कुछ ऐसे ही विचार थे. वह कहते हैं कि एक सरकार मुक़दमा दायर करती है, तो दूसरी सरकार उसे साज़िश के तहत कमज़ोर कर देती है. बहरहाल, वरुण गांधी के मामले पर जिस चतुराई से सपा सरकार ने गेम खेला है, उसे समझने वाले बखूबी समझ रहे हैं. असल में समाजवादी पार्टी का यही दोहरा चरित्र उसे कटघरे में खड़ा करती है. ■

वरुण मामले में यूपी सरकार का यूटर्न

सपा सरकार अपने फ़ैसलों को लेकर यूटर्न लेने के लिए काफ़ी नाम कमा चुकी है. कभी यह उसकी राजनीतिक मजबूरी लगती है, तो कभी ज़रूरत. ऐसा करते समय उन्हें समाजवादी विचारधारा का भी ख़्याल नहीं रहता. अगर ऐसा न होता तो भाजपा के युवा सांसद वरुण गांधी के ख़िलाफ़ वह पहले नरम और बाद में गरमरवैया नहीं अपनाती. शायद सपा सरकार दोनों हाथों में लड्डू चाहती है. इसीलिए पहले तो उसने वरुण के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण का मुक़दमा वापस करने की फाइल आगे बढ़ाई और जब गवाहों के पक्षद्रोही बनने के बाद वरुण बरी हो गए, तो अल्पख्यकों को खुश करने के लिए ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात करने लगी,जबकि यह लगभग तय है कि गवाहों के मुकरने के बाद अब किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है.

अखिलेश सरकार ने वरुण गांधी के प्रति अपना रवैया बदलते हुए अब उन्हें अदालत से मिल रही राहत का विरोध करने का फ़ैसला किया है. आईजी एसटीएफ आशीष गुप्ता ने मीडिया को सरकार के रुख की जानकारी देते हुए बताया कि वरुण को पीलीभीत में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मुक़दमों में सेशन और सीजेएम की अदालत से मिली राहत का विरोध किया जाएगा. सरकार इसके लिए सक्षम अदालतों में अपील दायर करेगी. बहरहाल, यह बदलते सियासी समीकरणों का ही नतीजा है कि जिस सरकार ने नवंबर 2012 में वरुण पर दर्ज मुक़दमों को वापस लेने के लिए प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, वही सरकार वरुण को कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके ख़िलाफ़ अपील में जाने की बात कर रही है. वैसे क़ानून के जानकार यही कह रहे हैं कि सपा सरकार ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए यह क़दम उठाया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अन्ना के मुताबिक़, देश को आज़ाद कराने में हमारे महान सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी.

परशुराम जयंती के बहाने

अब ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश

महापुरुषों की पहचान उनके कृतित्व से होती है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए सियासी पार्टियां अब महापुरुषों के नाम पर जातिगत गोलबंदी करना चाहते हैं. पिछले दिनों परशुराम जयंती पर कुछ ऐसा ही दांव समाजवादी पार्टी ने खेला. ख़ुद को डॉ. लोहिया की विचारधारा का पक्षधर कहने वाली सपा को यह भी ख्याल नहीं रहा कि जाति तोड़ो-समाज जोड़ो का नारा किसी जमाने में डॉ. राममनोहर लोहिया ने ही दिया था...

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति इन दिनों परवान चढ़ रही है. जिस तरह एक दशक पहले दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक का बोलबाला था और जिस पर हर एक पार्टी की निगाहें टिकी रहती थीं, आज वही स्थिति ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर है. दरअसल, प्रदेश में गला काट जातीय राजनीति ने हर तबके को इस तरह जकड़ रखा है कि कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया है. यही वजह है कि हर पार्टी जातिगत राजनीति करने को मजबूर हैं. ब्राह्मणों पर बिछी सियासी बिसात पर सपा और बसपा ने तो पूरी तरह नज़र बनाए हुए है. एक तरफ़ बसपा नारा देती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा. सपा इससे पूरी तरह वाकिफ़ है कि इसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बसपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को धूल चटाई थी. उस समय बसपा में ब्राह्मण खेमे का नेतृत्व सतीश मिश्र संभाल रहे थे. हालांकि बसपा का यह दुर्भाग्य रहा कि भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंसकर उसने अपना जिताऊ फार्मूला 2012 के विधानसभा चुनाव में खो दिया और इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिला.

ग़ौरतलब है कि वर्ष 2007 में बसपा ने अस्सी ब्राह्मण प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था और सत्ता पर क़ाबिज़ हुई थी. उसी तरह वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में उसने चौहत्तर ब्राह्मणों को टिकट थमाया, लेकिन उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फेल हो गया. वहीं दूसरी ओर सपा ने पचास ब्राह्मण को टिकट दिया, जिनमें इक्कीस विधायक जीत गए और पार्टी को सत्ता मिली. अब बसपा की मंशा फिर से दलित और ब्राह्मण गठजोड़ करने की है. हालांकि बसपा की इस कोशिश पर सपा की नज़र बनी हुई है. दरअसल, उसने ब्राह्मण को लुभाने के लिए लखनऊ में 300 एकड़ भूमि पर पंडित जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क और परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का ऐलान कर डाला, यानी सपा इन दिनों एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है. एक तरफ सपा भाजपा की पक्षधर ब्राह्मण मतों पर सेंध लगाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस और बसपा को गच्चा देने में वह कोई मौक़ा नहीं छोड़ना चाहती. इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक का कहना है कि ब्राह्मण ने हमेशा भ्रष्टाचार और अन्याय के ख़िलाफ़ वोट दिया है.

> **लोकसभा चुनाव की तारीख़ नज़दीक आते ही सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा जातीय सम्मेलन करने और महापुरुषों की जयंती मनाने में मशगूल हो गए हैं. असल में उनका मक़सद महापुरुषों को याद करना नहीं है, बल्कि इसी के बहाने वे जातीय गोलबंदी में सफल होना चाहते हैं. अगर देखा जाए, तो इस मामले में सपा और बसपा एक दूसरे को मात देना चाहते हैं.**

बहरहाल, लोकसभा चुनाव की तारीख़ नज़दीक आते ही सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा जातीय सम्मेलन करने और महापुरुषों की जयंती मनाने में मशगूल हो गए हैं. असल में उनका मक़सद महापुरुषों को याद करना नहीं है, बल्कि इसी के बहाने वे जातीय गोलबंदी में सफल होना चाहते हैं. अगर देखा जाए, तो इस मामले में सपा और बसपा एक दूसरे को मात देना चाहते हैं. ■

आरटीआई में छेड़छाड़ पर भड़कीं सोनिया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा नित्य नए विवादों में घिरते जा रहे हैं. कभी उनकी सरकार की कार्यशैली को लेकर विपक्षी पार्टियां हल्ला बोलती हैं, तो कभी राज्य के सामाजिक संगठन उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आते हैं. ऐसे में आरटीआई में रद्दोबदल करना उन्हें महंगा पड़ गया है. विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बल्कि कांग्रेस आलाकमान भी मुख्यमंत्री बहुगुणा को खरी-खोटी सुना रहे हैं. क्या है पूरा मामला, पढ़िए इस रिपोर्ट में...

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को नकार कर नया क़ानून लाना भारी पड़ गया है. ग़ौरतलब है कि बहुगुणा ने आरटीआई क़ानून को कुंद करने के लिए एक खेल खेला था,जिस पर स्थानीय आरटीआई कार्यकर्ता भड़क गए. हालांकि जनवरी में बहुगुणा सरकार की ओर से अधिसूचित सूचनाधिकार नियमावली पर कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश सरकार के इस कार्यवाही पर गहरी आपत्ति ज़ाहिर की थी. इस बाबत सोनिया ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को पत्र लिखकर कहा है कि वह कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे आरटीआई की मूल भावना प्रभावित हो. सोनिया ने इस बात पर भी रोष प्रकट किया है कि नियमावली बनाने से पहले प्रदेश सरकार ने आरटीआई कानून के स्टेक होल्डरों से विचार-विमर्श क्यों नहीं किया. मुख्यमंत्री बहुगुणा की इस मनमानी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैरत में हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिस क़ानून से जनता को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक हथियार मिला और जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया, आख़िर उसे मुख्यमंत्री बहुगुणा क्यों तहस-नहस करना चाहते हैं. क्या वह ऐसा किसी दवाब में कर रहे हैं, यह जांच का विषय है.

बहरहाल, मुख्यमंत्री बहुगुणा को संबोधित पत्र में सोनिया ने कहा है कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) के निदेशक माजा दारूवाला उनके संज्ञान में यह बात ले आए हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा नोटिफाइड आरटीआई नियमावली से सूचना क़ानून की ताक़त ख़त्म हो जाएगी. सीएचआरआई निदेशक का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने जो नई आरटीआई नियमावली बनाई है, उससे सूचना आवेदकों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी और लोक सूचनाधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को अपार शक्तियां मिल जाएंगी. सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि उनके संज्ञान में यह भी लाया गया है कि नियमावली बनाने से पहले सूचनाधिकार के स्टेक होल्डरों मसलन, सूचना आयोग, सूचनाधिकार कार्यकर्ता, सूचनाधिकार से जुड़े संगठनों और विशेषज्ञों से कोई परामर्श तक नहीं लिया गया.

ग़ौरतलब है कि 28 फरवरी को मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में सोनिया गांधी ने कहा है कि यूपीए सरकार सार्वजनिक सेवाओं में और ज़्यादा पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए बहुत प्रयास कर रही है. ऐसे में राज्य सरकार को सूचनाधिकार से जुड़ी ऐसी नियमावली बनानी चाहिए, जो सूचना क़ानून की मूल भावना के अनुरूप हो. कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि सरकार सूचना क़ानून के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सूचनाधिकार क़ानून से जुड़ी नियमावली को लेकर उठ रहे तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री से रिपोर्ट भी तलब की है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने जो सूचना का अधिकार नियमावली नोटिफाई की है, उसका राज्य सूचना आयोग समेत सूचनाधिकार कार्यकर्ता और सूचनाधिकार से जुड़े तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं. इस नियमावली के कारण राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग के बीच टकराव और बढ़ता जा रहा है. पिछले दिनों पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त डॉ आरएस टोलिया ने भी इस बाबत यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था. इतना ही नहीं कई सूचनाधिकार कार्यकर्ता और संगठनों ने तो इस नियमावली के विरुद्ध नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं, जो अदालत में विचाराधीन हैं. आरटीआई कार्यकर्ताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों को पोषित करने के लिए आरटीआई का पर कतरना चाहते हैं और इस खेल में सूबे के भ्रष्ट अफसरों के गिरोह ने सुनियोजित तरीक़े से इस कार्य को अंज़ाम दिया है.

अमिताभ कुमार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित

लखनऊ में पदस्थापित भारतीय रेल सेवा के अधिकारी अमिताभ कुमार को राजभाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेलवे के सर्वोच्च सम्मान रेलमंत्री राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा रेल मंत्री की ओर से प्रदान किया गया. ग़ौरतलब है कि लखनऊ के चारबाग़ स्टेशन पर वर्षों तक स्टेशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे अमिताभ कुमार वर्तमान में उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक मुख्यालय में सहायक परिचालन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं. यह पुरस्कार हिंदी में लिखित उनके तीन उपन्यासों के लिए प्रदान किया गया है. उनकी रेल विभाग में हिंदी प्रेमी अधिकारी के रूप में अपनी एक अलग पहचान है. उनके द्वारा हिंदी में लिखे गए तीन उपन्यास ब्लडी मैरिट स्कालर्स, ऑपरेशन लाग आउट और महंत द गॉड फादर प्रकाशित हो चुके हैं. वह इसके पूर्व दो बार रेलमंत्री द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

ज़मीन से जुड़े शायर थे आज़मी : अखिलेश यादव

मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी की 11वीं पुण्यतिथि पर पिछले दिनों संगीत नाटक अकादमी में ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी की ओर से आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कैफ़ी आज़मी ज़मीन से जुड़े एक प्रगतिशील शायर थे. उनके व्यक्तित्व की छाप उनकी शायरी में बखूबी देखी जा सकती है. मुख्यमंत्री अखिलेश के मुताबिक़, उन्होंने अपने जीवन में तमाम ऊंचाइयों को छूते हुए प्रदेश का नाम रौशन किया. इस मौक़े पर गीतकार गोपाल दास नीरज, शायर प्रो. वसीम बरेलवी और चित्रकूट से महिलाओं की सहायता से निकाले जा रहे अख़बार ख़बर लहरिया की संपादक शालिनी जोशी को कैफ़ी आज़मी अवार्ड से नवाज़ा गया. उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष और गोपाल दास नीरज ने कैफ़ी आज़मी को अपना बड़ा भाई बताया और मुंबई में उनसे मुलाक़ात से लेकर यशभारती सम्मान पाने का संस्मरण सुनाया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कैफ़ी आज़मी हिंदी और उर्दू भाषा को गंगा-जमुनी तहजीब का माध्यम मानते थे. वे तो बस मोहब्बत की भाषा जानते थे. वहीं इस मौक़े पर प्रो. वसीम बरेलवी ने कहा कि कैफ़ी आज़मी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था. उनका मानना था कि हिंदुस्तान का शायर होने के लिए अवाम के बीच जाना बेहद ज़रूरी है. इस समारोह में प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री प्रो. अभिषेक मिश्र और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष नावेद सिद्दिकी भी मौजूद थे. जावेद अख़्तर और अभिनेत्री शबाना आज़मी ने नाटक कैफ़ी और मैं का मंचन कर अपने शायर पिता को श्रद्धांजलि दी. इस नाटक में जावेद अख़्तर ने कैफ़ी आज़मी और शबाना ने अपनी मां शौकत आज़मी का किरदार निभाया.

शहीदों का अपमान कर रहे हैं राजनेता : अन्ना

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक पार्टियां संविधान विरोधी काम कर रहे हैं. सरकार की ग़लत नीतियों की वजह से ही देश के किसानों की हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही है. यह बात समाजसेवी अन्ना हज़ारे ने जनतंत्र यात्रा के दौरान उत्तरकाशी की एक जनसभा में कही.

अन्ना के मुताबिक़, देश को आज़ाद कराने में हमारे महान सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी. लेकिन शहीदों के उन सपनों को भ्रष्ट राजनेता चकनाचूर कर रहे हैं. उन्होंने देश में व्यवस्था परिवर्तन को नितांत ज़रूरी बताते हुए कहा कि युवाओं को अब निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनकी जनतंत्र यात्रा का मक़सद देश के लोगों को जागरूक करना है. वहीं इस मौक़े पर चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि अन्ना सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में जनसंसद आयोजित करने वाले हैं, इसलिए उत्तराखंड वासियों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे. उनके मुताबिक़, सीबीआई सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है, इसलिए सीबीआई को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की आवश्यकता है.

ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, भविष्य साकार हो रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव
मा. सांसद, लोकसभा एवं पूर्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार

श्री अखिलेश यादव
मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

कन्या विद्या धन

योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए एकमुश्त रू. 30,000 की सहायता प्रदान की जा रही है। इससे इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।

बेरोजगारी भत्ता

प्रदेश के शिक्षित परंतु बेरोजगार युवाओं को रू. 1000 का मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। भत्ते के कारण, रोजगार मिलने तक अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ बेरोजगारों का हौसला बढ़ाने और उनके दिलों में आत्मविश्वास जगाने में भी मदद मिली हैं।

वूमेन पॉवर लाइन

टोल फ्री नम्बर 1090 के साथ यह हेल्पलाईन प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने का लक्ष्य रखती है। आपत्तिजनक फोन कॉल या एसएमएस/एमएमएस की स्थिति में महिलायें उपरोक्त नम्बर पर कॉल कर, अपनी पहचान गुप्त रखकर भी, पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा

जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं त्वरित उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पहली बार समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा शुरू की गई है। टोल फ्री नम्बर 108 पर कॉल कर इस मुफ्त सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। गर्भवती महिलायें, दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति और गंभीर रोगियों को जल्द चिकित्सा सेवाओं का निश्चित लाभ होगा।

दर्शन शर्मा

लैपटॉप वितरण योजना

योजना के अंतर्गत प्रदेश के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने हेतु मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं। इससे न केवल छात्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ होगा, बल्कि शिक्षा भी आसान और बेहतर बनेगी। इससे उत्तर प्रदेश के छात्र/छात्राओं को बेहतर अवसर मिलने के साथ उनका भविष्य भी उज्ज्वल बनेगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

उत्तर प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास हेतु बेहतर वातावरण सृजित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012, सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012, उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012, सौर ऊर्जा नीति-2013, चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 एवं कुक्कुट प्रोत्साहन नीति-2013 लागू।

CELEBRATING 365 DAYS

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री के आह्वान को अपनी आवाज़ बनाते हुए बकुलाही के सपूतों ने भूजल सप्ताह के पूर्व ही नदी का नजारा बदल डाला.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बकुलाही नदी को बचाने का भगीरथ प्रयास

ग्रामीण आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार

बकुलाही नदी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे समाज शेखर ने जब नदी की विलुप्त हुई प्राकृतिक धारा को पुनः बहाल करने का प्रयास शुरु किया, तो एक लाख प्यासे लोगों को मानो संजीवनी मिल गई.

पौराणिक हिंदू मान्यता है कि सदानीरा गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान ने प्रसन्न होकर धरती की प्यास बुझाने के लिए जाह्नवी को इस वसुंधरा पर भेजा. एक ऐसा ही भगीरथ प्रयास प्रतापगढ़ ज़िले में हो रहा है, जहां 25 गांवों को पानी मुहैया कराने वाली बकुलाही नदी को बचाने की कोशिश स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं. क्या है पूरी कहानी, पढ़िए इस रिपोर्ट में

सागर सत्यार्थी
feedback@chauthiduniya.com

प्रतापगढ़ ज़िले के दक्षिणांचल के पचीस गांवों में बकुलाही नदी का मुद्दा सुलग रहा है. इस नदी को बचाने के लिए ग्रामीण अब आर–पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं. क़रीब ढाई दशक पूर्व जल पुरुष राजेंद्र सिंह से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने बकुलाही नदी को बचाने का संकल्प लिया था. बीते पच्चीस वर्षों में इस अभियान में हज़ारों लोग शामिल भी हुए हैं और उन्हीं कहना है कि जो भी हो जाए, हम जान देकर भी इस नदी की रक्षा करेंगे.

ग़ौरतलब है कि 25 वर्ष पूर्व बकुलाही नदी की धारा से छेड़छाड़ की गई थी और यह छेड़छाड़ नैसर्गिक कम राजनीतिक अधिक थी. क़रीब 18 किलोमीटर लंबी इस नदी के किनारे तक़रीबन 25 गांव बसे हैं. इन गांवों में सरायदेवराय, डीहकटरा, छतौना, मनेहू, हिंदूपुर, बाबूपुर, सरायमेदीराय, बरईपुर, मिश्रपुर, सिउरा, हैसी, बुकनापुर, पनई का पूरा, शोभीपुर, जमुआ, वैरीसाल का पुरवा, रामनगर, भटपुरवा, ढेमा गौरा आदि शामिल हैं. इन गांवों से बकुलाही की धारा क्या गई, जैसे उनकी मुस्कराहट ही विलुप्त हो गई. गांवों का जलस्तर धीरे–धीरे पातालमुखी हो गया और फ़सलें सिंचाई के लिए तरसने लगीं. नदी किनारे मौजूद वनक्षेत्रों पर भी तस्करों की नज़र लग गई. इतना ही नहीं, जो क्षेत्र कभी प्रवासी पक्षियों का ठिकाना हुआ करता था, वहां अब प्रवासी पक्षियों की कोई आहट ही महसूस नहीं होती.

बकुलाही नदी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे समाज शेखर ने जब नदी की विलुप्त हुई प्राकृतिक धारा को पुनः बहाल करने का प्रयास शुरु किया, तो एक लाख प्यासे लोगों को मानो संजीवनी मिल गई. नतीजा यह हुआ कि कदम से कदम जुड़ते गए और कारवां बनता गया. पहले जन जागा और फिर जनसमूह, तत्पश्चात जनता जागी और जनसैलाब उमड़ पड़ा. पूरी दुनिया भूजल दिवस मनाने जा रही थी, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भूजल सप्ताह मनाने का संकल्प लिया.

मुख्यमंत्री के आह्वान को अपनी आवाज़ बनाते हुए बकुलाही के सपूतों ने भूजल सप्ताह के पूर्व ही नदी का नजारा बदल डाला. श्रमदान को आंदोलन से जोड़कर बकुलाही नदी पर कच्चा बांध बनाया गया और नदी की धारा को उसके प्राकृतिक मार्ग पर जाने के लिए घुमाया गया.

बकुलाही के ग्रामीणों और समाज शेखर ने 18 किलोमीटर लंबी नदी को पुरानी जलधारा प्रदान कर 25 गांवों में निवास करने वाले हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है. ग़ौरतलब है कि बकुलाही की मूल धारा के बीच गेल इंडिया अवरोध बनी हुई है. गेल इंडिया ने नदी के मार्ग में अपनी पाइप लाइन बिछा रखी है. ग़ौरतलब है कि नदी के बीच से गुजरने वाली पाइप लाइन बिछाने के मानक कुछ अलग होते हैं, लेकिन गेल इंडिया ने पाइप लाइन बिछाने में नियमों की अनदेखी की है, जिससे नदी की जलधारा प्रभावित हुई है.

बकुलाही नदी को जीवनदान देने में लगे लोगों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से काफी अपेक्षाएं हैं. उनके अनुसार, ग्रामीणों की मांग पूरी तरह ज़ायज़ है और इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए. स्थानीय लोगों ने शासन पर आरोप लगाया कि तत्कालीन ज़िलाधिकारी ह्यदेश कुमार ने पक्का चेक डैम बनाकर बकुलाही की दोनों धाराओं को बहाल रखने की दिशा में संबंधित विभागों को सर्वे कर एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके तबादले के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में रख दिया गया. हालांकि बकुलाही नदी को पुनर्जीवित करने के संबंध में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो सक्रियता दिखाई है, उससे नदी किनारे बसे लोगों में इन दिनों खुशी का माहौल है.■

निजी स्कूलों की मनमानी और मूकदर्शक सरकार

देश में निजी स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है. इन विद्यालयों के संचालक अब इतने धनपशु बन चुके हैं कि उनके लिए बच्चों को शिक्षा देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके अभिभावकों से ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना रह गया है. एक कहावत है कि किसी को भी वैद्य और वकील से पाला न पड़े, यही जुमला अब शोषण और दोहन में जुटे निजी स्कूलों पर भी चरितार्थ हो रहा है. आख़िर किसकी शह पर मनमानी कर रहे हैं निजी स्कूल के संचालक और क्यों लाचार दिख रही है सरकार, पढ़िए इस रिपोर्ट में...

सागर सत्यार्थी
feedback@chauthiduniya.com

एजुकेशन हब के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है और वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालय अपनी लाचारी पर खुद आंसू बहा रहा है. नो प्रॉफिट, नो लॉस के वादे के साथ अच्छी तालीम देकर बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए शहर के गली–कूचों में रोज कुकुरमुत्ते की तरह खुलने वाले ये स्कूल अब शिक्षा देने का काम कम और अपना व्यवसाय बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. हर हाल में मनमानी पर उतारू राजधानी के पब्लिक स्कूल लाभ कमाने के लिए वार्षिक–मासिक फीस वसूलने के अलावा, जूते बेचने से लेकर कॉपी–किताब और ड्रेस बेचने का धंधा भी कर रहे हैं. निजी स्कूलों के संचालक मोटी कमाई के फेर में हर साल यूनिफार्म कोड बदलवाने, सप्ताह में चार अलग–अलग तरह की ड्रेस मंगवाने और हर साल कक्षाओं के सिलेबस बदलते रहते हैं. हालांकि निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए आरटीई क़ानून के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त नियम बनाए हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर को व्यवसाय बनाने वाले स्कूल प्रबंधकों को इससे कोई मतलब ही नहीं है. दरअसल, कुछ स्कूलों को आरटीई के नियमों की परवाह ही नहीं है, तो कुछ इसे लागू होने के तीन साल बाद भी खुद को इससे अनभिज्ञ बता रहे हैं. शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वाले पब्लिक स्कूलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते. स्कूलों की यह मनमानी सिर्फ राजधानी देहरादून में ही नहीं चल रही है, बल्कि मसूरी, नैनीताल, रुडकी, हरिद्वार और ऋषिकेश समेत अन्य ज़िलों में बदस्तूर जारी है.

सर्दी की छुट्टियों के बाद उत्तराखंड में स्कूल खुलने लगे हैं. इसी के साथ फीस, यूनिफार्म और किताबें ख़रीदने का दौर शुरू हो गया है. वैसे, वक्त की नजाकत को भांपते हुए सरकार ने भी एक हेल्प लाइन नंबर शुरू कर दिया है. इससे फ़ायदा यह हुआ कि अब इन अभिभावकों की शिकायतें सुनी जा रही हैं. मसूरी के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ रहे बच्चे के फेल होने से परेशान अभिभावक बड़ी साफ़गोई से यह कहते हैं कि किससे और किस लिए शिकायत करें, क्योंकि पिछले साल भी स्कूल प्रशासन ने ऐसा ही सलूक बच्चों के साथ किया था, हमने शिकायत की, मीडिया में भी छपा, लेकिन कार्यवाही के नाम पर किसी ने कुछ भी नहीं किया. उल्टा, शिकायत करने वाले अभिभावक और उनके बच्चे स्कूल प्रबंधक के निशाने पर आ गए, जिसका ख़ामियाजा वे आज तक भुगत रहे हैं. डर के मारे अब कोई भी अभिभावक प्रबंधन की ज्यादतियों के ख़िलाफ़ मुंह खोलने को तैयार नहीं है.

हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई क़ानून लागू कर अपनी पीठ थपथपा रही है. उसके प्रावधानों को लागू करने में उत्तराखंड ने तेज़ी से कदम बढ़ाए थे, लेकिन यहां की स्थिति चौंकाने वाली है. बाल अधिकारों की मुहिम के सामने राज्य की कमज़ोर इच्छाशक्ति और आर्थिक तंगहाली बच्चों के बुनियादी अधिकारों के सामने पहाड़ बनकर खड़ी है. ज़िम्मेदार सरकारी महकमे मनमानी पर उतारू पब्लिक स्कूलों के ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही करने की बजाय हाथ जोड़कर उनके मान मनोव्वल में जुटे हैं, जबकि, सरकार के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल भी बेबस और लाचार हैं. भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज़ से अनुकूल कुछ सरकारी स्कूलों में एक बच्चे के पीछे एक शिक्षक, तीन बच्चों के पीछे दो शिक्षक भी तैनात हैं. खासकर, सरल और सुगम पहुंच वाले मैदानी हिस्सों से इस तरह की ख़बरें आना आम बात है. राजनैतिक संरक्षण के चलते इन शिक्षकों–अधिकारियों को कहने–सुनने वाला कोई नहीं है. राज्य के 3928 सरकारी स्कूलों में आज भी अंधेरा पसरा है, जबकि 1150 स्कूलों में पढ़ रहे सैकड़ों बच्चों के हलक बूंद–बूंद पानी को तरस रहे हैं. प्राकृतिक आपदा के कारण इन स्कूलों की पेयजल लाइनें ध्वस्त हो गई हैं. जिनकी दोबारा मरम्मत नहीं की जा सकी है. हैरानी की बात तो यह है कि राज्य के 521 सरकारी स्कूलों में गर्ल्स टायलेट नहीं हैं, जबकि 1100 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए जगह ही नहीं है. दूर–दराज के कई स्कूल इसलिए भी अंधेरे में हैं, क्योंकि उन गांवों में आज तक लाइट ही नहीं पहुंच पाई है. इन सवालों और समस्याओं के बीच सूबे के शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी बेबस नज़र आ रहे हैं. उनका दावा है कि आरटीई एक्ट को प्रदेश में बेहतर ढंग से लागू किया गया है. हालांकि, आर्थिक तंगी के कारण कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा.

ग़ौरतलब है कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के बजट में भारी कटौती की है. इसी के मद्देनज़र इस बार राज्य की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए 847.79 करोड़ रुपये के बजट में से केवल 367.02 करोड़ रुपये की मंजूरी केंद्र ने दी है. ऐसे में, शिक्षा का अधिकार क़ानून के तहत नए विद्यालयों की स्थापना से लेकर शिक्षकों की भर्ती बुरी तरह प्रभावित है. शिक्षक स्कूल में पढ़ाने की बजाय अपनी मांगों के लिए आए दिन राजधानी पहुंचकर धरना–प्रदर्शनों में व्यस्त हैं और नेता–अफसर उनके मान मनोव्वल में लगे हैं. बहरहाल, प्रदेश में एक तरफ निजी स्कूलों की मनमानी और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की लाचारी के आगे शिक्षा की इन इबादतगाहों में बचपन सजने–संवरने की बजाय कुम्हलाने को मजबूर है. ■

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120–6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366